एसटी.स्टीफन कॉलेज ई. टी. सी. ईटीसी।

वी.

दिल्ली विश्वविद्यालय ई. टी. सी. ईटीसी।

6 दिसंबर, 1991

(

[एम. एच. कनिया, के. जगन्नाथ शेट्टी, एन. एम. कासलीवाल,

एम. फातिमा बीवी और योगेश्वर दिवस, जे. जे.]

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 30 (1)-अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान

शिक्षा संवैधानिक सुरक्षा-उद्देश्य और उद्देश्य।

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 30 (1), 29 (1), 29 (2) अल्पसंख्यक शिक्षा।ग

राष्ट्रीय संस्थान शिक्षा में धार्मिक स्वायत्तता और अनुच्छेद भेदभाव के तहत निर्माण अधिकार।

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 30 (1), 29,14,15-अल्पसंख्यक शिक्षा

राष्ट्रीय संस्थान-धर्म के आधार पर प्रवेश-धर्म की वैधता।

डी.

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 30 (1)-अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान

- आवश्यकताओं के तहत संरक्षण का दावा करने वाली शिक्षा।

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 30,29-सं.स्टीफन कॉलेज,

चाहे वह धार्मिक अल्पसंख्यक संस्था हो।

ई.

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 30 (1)-"मामलों का प्रबंधन"

संस्थान का "," स्थापना "," प्रशासन "-निर्माण-अल्पसंख्यक शिक्षा राष्ट्रीय संस्थान-प्रशासन का अधिकार-दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, क़ानून, विनियम/राज्य नियंत्रण की प्रकृति और दायरा-का प्रभाव और वैधता।एफ भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 30 (1) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान-प्रशासन का अधिकार-एक कॉलेज का प्रवेश कार्यक्रम-छात्रों का चयन-विश्वविद्यालय के विनियम/निर्देश।

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 30 (1)-अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान प्रवेश चयन साक्षात्कार-अपनाई गई प्रक्रिया का उद्देश्य, जी चाहे उचित हो।

3

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 30 (1), 30 (2), 337-अल्पसंख्यक शिक्षा

राष्ट्रीय संस्था राज्य सहायता-प्रशासन मामले में राज्य नियंत्रण का उद्देश्य और दायरा।

एच.

121

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

टी 122

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14,15,30,29-अल्पसंख्यक शिक्षा

क.

(

राष्ट्रीय संस्थान सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रवेश आरक्षण और समानता अवधारणा निर्माण।

क़ानूनों की व्याख्या-निर्माण के प्रकार-भारत का संविधान, 1950 अनुच्छेद 30 (1) और 29 (2) निर्माण की विधि।

W.P.NO.1868/1980

याचिकाकर्ता-महाविद्यालय प्रतिवादी आर दिल्ली विश्वविद्यालय का एक घटक महाविद्यालय था।यह विश्वविद्यालय से भी संबद्ध था। एक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित कॉलेज एक सहायता प्राप्त शैक्षणिक सी संस्थान था।

महाविद्यालय ने B.A./B.Sc (ऑनर्स) में तीन साल का डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान किया।

बी. ए. (उत्तीर्ण) और बी. एससी. (सामान्य) और एम. ए. और एम. एससी. में दो साल का स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम।

आगे बढ़ें

डी.

महाविद्यालय का अपना प्रवेश कार्यक्रम था।ईसाई धर्म

प्रवेश में डेंट को प्राथमिकता दी गई थी।25.5.1980 पर, कॉलेज ने शैक्षणिक वर्ष 1980-81 के लिए "प्रवेश विवरण पत्रिका" प्रकाशित की।इसमें कहा गया था कि प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20.6.1980 होगी।

ई.

और यह कि छात्रों के अंतिम चयन से पहले एक साक्षात्कार होगा।5.6.1980 पर, विश्वविद्यालय ने सभी संबद्ध कॉलेजों को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें कॉलेजों में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को अधिसूचित किया गया।

30.6.1980 और उसमें प्रवेश का कार्यक्रम भी चरणबद्ध किया गया था।

च

9.6.1980 पर, विश्वविद्यालय ने एक अन्य परिपत्र में कुछ प्रावधान किए हैं

प्रवेश के लिए दिशानिर्देश, बी. ए. में प्रवेश। (पास)/बी. ए.व्यावसायिक (अध्ययन) पाठ्यक्रम योग्यता परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत की योग्यता पर आधारित होने चाहिए; कि B.Com में प्रवेश।(पास), बी. ए. (ऑनर्स) और B.Com (ऑनर्स) पाठ्यक्रम भी अंकों के आधार पर होने चाहिए। कि अगर कोई कॉलेज अंकों को महत्व देने का प्रस्ताव करता है

जी.

योग्यता परीक्षा के कुल अंकों के अलावा एक या अधिक व्यक्तिगत विषयों में प्राप्त, इसे कॉलेज प्रॉस्पेक्टस या नोटिस बोर्ड के माध्यम से पहले से अधिसूचित किया जाना चाहिए।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने विश्वविद्यालय से शिकायत की

एच एस टी।स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय 123

कि याचिकाकर्ता-कॉलेज विश्वविद्यालय के कानूनों और अध्यादेशों का उल्लंघन कर रहा था

3

नान्स, क्योंकि इसने आवेदनों की प्राप्ति के लिए अपनी समय सारिणी निर्धारित की थी

प्रवेश से पहले प्रवेश और साक्षात्कार आयोजित करना।

विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता-कॉलेज से अनुरोध किया कि वे

विश्वविद्यालय अनुसूची अपने परिपत्र दिनांक 5.6.1980 के अनुसार।

याचिकाकर्ता-महाविद्यालय ने विश्वविद्यालय को सूचित किया कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

प्रवेश कार्यक्रम बनाया जा सकता है।

जब विश्वविद्यालय ने अपने दिनांक 7/9.6.1980 के पत्र में याचिकाकर्ता-महाविद्यालय को प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय की तारीखों के लिए निर्धारित तिथियों का पालन करने के लिए कहा, तो याचिकाकर्ता-महाविद्यालय ने जवाब दिया कि विश्वविद्यालय के परिपत्रों का पालन करना संभव नहीं है।लेकिन इसने विश्वविद्यालय को आश्वासन दिया कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि से पहले कोई प्रवेश सूची नहीं रखी जाएगी।

विश्वविद्यालय।

16.6.1980 पर एक छात्र ने याचिकाकर्ता-कॉलेज में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें डी.

महाविद्यालय का प्रवेश कार्यक्रम।

30.6.1980 पर उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि जैसा कि कॉलेज ने नहीं किया था

कॉलेज द्वारा 5.6.1980 और 9.6.1980 तक प्रवेश के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय के परिपत्रों की वैधता को चुनौती दी गई।(ई रिट याचिका T.C.No में विषय वस्तु थी। इस न्यायालय के समक्ष 1980 का 3)।

याचिकाकर्ता-कॉलेज ने इस न्यायालय का रुख किया (डब्ल्यू. पी. दायर करके। (सिविल) सं. 1868) कला के तहत।32 संविधान में कहा गया है कि कॉलेज एक धार्मिक अल्पसंख्यक संचालित संस्थान था; कि हालांकि यह विश्वविद्यालय का एक घटक कॉलेज एफ था और प्रतिवादी-विश्वविद्यालय से संबद्ध था, लेकिन यह एक धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं था।

जे

महाविद्यालय ने कहा कि महाविद्यालय की शुरुआत के बाद से यह अंतर्निहित प्रबंधकीय शक्तियों का प्रयोग कर रहा था, जैसे कि प्रवेश के लिए उचित तिथियां तय करना और पूरे देश में उम्मीदवारों का साक्षात्कार आयोजित करना, जिन पर प्रतिवादी-विश्वविद्यालय द्वारा सवाल नहीं उठाए गए थे या हस्तक्षेप नहीं किया गया था; कि विश्वविद्यालय के परिपत्र याचिकाकर्ता-महाविद्यालय के जी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेंगे, क्योंकि प्रवेश अनुसूची का निर्धारण प्रत्यक्ष प्रबंधकीय था; कि प्रबंधन के किसी भी हिस्से को अतिक्रमण के बिना दूसरे निकाय में नहीं लिया जा सकता है और निवेश नहीं किया जा सकता है।

गारंटीकृत अधिकार पर; कि अंकों के आधार पर प्रवेश के लिए छात्रों का चयन अनुचित होगा और संविधान के अनुच्छेद 30 और एच 124 के तहत गारंटीकृत कॉलेज के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए कि विश्वविद्यालय के परिपत्र दिनांकित 5.6.1980 और 9.6.1980 घोषित किए जाने चाहिए

आई.

कॉलेज की अल्पसंख्यक स्थिति को देखते हुए इसे रद्द कर दें।इस रिट याचिका में, (1980 का डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 1868), दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ एक मध्यस्थ बन गया।

डब्ल्यू. पी. सं.13213-14 / 84

कला के तहत।32 संविधान के अनुसार, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ और एक अन्य ने प्रवेश वर्ष के संबंध में दो रिट याचिकाएं दायर कीं, जिसमें इस न्यायालय से कॉलेज को प्रवेश सी आदि के संबंध में सभी विश्वविद्यालय नीतियों, नियमों, विनियम अध्यादेशों का पालन करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। उन्होंने इस अदालत से कॉलेज को ईसाई छात्रों के पक्ष में वरीयता देने से रोकने का भी अनुरोध किया।

याचिकाकर्ता-छात्र संघ ने तर्क दिया कि कॉलेज को किसी भी अदालत द्वारा अल्पसंख्यक कॉलेज घोषित नहीं किया गया था और न ही इसे विश्वविद्यालय द्वारा अल्पसंख्यक कॉलेज के रूप में मान्यता दी गई थी; कि कॉलेज को धर्म के आधार पर छात्रों के साथ भेदभाव करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि कॉलेज को सरकार से भरण-पोषण अनुदान मिल रहा था; और यह कि केवल धर्म के आधार पर कॉलेज में प्रवेश के लिए छात्रों के साथ भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 29 (2) के प्रावधानों के विपरीत था।

विश्वविद्यालय ने तर्क दिया कि प्रत्येक कॉलेज को विश्वविद्यालय के ई क़ानूनों, अध्यादेशों और विनियमों का पालन करना चाहिए; कि कॉलेज को विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना आवश्यक है।

छात्रों के प्रवेश के संबंध में; कि अध्यादेश XVIII के खंड 6-ए (5) के तहत; कर्मचारी परिषद को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नीति के ढांचे के भीतर प्रवेश नीति के निर्माण के संबंध में सिफारिशें करनी थीं; कि कॉलेज अपना प्रवेश स्वयं निर्धारित नहीं कर सकता था।

च

नीति ताकि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नीति के साथ टकराव में हो; कि चूंकि कॉलेज राज्य निधि से सहायता प्राप्त कर रहा था, इसलिए वह प्रवेश के मामले में आधार या धर्म या भाषा पर भेदभाव करने का हकदार नहीं था, जो संविधान के अनुच्छेद 29 (2) के अधिदेश के विपरीत था; कि विश्वविद्यालय के परिपत्र किसी भी तरह से निकाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते थे। महाविद्यालय; कि महाविद्यालय अन्य सभी महाविद्यालयों की तरह विश्वविद्यालय के परिपत्रों का पालन करने के लिए बाध्य था, जिसमें प्रवेश के मामले में निर्देश शामिल थे; और यह कि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत महाविद्यालय का मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं हुआ था।

4

सी. ए. सं.1830-41 1989 का; C.A.No। 1989 का 1786 और C.A.No। 2829 का

एच.

1989 .

एसटी.स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय 125

1

जिन छात्रों को इलाहाबाद एग्री-एक सांस्कृतिक संस्थान द्वारा प्रवेश से वंचित कर दिया गया था, जिसे क्रिस तियान धार्मिक अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किया गया था, उन्होंने कला के तहत रिट याचिकाएं दायर कीं।226 चर्च प्रायोजित के आरक्षण और प्रवेश को चुनौती देने वाले संविधान का

ईसाई छात्र।

उच्च न्यायालय ने यह घोषणा करते हुए कि क्रिस-बियान छात्रों के लिए आरक्षण की नीति संविधान के अनुच्छेद 29 (2) के तहत नागरिकों को दी गई समानता की गारंटी के विपरीत है, रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया।संस्थान ने संविधान के अनुच्छेद 133 (1) (ए) के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए सी. ए. संख्या दायर की।1831-41 1989 का उच्च न्यायालय के एस को चुनौती देना

निर्णय लेते हैं।

C.A.Nos।1786/89 और 2829/89 उसी फैसले के खिलाफ दायर किए गए थे

पीड़ित छात्रों द्वारा उच्च न्यायालय।

इन प्रश्नों पर, (1) क्या सेंट स्टीफन कॉलेज एक अल्पसंख्यक संचालित संस्थान था?(ii) क्या सेंट स्टीफन कॉलेज एक अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में विश्वविद्यालय के परिपत्रों दिनांक 5.6.1980 और 9.6.1980 से बंधा था,

डी. आई.

यह निर्देश देते हुए कि कॉलेज को योग्यता प्राप्त करने वाले परीक्षा देने वाले देशों में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत की योग्यता के आधार पर छात्रों को प्रवेश देना चाहिए?और (iii) क्या आई. डी. 1 का महाविद्यालय और इलाहाबाद कृषि सांस्कृतिक संस्थान अपने समुदाय के छात्रों को वरीयता देने या सीटें आरक्षित करने के हकदार थे, और क्या ऐसी वरीयता या आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 29 (2) के तहत अमान्य होगा?, यह न्यायालय, डब्ल्यू. पी. को अनुमति देता है। (ग) महाविद्यालय द्वारा दायर सं. 1868/1980 और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपील, और W.P.Nos को खारिज करते हुए। 13213-14 1984 और T.C.No। 3/1980,

ई.

एफ हेल्डः(M.H.Kania, के. जगन्नाथ शेट्टी, एम. फातिमा बीवी और योगेश्वर दयाल, जेजे।बहुमत-पर के. जगन्नाथ शेट्टी, जे.)

1.01 भारत एक बहु-सांस्कृतिक और बहु-धार्मिक समाज है।यह विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ एक असाधारण बहुलवादी और जटिल समाज है।इसके अलावा, भाषाई आकांक्षाएं और जातिगत विचार भी हैं।अल्पसंख्यक समूह में ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो चाहते हैं

बहुसंख्यक में आत्मसात करें, लेकिन समूह का स्वयं गैर-आत्मसात के लिए सामूहिक हित है।यह एक समुदाय के रूप में संरक्षण और संवर्धन में रुचि रखता है।यह मुख्य कारण प्रतीत होता है जिसके लिए अनुच्छेद 30 (1) को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था।[178 सी-ई]

1.02 अल्पसंख्यकों के साथ धार्मिक तटस्थ तरीके से व्यवहार नहीं किया जा सकता है।

क.

उनके द्वारा स्थापित और प्रशासित शैक्षणिक संस्थान।

स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 30 (1) का उद्देश्य यह नहीं था।अनुच्छेद 30 (1) को केवल धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों के लिए एक उचित सौदा सुनिश्चित करने के लिए शामिल किया गया था।फ्रेमरों द्वारा बहुत अधिक स्वतंत्रता के बाद उन्हें एक मौलिक अधिकार के रूप में इसकी गारंटी दी गई थी।इसे संकीर्ण न्यायिक बी व्याख्या या कर्कश पांडित्य द्वारा रद्द नहीं किया जाना चाहिए।एक व्यापक दृष्टिकोण और राजनेताओं जैसी दृष्टि होनी चाहिए।कैथोलिक दृष्टिकोण जिसके कारण अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित प्रावधानों का मसौदा तैयार किया गया, उसे शून्य नहीं माना जाना चाहिए।यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अल्पसंख्यकों को अपनापन और सुरक्षा की भावना से वंचित करने के लिए कुछ भी नहीं किया जाए।[180 डी-ई]

एस.

1.03 अल्पसंख्यकों को अपने उम्मीदवारों को स्वीकार करने का अधिकार है

अपने संस्थानों के अल्पसंख्यक चरित्र को बनाए रखें।यह एक आवश्यक सहवर्ती अधिकार है जो स्थापित करने और प्रशासित करने के अधिकार से आता है।

अनुच्छेद 30 (1) में शैक्षणिक संस्थान।अल्पसंख्यक समुदायों में माता-पिता के लिए भी एक संबंधित अधिकार है।माता-पिता को अपने बच्चों को उन संस्थानों में शिक्षित करने का अधिकार है जो उनके अपने धर्म के अनुकूल वातावरण हों।[181 सी-डी]

2.01 .शिक्षा में संवैधानिक अवधारणा या धार्मिक स्वायत्तता

अनुच्छेद 30 (1) को अनुच्छेद 29 (2) के तहत संवैधानिक गारंटी के साथ संतुलित करना होगा।दोनों लेख एक ही क्षेत्र में काम करते हैं, अर्थात् शैक्षणिक संस्थान।अनुच्छेद 30 (1) के तहत अल्पसंख्यकों को गारंटीकृत अधिकार

ई.

अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है, और इसकी व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि यह अनुच्छेद 29 (2) में दिए गए अधिकार को नष्ट न करे।[173 एफ-जी]

1

2.02 .अनुच्छेद 29 (1) के तहत नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 (1) के तहत, अल्पसंख्यकों-धार्मिक या भाषाई-को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है।शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्यों तक ही सीमित नहीं है।अनुच्छेद 30 (1) में अधिकार व्यापक आयाम के हैं।अनुच्छेद 30 (1) की चौड़ाई को उन विचारों से कम नहीं किया जा सकता है जिन पर अनुच्छेद 29 (1) आधारित है।अनुच्छेद 30 (1) में "उनकी पसंद के" शब्द अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक संस्थानों के प्रकार का चयन करने के लिए विशाल विकल्प छोड़ते हैं।

च

जी.

जिसे वे स्थापित करना चाहते हैं।वे अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के लिए या सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने के लिए या दोनों उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं।[175 एच-176 सी]

एच एस टी।स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय 127

2.03 .सामूहिक अल्पसंख्यक अधिकार को कार्यात्मक ए बनाने की आवश्यकता है और इसे बेकार संख्या में नहीं घटाया जाना चाहिए।अनुच्छेद 30 (1) के तहत एक सार्थक अधिकार को आकार दिया जाना चाहिए, ढाला जाना चाहिए और बनाया जाना चाहिए, साथ ही साथ अनुच्छेद 29 (2) के तहत व्यक्तियों के अधिकार की पुष्टि की जानी चाहिए।दोनों प्रतिस्पर्धी अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है।यह आवश्यक है कि

अनुच्छेद 29 (2) और अनुच्छेद 30 (ए) के बीच इन अनुच्छेदों के अक्षर और भावना के बीच, अतीत की परंपराओं और वर्तमान बी की सुविधा के बीच, समाज की स्थिरता की आवश्यकता और परिवर्तन की आवश्यकता के बीच मध्यस्थता करें।

[181 ई-एफ]

3.01 .अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के लिए संस्थागत वरीयता के आधार पर

धर्म स्पष्ट रूप से निषिद्ध पर एक संस्थागत भेदभाव है।

धर्म का आधार।यह केवल धर्म के आधार पर गैर-अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों को कलंकित या अलग करने के लिए काम करता है।यदि कोई शैक्षणिक संस्थान एक उम्मीदवार को "हां" कहता है लेकिन धर्म के आधार पर दूसरे उम्मीदवार को "नहीं" कहता है, तो यह जमीनी स्तर पर भेदभाव के बराबर है।

धर्म का।अनुच्छेद 29 (2) का अधिदेश यह है कि ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा।[176 ई-एफ]

:

डी.

3.02 .अनुच्छेद 30 (1) में दिए गए संस्थान के चयन का मतलब यह नहीं है कि अल्पसंख्यक अपने समुदाय के लोगों के लाभ के लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं।वास्तव में वे ऐसा नहीं कर सकते।मिनोरी संबंध केवल अपने लाभ के लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित नहीं कर सकते हैं।

समुदाय।यदि ऐसा उद्देश्य होता तो अनुच्छेद 30 (1) अलग होता।

शब्दबद्ध और इसमें "अपने समुदाय के लिए" शब्द शामिल होंगे।इस तरह के शब्दों के अभाव में अनुच्छेद का यह अर्थ लगाना कानूनी रूप से अस्वीकार्य है कि यह अल्पसंख्यकों को अपने स्वयं के लाभ के लिए शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है।[176 जी-177 ए]

3.03 .व्यवहार में भी, इस तरह के दावों को विनाशकारी शत्रुता के रूप में देखे जाने की संभावना है।अपेक्षाकृत एक सजातीय समाज होना निर्णायक नहीं हो सकता है।यह धार्मिक कट्टरता की ओर ले जा सकता है जो मानव जाति के लिए अभिशाप है। धर्मनिरपेक्ष चरित्र वाले राष्ट्र निर्माण में सांप्रदायिक स्कूल या कॉलेज; सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने के लिए अलग-अलग संकाय या विश्वविद्यालय अवांछनीय हैं और जो धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को कमजोर कर सकते हैं।वे संविधान में अंतर्निहित धर्मनिरपेक्षता और समानता जी की केंद्रीय अवधारणा के साथ असंगत होंगे।प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान चाहे जो भी हो

एफ.

च

जिस समुदाय से यह संबंधित है, वह एक 'पिघलने वाला बर्तन' है।हमारे राष्ट्रीय जीवन में, छात्र और शिक्षक महत्वपूर्ण घटक हैं। यही वह जगह है जहाँ वे दूसरों की संस्कृतियों और मान्यताओं के प्रति सम्मान और सहिष्णुता विकसित करते हैं।इसलिए यह आवश्यक है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न समुदायों के छात्रों का उचित मिश्रण होना चाहिए।[177 बी-सी]

एच 128

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3.04 द्वारा बनाए गए या सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच

क.

राज्य निधि अनुच्छेद 29 (2) की विशेष चिंता है।यह किसी व्यक्ति के इस अधिकार को मान्यता देता है कि उसके साथ केवल नागरिक के विशेष धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है या राज्य द्वारा बनाए गए शैक्षणिक संस्थानों में या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने के लिए किसी विशेष भाषा का होना पूरी तरह से निषिद्ध है।यह अल्पसंख्यकों के साथ-साथ बी गैर-अल्पसंख्यकों पर भी लागू होता है।जब किसी नागरिक का धर्म, नस्ल, जाति, भाषा अन्य योग्यताओं के बराबर होने पर वरीयता या भाषा का आधार नहीं होगा।

अक्षमता।इसी तरह, अनुच्छेद 29 (2) में उपयोग किए गए "उनमें से कोई भी" शब्दों का उद्देश्य इस बात पर और जोर देना है कि अनुच्छेद में उल्लिखित किसी भी आधार को भेदभाव का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता है।[177 एफ-एच)

एस.

3.05 .तथ्य यह है कि अनुच्छेद 29 (2) अल्पसंख्यकों के साथ-साथ गैर-अल्पसंख्यकों पर भी लागू होता है

अल्पसंख्यकों का मतलब यह नहीं है कि इसका उद्देश्य विशेष अधिकार को समाप्त करना था

अनुच्छेद 30 (1) में अल्पसंख्यकों को गारंटी दी गई है।अनुच्छेद 29 (2) गैर-आपराधिकता से संबंधित है और यह केवल व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है।गैर-भेदभाव द्वारा सामान्य समानता अल्पसंख्यकों का एकमात्र लक्ष्य नहीं है।बहुसंख्यक शासन के तहत अल्पसंख्यक अधिकारों का तात्पर्य गैर-भेदभाव से अधिक है और वास्तव में, यह गैर-भेदभाव के साथ शुरू होता है।हितों और संस्थानों की सुरक्षा और अवसरों की उन्नति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।विभेदक व्यवहार जो उन्हें बहुमत से अलग करता है, उनकी बुनियादी विशेषताओं को संरक्षित करने के लिए आवश्यक है।[178 ए-बी]

3.06 .अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान इसके हकदार हैं -

ई.

अपने समुदाय के उम्मीदवारों को संस्थान के विषय के अल्पसंख्यक चरित्र को बनाए रखने के लिए पसंद करते हैं, निश्चित रूप से, विश्वविद्यालय मानक के अनुरूप।जिस क्षेत्र में संस्थान सेवा करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में समुदाय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य इस श्रेणी में प्रवेश को विनियमित कर सकता है।लेकिन किसी भी मामले में ऐसा प्रवेश वार्षिक प्रवेश के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।अल्पसंख्यक संस्थान उपलब्ध कराएंगे

च

अल्पसंख्यक समुदाय के अलावा अन्य समुदायों के सदस्यों के लिए वार्षिक प्रवेश का कम से कम पचास प्रतिशत।अन्य समुदाय के उम्मीदवारों का प्रवेश विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर किया जाएगा।[183 डी-ई] 4.01।संविधान के अनुच्छेद 30 (1) जी के संरक्षण का दावा करने के लिए सक्षम अल्पसंख्यक, और उस कारण से स्थापना का विशेषाधिकार और

अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों को बनाए रखने के लिए, भारत में रहने वाले व्यक्तियों का एक अल्पसंख्यक होना चाहिए।उन्होंने एक अच्छी तरह से परिभाषित धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक का गठन किया होगा।यह विदेशी असैन्य या संस्था के अधिकारों की परिकल्पना नहीं करता है, हालांकि, उनके उद्देश्य प्रशंसनीय हो सकते हैं।संविधान के बाद, अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक का मतलब अनिवार्य रूप से वे एच होना चाहिए जो भारत के नागरिकों का एक विशिष्ट और पहचान योग्य समूह बनाते हैं।चाहे वह एसटी हो।

स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय 129

1

यदि "पुराना सामान" या "नया उत्पाद" है, तो संस्थान का उद्देश्य ए वास्तविक होना चाहिए, न कि उपकरण।साधनों के बीच संबंध होना चाहिए

नियोजित और वांछित उद्देश्य।[156 डी-एफ]

4.02 .शैक्षणिक संस्थान को धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ पहचान करने में सक्षम बनाने के लिए कुछ सकारात्मक सूचकांक मौजूद होना चाहिए।लेख

30 (1) यह केवल धार्मिक और भाषाई बी अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए एक सुरक्षात्मक उपाय है और यह पूरी तरह से स्पष्ट करना आवश्यक है कि कोई भी अयोग्य या छिपी हुई संस्था संवैधानिक संरक्षण से दूर नहीं होनी चाहिए।[156 एफ]

5. महाविद्यालय का गठन एक स्वायत्त और स्वायत्त संस्थान के रूप में किया गया है।इसने अपना शासन चुनने के अधिकार को सुरक्षित रखा है?ग

}

निकाय, और अपने स्वयं के प्राचार्य का चयन और नियुक्ति करें, दोनों का संस्थान के अल्पसंख्यक चरित्र को बनाए रखने के लिए एक बड़ा योगदान कारक है।यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि कॉलेज के संविधान को दिल्ली प्रांत के संयुक्त स्टॉक कंपनियों के पंजीयक के साथ-साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में भी विधिवत पंजीकृत किया गया है।विश्वविद्यालय ने किसी भी स्तर पर महाविद्यालय के संविधान के किसी भी प्रावधान के बारे में कोई आपत्ति नहीं जताई है।इन तथ्यों और परिस्थितियों से यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि St.Stephen के कॉलेज की स्थापना और प्रशासन एक अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा किया गया था, अर्थात।, ईसाई समुदाय जो निर्विवाद रूप से भारत के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में एक धार्मिक अल्पसंख्यक है जहां कॉलेज स्थित है। [163 बी-डी]

ई.

6.01 .धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है।अनुच्छेद 30 (1) के तहत अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासन का अर्थ है 'संस्थान के मामलों का प्रबंधन'।यह मानव आंदोलन नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए ताकि उनके नामांकित व्यक्तियों के संस्थापक संस्थान को अपने विचार के अनुसार ढाल सकें और उनके विचारों के अनुसार कि सामान्य रूप से समुदाय और विशेष रूप से संस्थान के हितों की सर्वोत्तम सेवा कैसे की जाएगी।लेकिन शिक्षा के मानक प्रबंधन का हिस्सा नहीं हैं।मानक राजनीतिक निकाय से संबंधित है, और विचार या देश और उसके लोगों की प्रगति द्वारा शासित होता है।इस तरह के नियम सीधे प्रबंधन जी पर लागू नहीं होते हैं

सी.

हालाँकि वे अप्रत्यक्ष रूप से इसे प्रभावित कर सकते हैं।इसलिए, राज्य को शिक्षा के स्तर और संबद्ध मामलों को विनियमित करने का अधिकार है।अल्पसंख्यक संस्थानों को शैक्षणिक संस्थानों के उत्कृष्टता मानकों से नीचे आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।वे इसका पालन करने से इनकार नहीं कर सकते

प्रबंधन के अनन्य अधिकार की आड़ में शिक्षा का सामान्य स्वरूप

मन में।जबकि प्रबंधन उन पर छोड़ दिया जाना चाहिए, वे एच को दूसरों के साथ कदम रखने के लिए मजबूर कर सकते हैं। [165 एच-166 सी]

6.02 .अनुच्छेद 30 (1) में प्रयुक्त शब्द "स्थापित" और "प्रशासित" हैं।

क.

इन्हें संयोजित रूप से पढ़ा जाना चाहिए।अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा शैक्षणिक संस्थान का प्रशासन करने का दावा किया गया अधिकार संस्थान की स्थापना के प्रमाण पर निर्भर करता है।संस्थान की स्थापना का प्रमाण, इस प्रकार प्रशासन के अधिकार का दावा करने के लिए एक शर्त पूर्ववर्ती है

संस्था।[156 सी]

?

6.03 .राज्य या राज्य का कोई भी साधन अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा सामूहिक संबद्धता द्वारा स्थापित संस्थान के चरित्र से वंचित नहीं कर सकता है क्योंकि अनुच्छेद 30 (1) अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का विशेष अधिकार है।अल्पसंख्यक संस्थान की एक अलग पहचान है और इस तरह की सी पहचान को जारी रखने के साथ प्रशासन के अधिकार को दंडात्मक कार्रवाई से वंचित नहीं किया जा सकता है।इस तरह की कोई भी दंडात्मक कार्रवाई संवैधानिक गारंटी के विपरीत होने के कारण अमान्य होगी।प्रशासन का अधिकार संस्था के कार्यों के संचालन और प्रबंधन का अधिकार है।इस अधिकार

का प्रयोग व्यक्तियों के एक समूह द्वारा किया जाता है जिसमें संस्थापकों को विश्वास और विश्वास होता है।यदि अधिकार को मान्यता और बनाए रखना है तो संस्थान के ऐसे प्रबंधन निकाय को विस्थापित या पुनर्गठित नहीं किया जा सकता है।डी हालांकि, उचित विनियम अनुमत हैं लेकिन विनियम नियामक प्रकृति के होने चाहिए और अनुच्छेद 30 (1) के तहत गारंटीकृत अधिकार के संक्षिप्त होने के नहीं होने चाहिए।[160 एच-161 बी] *

च

6.04 .यद्यपि अनुच्छेद 30 (1) संविधान के भाग III में अन्य मौलिक अधिकारों के स्पष्ट रूप से विपरीत है, यह

ई.

इसे शिक्षा, शिक्षा के राष्ट्रीय मानकों और संबद्ध मामलों को विनियमित करने की राज्य की शक्ति के अधीन पढ़ा जाना चाहिए। [166 ई]

6.05 .प्रशासन के अधिकार में अवैध प्रशासन का अधिकार शामिल नहीं है।नियंत्रक प्राधिकारी होने के नाते राज्य को सभी शैक्षणिक मामलों को विनियमित करने का अधिकार और कर्तव्य है।नियम जो हितों की पूर्ति करेंगे

च

छात्रों और शिक्षकों के लिए, और संबद्ध संस्थानों के बीच शिक्षा के मानकों में एकरूपता बनाए रखी जा सकती है।अल्पसंख्यक संस्थान इस तरह के सामान्य पैटर्न और मानक के खिलाफ या कानून और व्यवस्था, स्वास्थ्य, श्रम संबंध, सामाजिक कल्याण कानून, अनुबंध, अपकृत्य आदि से संबंधित सामान्य कानूनों के खिलाफ प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकते हैं जो सभी समुदायों पर लागू होते हैं।जब तक शैक्षणिक संस्थान के प्रबंधन के लिए अल्पसंख्यकों के मूल अधिकार को छीन नहीं लिया जाता है, तब तक राज्य नियामक कानून बनाने में सक्षम है।हालाँकि, विनियमों का प्रभाव अल्पसंख्यकों के अपने बच्चों को अपने स्वयं के संस्थान में शिक्षित करने के अधिकार से वंचित करने का नहीं होगा।यह एक विशेषाधिकार है जो अनुच्छेद 30 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार में निहित है।[168 एफ-एच]

एच.

!

एसटी.स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय 131

6.06 .हालाँकि, अनुच्छेद 30 (1) ए में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को निर्धारित करने वाले कानून मनमाने, व्यक्तिगत या अनुचित नहीं होने चाहिए; उनका उद्देश्य और नियोजित साधनों के बीच एक उचित संबंध होना चाहिए।व्यक्तिगत अधिकारों को अनिवार्य रूप से प्रतिस्पर्धी अल्पसंख्यक हितों के साथ संतुलित करना होगा।[183 ए]

6.07 .दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम में कॉलेज के प्रबंधन को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में कॉलेज का प्रशासन करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने से रोकने वाली शक्तियों के साथ कोई प्रावधान नहीं है।[161 सी] 7.01।कॉलेज का प्रवेश कार्यक्रम संस्थान की उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है और यह प्रशासन का हिस्सा है जिसे कॉलेज संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत अल्पसंख्यक सी संस्थान के रूप में रखने का हकदार है।विश्वविद्यालय कॉलेज को अपने प्रवेश कार्यक्रम को समाप्त करने का निर्देश नहीं दे सकता है।

महाविद्यालय के कुप्रशासन के प्रमाण का अभाव।[163 जी-एच] 7.02।प्रवेश के लिए छात्रों का चयन करने का अधिकार प्रशासन का एक हिस्सा है।यह वास्तव में प्रशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है।इस शक्ति डी को भी विनियमित किया जा सकता है लेकिन विनियमन किसी भी अन्य विनियमन की तरह उचित होना चाहिए।यह अल्पसंख्यक संस्थान के कल्याण के लिए या इसका सहारा लेने वालों की बेहतरी के लिए अनुकूल होना चाहिए।[169 ए-बी] 7.03।तत्काल मामले में, ई योग्यता परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के समान आधार पर छात्रों का चयन करने के लिए विश्वविद्यालय के विवादित निर्देश भी ईसाई समुदाय से संबंधित छात्रों को प्रवेश देने के लिए St.Stephen के कॉलेज के अधिकार से वंचित कर देंगे।कॉलेज का अनुभव रहा है कि जब तक ईसाई छात्रों को कुछ रियायत नहीं दी जाती है, तब तक उनके पास कॉलेज में प्रवेश करने का कोई मौका नहीं होगा।यदि उन्हें अन्य समुदायों से संबंधित छात्रों की व्यापकता के साथ प्रतियोगिता में डाला जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के लिए एफ विचार क्षेत्र के भीतर भी नहीं लाया जा सकता है।कुछ हद तक रियायत देने के बाद भी, अल्पसंख्यक आवेदकों की एक छोटी संख्या को ही प्रवेश मिलेगा।[170 सी-डी]

8.01 .साक्षात्कार का उद्देश्य योग्यता परीक्षाओं में आवेदकों की योग्यता का पुनर्मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन करना नहीं है।योग्यता परीक्षाओं में ठीक किए गए अंक से जी वास्तव में चयन के लिए प्रासंगिक हैं और साक्षात्कार केवल पूरक परीक्षा है।कॉलेज विभिन्न विषयों में अंकों का अलग-अलग कट ऑफ प्रतिशत तय करता है।उम्मीदवारों को 1 के अनुपात में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता हैः4 या 1:5 यह अध्ययन के पाठ्यक्रमों के चयन के लिए उम्मीदवारों की पसंद पर निर्भर करता है।साक्षात्कार उच्च सत्यनिष्ठा, क्षमता और योग्यता वाले पुरुषों द्वारा आयोजित किया जाता है।ये वे लोग हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं 132

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए और छात्र।साक्षात्कार के दौरान, विषय के बारे में उम्मीदवार के ज्ञान और वर्तमान समस्याओं के बारे में उनकी सामान्य जागरूकता का परीक्षण करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं।छात्र को आवेदन पत्र में अपनी रुचि, शौक, मूल्य, कैरियर योजना आदि प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता होती है। साक्षात्कार समिति के प्रत्येक सदस्य उम्मीदवारों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं और

साक्षात्कार समिति के सभी सदस्यों द्वारा व्यक्त बी राय को ध्यान में रखते हुए अध्ययन के प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए चयन किया जाता है।सर्वसम्मति से उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार की जाती है।इस प्रकार चयन उम्मीदवार के शैक्षणिक रिकॉर्ड और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर उसकी सर्वांगीण क्षमता, कॉलेज में रहने से लाभ उठाने की क्षमता के साथ-साथ साक्षात्कार में योगदान करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

*

कॉलेज का जीवन।ग्रेडिंग द्वारा प्रदर्शन का आकलन करना शैक्षणिक क्षेत्र में अपनाई जाने वाली एक प्रसिद्ध सी विधि है।
[170 एफ-171 ए]

8.02 .केवल छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों द्वारा निर्धारित प्रवेश, भविष्य के शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए सबसे अच्छा उपलब्ध वस्तुनिष्ठ मार्गदर्शक नहीं हो सकता है।दूसरी ओर कॉलेज प्रवेश कार्यक्रम, उम्मीदवारों के वादे और उपलब्धि की परीक्षा पर आधारित प्रतीत होता है

>

डी योग्यता परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन के अंधे तरीके से बेहतर होगा।सेंट स्टीफन कॉलेज विश्वविद्यालय के विवादित परिपत्रों से बंधा नहीं है।[172 बी-सी]

9.01 .शैक्षणिक संस्थान व्यापारिक घराने नहीं हैं।वे धन उत्पन्न नहीं करते हैं।वे सार्वजनिक धन या निजी धन के बिना जीवित नहीं रह सकते।

ई.

सहायता करते हैं।शुल्क के संग्रह पर प्रतिबंध के साथ शुल्क के संग्रह पर भी प्रतिबंध है, अल्पसंख्यकों को अनुदान-सहायता के बिना शैक्षणिक संस्थानों को बनाए रखने का बोझ नहीं डाला जा सकता है।वे नहीं करते।

2

दूसरों पर आर्थिक लाभ प्राप्त करें।राज्य की सहायता के बिना शैक्षणिक संस्थान होना संभव नहीं है।इसलिए अल्पसंख्यकों को अपने दम पर शैक्षणिक संस्थानों को बनाए रखने के लिए नहीं कहा जा सकता है।[179 डी-ई]

च

9.02 .अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए राज्य अनुदान का कोई हक नहीं है।एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए राज्य अनुदान प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 337 के तहत केवल एक विराम-अंतराल व्यवस्था थी।राज्य से अनुदान प्राप्त करने के लिए अन्य अल्पसंख्यकों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।लेकिन जी अनुच्छेद 30 (2) के तहत, राज्य शैक्षणिक संस्थानों को सहायता प्रदान करने में उपचार की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बाध्य है।वित्तीय सहायता देते समय अल्पसंख्यक संस्थानों के साथ अलग

व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।वे उसी तरह वित्तीय सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं जैसे बहुसंख्यक समुदायों के संस्थान प्राप्त करते हैं।[178 जी-17 9 ए]

9.03 .राज्य सहायता की प्राप्ति अनुच्छेद एसटी के अधिकारों को बाधित नहीं करती है।

एच.

स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय 133

30 (1) .राज्य अनुदान-ए सहायता प्राप्त करने और इसके उचित उपयोग के लिए उचित शर्तें निर्धारित कर सकता है।राज्य के पास अनुच्छेद 30 (1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को अपने अधिकारों को छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोई शक्ति नहीं है।[179 बी] 9.44।अनुच्छेद 36 (1) के तहत अधिकार इसके बाद भी अप्रभावित रहते हैं।

सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करना।[179 डी]

10.01 .संविधान धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की स्थापना करता है।किसी भी लोकतंत्र का सजीव सिद्धांत लोगों की समानता है।लेकिन यह विचार कि सभी लोग समान हैं, गहराई से अटकलबाजी है।कुछ व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करने के लिए, हमें उनके साथ अलग व्यवहार करना चाहिए।हमें अल्पसंख्यकों के पक्ष में उचित स्तर पर भेदभाव को पहचानना होगा।लेकिन धार्मिक तटस्थ सी तरीके से धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सकारात्मक कार्रवाई करना असंभव है।धर्म से परे जाने के लिए।हम धर्म को नजरअंदाज नहीं कर सकते।हमें पहले धर्म का ध्यान रखना चाहिए।[181 जी]

10.02 .सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण

"

डी अग्रिम को बढ़ावा देकर बड़े पैमाने पर समाज के हितों की सेवा करेगा

समाज में कमजोर तत्वों का ध्यान रखना।[182 बी]

10.03 .कानून के समक्ष समानता की अवधारणा और कुछ प्रकार के भेदभाव के निषेध के लिए समान व्यवहार की आवश्यकता नहीं है।2 'समानता का अर्थ है सापेक्ष समानता, अर्थात् समान रूप से व्यवहार करने का सिद्धांत जो समान और असमान हैं। असमान लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए उनकी असमानता के अनुसार अनिवार्य रूप से अलग होना न केवल अनुमति है बल्कि आवश्यक है।ई [182 एच]

बॉम्बे राज्य बनाम।बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी, [1955] 1 एस. सी. आर. 568; सिद्धजभाई भाई बनाम।बॉम्बे और अन्र राज्य।, [1963] 3 एससीआर 837; रेव. 7 पिता W.Proost और ओआरएस।वी.बिहार राज्य और अन्य।, [1969] 2 एस. सी. आर. 73; गांधी फैज़-एम-कॉलेज शाहजहांपुर बनाम।आगरा विश्वविद्यालय और अन्र।, [1975] एफ 2 एससीसी 283। D.A.V.College जालुंडुर बनाम.पंजाब राज्य, [1971] 2 एस. सी. सी. 269; A.P.Christian मेडिकल एजुकेशनल सोसाइटी बनाम।आंध्र प्रदेश सरकार, [1986] 2 एससीआर 749; चिक्कला सैमुअल बनाम।जिला शिक्षा अधिकारी, हैदर बड और अन्र।, ए. आई. आर. 1982 ए. पी. 64; राजेरशी मेमोरियल बेसिक ट्रेनिंग स्कूल बनाम।केरल राज्य और ए. एन. आर., ए. आई. आर. 1973 केर।89 ; अज़ीज़ बाशा बनाम।भारत संघ, [1968] 1 एससीआर 833; S.K.Patro वी।बिहार राज्य, [1970] 1 एससीआर 172; पुनः:जी केरल शिक्षा विधेयक, 1957, [1959] एस. सी. आर. 995; केरल राज्य बनाम।मदर प्रो विंसियल, [1971] 1 एस. सी. आर. 734; अहमदाबाद सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज सोसाइटी बनाम।गुजरात राज्य और अन्र।, [1975] 1 एस. सी. आर. 173; लिली कुरियन बनाम।लेविना और ओर्स।, [1979] 1 2 एस. सी. सी. 124; आर.Rev.Magr मार्क नेटो v.केरल सरकार, [1979] 1 एस. सी. आर. 609; स्कूल शिक्षा निदेशक, तमिलनाडु सरकार बनाम।रेव. भाई जी. आरोग्यसामी, ए. आई. आर. 1971 मद्रास 440; R.Chitralekha और ओआरएस।वी.

134 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1991] की स्थिति।3 एस सी आर।

ए मैसूर और ओआरएस।, [1964] 6 एससीआर 308:A.Peeriakaruppan v.तमिलनाडु राज्य, [1971] 2 एस. सी. आर. 430; सुश्री निशी माघू और अन्य।वी.जम्मू और कश्मीर राज्य, [1980] 4 एससीआर 95; अजय हसिया आदि। V.Khalid मुजीब सेहरावर्दी, [1981] 2 एससीआर 79; लीला धर बनाम।राजस्थान राज्य और अन्य।, [1982] 1 एससीआर 320, कोशल कुमार गुप्ता बनाम।जम्मू और कश्मीर राज्य, [1984] 3 एससीआर 407; DN.Chanchala वी।

मैसूर राज्य।[1971] सप.एस. सी. आर. 608, मद्रास राज्य बनाम।चंपकम दोराजराजन, [1951] 2 एससीआर 525; मैक कुलॉक बनाम।मैरीलैंड, 4 व्हीट 316 407 पर; कोहेन बनाम।वर्जिना, 6 व्हीट 264 387 पर; कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बनाम।एलन बक्के, 438 U.S.265; बालाजी बनाम।मैसूर राज्य, [1963] 1 पूरक।एस. सी. आर. 43; अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ (रेलवे) बनाम।भारत संघ और ओआरएस।, [1981] 2 एस. सी. आर. 185; केरल राज्य बनाम। N.M.Thomas और ओआरएस।, [1976] 1 एस. सी. आर. 906,933, संदर्भित।

ग

B.Shiva रावःभारत के संविधान का निर्माण-दस्तावेजों का चयन करें, Vol.II P.298; CAD खंड VII 1949 pp.895 , 925 ; B.Shiva रावःभारत के संविधान की रचना एक अध्ययन, 1969 एड. पी.280 , ले जाया जाता है।

डी.

एन. एम. कासलीवाल, जे. (असहमति)

1.01 .हमारे संविधान का उद्देश्य विविधता में एकता है।यह विविधताओं को आत्मसात करके एकता को समृद्ध करने के लिए है, यह विभाजक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं है।इसलिए, Art.30 (1) द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार का विस्तार नहीं किया जाना चाहिए ताकि अन्य मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण किया जा सके।

ई.

अधिकार या संस्थापक पिताओं के इरादों के विपरीत जाना।[209 डी] 1.02।संविधान के निर्माता विभिन्न धर्मों, विशिष्ट भाषाओं और विविध संस्कृतियों वाले विभिन्न समुदायों की समस्याओं को पूरी तरह से जानते थे।हमारे संविधान की पूरी इमारत धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है और जहां तक अल्पसंख्यकों का संबंध है, इसे माना जाता था

च

यह आवश्यक है कि उन्हें अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के संबंध में कुछ अधिकार दिए जाएं।भारत के क्षेत्र में या उसके किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति रखने का अधिकार दिया गया था।शिक्षा संपूर्ण समाज को एकजुट करने का एक मजबूत कारक है

जी देश और यह आवश्यक माना जाता था कि जहां कोई भी शैक्षिक

संस्थान का रखरखाव राज्य द्वारा किया जाता है या राज्य निधि से सहायता प्राप्त की जाती है तो ऐसी संस्था में प्रवेश के मामले में प्रत्येक नागरिक को समानता के अधिकार की गारंटी दी जाती थी।यदि धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक राज्य निधि से किसी भी सहायता के बिना किसी भी शैक्षणिक संस्थान को चलाना चाहते हैं, तो ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामले में अल्पसंख्यकों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था और वे इसके लिए स्वतंत्र थे।

:

एसटी.स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय 135 अपने समुदाय के छात्रों को प्रवेश देता है।लेकिन ऐसे मामले में जहां वे राज्य निधि से सहायता प्राप्त कर रहे थे, जो इस देश के प्रत्येक नागरिक से करों के माध्यम से योगदान से आता है, तब अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित ऐसे शैक्षणिक संस्थानों को अन्य सभी संस्थानों के अनुरूप होना पड़ता था

शैक्षणिक संस्थान और वे किसी भी नागरिक को धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर प्रवेश से इनकार करने के हकदार नहीं थे।[208 सी-ई] बी 1.03।हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि धार्मिक कट्टरवाद और भाषाई संकीर्णता विघटनकारी प्रवृत्तियों की ओर ले जाती है और समग्र रूप से राष्ट्रीय एकता में बाधा डालती है।यह आवश्यक है कि अल्पसंख्यक शामिल हों और देश की आम धारा का हिस्सा बनें।संविधान निर्माताओं ने इस देश के नागरिकों के किसी भी वर्ग की विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का प्रावधान किया और अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार दिया।साथ ही कला में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है।28 कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी जो पूरी तरह से राज्य निधि से संचालित होती है।जबकि संस्थान के रखरखाव या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने के मामले में, किसी भी नागरिक को अनुच्छेद 29 के खंड (2) के तहत केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।अल्पसंख्यकों के अपनी भाषा में

शिक्षा प्रदान करने और अतिरिक्त पाठ्यचर्या गतिविधियों के माध्यम से अपनी संस्कृति का प्रसार करने और इस प्रकार अपनी संस्कृति का संरक्षण करने के अधिकार में कोई बाधा या बाधा नहीं है।कला का खंड (2)।29 इस तरह के किसी भी अधिकार को नहीं छीनता है और न ही अल्पसंख्यकों पर उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों को चलाने में कोई प्रतिबंध लगाता है।बल्कि यह अल्पसंख्यकों के हित में होगा कि वे अन्य समुदायों के छात्रों को प्रवेश दें और समुदाय की एक विस्तृत श्रृंखला में अपनी संस्कृति का प्रसार करें।के लिए

उदाहरण के लिए, यदि ईसाई एक शैक्षणिक संस्थान चला रहे हैं, तो वे शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी रखने के लिए स्वतंत्र हैं। वे ईसाई धर्म के उच्च आदर्शों और मूल्यों को भी सिखा सकते हैं।एकमात्र प्रतिबंध वह है जो कला में निहित एफ है।28 (3) जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान पर लागू होता है, चाहे वह अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक संस्थान क्यों न हो।Art.28 (3) के तहत प्रतिबंध यह है कि ऐसे शैक्षणिक संस्थान में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी जो ऐसी संस्था में दी जा सकती है या किसी भी धार्मिक पूजा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी जो ऐसी संस्था में उसकी सहमति के बिना आयोजित की जा सकती है और यदि ऐसा व्यक्ति अपने अभिभावक की सहमति के बिना नाबालिग है।[208 एफ-209 सी]

1.04 .संविधान के भाग (III) की पूरी योजना का अवलोकन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि संविधान निर्माताओं का इरादा किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए पूर्ण अधिकार प्रदान करने का नहीं था। प्रवेश के अधिकार को कला द्वारा सीमित किया गया है।

1 1

136

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

ए 15 (4) जो राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े किसी भी नागरिक वर्ग या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासन के मामले में कोई विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है।

4 2

राज्य से सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षणिक संस्थानों में।कला.28 (3) एक अन्य प्रतिबंध लगाता है जिसके अनुसार राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या कोई सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या ऐसी संस्था में दी जाने वाली या आयोजित किसी भी धार्मिक पूजा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

ऐसे व्यक्ति की सहमति या यदि ऐसा व्यक्ति अपने अभिभावक की सहमति के बिना नाबालिग है।इस प्रकार, भले ही किसी अल्पसंख्यक ने एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की हो, लेकिन यदि वह सहायता प्राप्त करता है या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है,

यह कला के अधिदेश से बंधा हुआ है।28 (3) .तीसरा प्रतिबंध कला द्वारा लगाया गया है।सी 29 (2) जिसके अनुसार यदि ऐसे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान प्राप्त करते हैं

राज्य निधि से सहायता तब किसी भी नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर प्रवेश से इनकार नहीं कर सकती है।इस प्रकार अनुच्छेद 15 (4), 28 (3) और 29 (2) अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकार पर सीमाओं को व्यक्त करते हैं।30 (1) .[212 ए-डी]

डी.

1.05 .मामले के किसी भी दृष्टिकोण से यदि कॉलेज से सहायता प्राप्त हो रही है

राज्य को कला की कठोरता का पालन करना पड़ता है।29 (2) मामले में

•

महाविद्यालय में छात्रों का प्रवेश।[213 ई] 1.006।सेंट स्टीफन कॉलेज और इलाहाबाद कृषि संस्थान आरक्षण के किसी भी तरजीही अधिकार का दावा करने के हकदार नहीं हैं।

ई.

ईसाई समुदाय के छात्रों को अनुदान सहायता मिल रही है।[213 जी] 2.01।मामलों में शामिल विवाद कला के खंड (2) के बीच है।29 और कला का खंड (1)।30. संविधान के निर्माता अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण देने की आवश्यकता के बारे में पूरी तरह से जानते थे, लेकिन साथ ही वे चाहते थे कि यदि कोई शैक्षिक

च

संस्थान राज्य निधि से सहायता प्राप्त करके चलाए जाते हैं तो किसी भी नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है।

भाषा या उनमें से कोई भी।अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकार।29 (1) या कला:30 (1) कला के खंड (2) के दौरान सक्षम कर रहे हैं।29 एक आदेश है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के मामले में

राज्य द्वारा बनाए गए या सहायता प्राप्त करने वाले सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और उन्हें केवल धर्म, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है।कला के तहत गारंटीकृत अधिकार।29 (2) एक विशेष अधिकार है जो गारंटीकृत सामान्य अधिकार पर प्रबल होगा

कला के तहत अल्पसंख्यक।30 (1) .[202 एफ-जी]

2.02 एस. टी. की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार अल्पसंख्यकों को दिया गया।

एच.

स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय 137

कला के तहत शैक्षणिक संस्थान।30 (1) संविधान का अनुच्छेद निरपेक्ष ए नहीं है और हमेशा उचित विनियमों के अधीन है। अगर एक अल्पसंख्यक ने स्थापित किया था

शिक्षा प्राप्त किए बिना शैक्षणिक संस्थान का प्रशासन कर रहा है

राज्य निधि से सहायता तब अनुच्छेद के खंड (2)।29 खेल में नहीं आएगा।हालाँकि, यदि ऐसा शैक्षणिक संस्थान राज्य से सहायता प्राप्त कर रहा है

निधियां तब कला के खंड (2) की कठोरता के अधीन होंगी।29 और यह केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा बी या उनमें से किसी के आधार पर प्रवेश से इनकार नहीं कर सकता है।यदि ऐसी संस्था अपने धर्म से संबंधित उम्मीदवारों को वरीयता देती है या आरक्षण देती है, तो यह कारण देने के लिए बाध्य है

दूसरे से संबंधित उम्मीदवार के साथ असमानता और भेदभाव

धर्म और यह धर्म के आधार पर प्रवेश से इनकार होगा और कला द्वारा प्रभावित होगा।29 (2) .[201 ए-सी]

ग

2.03 .कला के तहत प्रदत्त अधिकार।30 एक सामान्य अधिकार है जो सभी अल्पसंख्यकों को दिया जाता है, लेकिन यदि कोई शैक्षणिक संस्थान स्थापित और प्रशासित है

इस तरह के अल्पसंख्यकों को राज्य के कोष से अनुदान-सहायता का लाभ भी मिलता है, तो इसे अन्य सभी शैक्षिक संस्थाओं के समान ही देना पड़ता है।

}

ऐसे संस्थान में छात्रों को प्रवेश देने के मामले में संस्थान और

अपने धर्म के छात्रों के लिए किसी भी सीट को प्राथमिकता या आरक्षित नहीं कर सकते।[201 सी] डी 2.04।कला का खंड (2)।29 यह कला के समानता खंड का समकक्ष है।15. किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

धर्म, नस्ल, जाति या भाषा या उनमें से किसी के आधार पर या उनके द्वारा बनाए गए या सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के मामले में

ई.

राज्य।कला का कौन-सा खंड (1)।29 नागरिकों के एक वर्ग के अधिकारों की रक्षा करता है जिसकी अपनी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, खंड (2) द्वारा प्रदत्त अधिकार नागरिक को दिया गया एक व्यक्तिगत अधिकार है न कि किसी समुदाय के सदस्य के रूप में।यह खंड (2) सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है, चाहे वे बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हों।

कला की तुलना में।15 (1) , ऐसा प्रतीत होता है कि 'लिंग' और 'जन्म स्थान' को कला से हटा दिया गया है।29 (2) .इसलिए, पुरुषों या महिलाओं के लिए विशेष रूप से लक्षित शैक्षणिक संस्थान को राज्य द्वारा बनाए रखा जा सकता है।

च

संविधान का उल्लंघन।[201 डी-एफ]

2.05 .Art.30 का खंड (1) अल्पसंख्यक समुदाय को संचालित संस्थानों में अपने समुदाय के बच्चों को निर्देश देने का अधिकार देता है।

जी.

उसके द्वारा और उसकी अपनी भाषा में।यह दो अधिकार प्रदान करता है, (ए) एक संस्था स्थापित करने का अधिकार, (बी) इसे प्रशासित करने का अधिकार।स्थापना के अधिकार का अर्थ है अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा किसी संस्था को अस्तित्व में लाना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई एक परोपकारी व्यक्ति अपने स्वयं के साधनों से संस्था या समुदाय को धन देता है या समुदाय बड़े पैमाने पर धन का योगदान करता है।अधिकार का अगला भाग ऐसी संस्था के प्रशासन से संबंधित है।प्रशासन

एच.

एक वक्तव्य का अर्थ है संस्थान के मामलों का प्रबंधन।यह प्रबंधन नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए ताकि संस्थापक या उनके नामांकित व्यक्ति संस्थान को उस तरह से ढाल सकें जैसा वे उचित समझते हैं, और उनके विचारों के अनुसार कि सामान्य रूप से समुदाय और विशेष रूप से संस्थान की सर्वोत्तम सेवा कैसे की जाएगी।हालाँकि, इसमें एक अपवाद है और यह है कि शिक्षा के मानक प्रबंधन का हिस्सा नहीं हैं।ये बी मानक राजनीतिक निकाय से संबंधित हैं और देश और उसके लोगों की प्रगति को ध्यान में रखते हुए अपनाए जाते हैं।इसलिए, यदि विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम को सारणीबद्ध करता है, जिसका पालन किया जाना चाहिए, तो विशेष विषयों के अधीन, जिन्हें संस्थान पढ़ाना चाहता है, और कुछ हद तक राज्य इसके लिए रोजगार की शर्तों को भी विनियमित कर सकता है।

शिक्षकों और छात्रों का स्वास्थ्य और स्वच्छता।इस तरह के नियम सीधे प्रबंधन पर लागू नहीं होते हैं, हालांकि वे अप्रत्यक्ष रूप से इसे प्रभावित कर सकते हैं।अल्पसंख्यक संस्थानों को शैक्षणिक संस्थानों से अपेक्षित उत्कृष्टता के मानकों से नीचे गिरने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, या प्रबंधन के अनन्य अधिकार की आड़ में, सामान्य पैटर्न का पालन करने से इनकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जबकि प्रबंधन उन पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वे दूसरों के साथ कदम रखने के लिए मजबूर हो सकते हैं।[201 जी-202 सी]

डी.

2.06 .कला का खंड (1)।29 यह कला के खंड (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार का पूरक है।30. एक अल्पसंख्यक अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति का प्रभावी रूप से तभी संरक्षण कर सकता है जब उसे अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार हो।हालाँकि, Art.30 (1) के तहत अधिकार Art.29 (1) के तहत विचारों से स्वतंत्र एक अलग अधिकार है। [202 ई]

ई.

3.01 .विश्वविद्यालय उन महाविद्यालयों के संबंध में नियामक उपाय निर्धारित कर सकता है जो ऐसे विश्वविद्यालय से संबद्ध या घटक हैं।यदि इस तरह के उपाय शैक्षिक संस्थान को शिक्षा का एक प्रभावी साधन बनाने के लिए उचित और अनुकूल हैं, तो इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है।[189 ई]

च

3.02 .यह हमारे देश के प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान का मौलिक कर्तव्य है कि वह शिक्षा का अवसर प्रदान करे और भविष्य के शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्तता का आकलन योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जा सकता है न कि साक्षात्कार के आधार पर।[197 B] G 3.03 महाविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार इस देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है।जो नव-धनी या राजनीतिक संरक्षण या आकर्षण रखते हैं, उन्हें साक्षात्कार के आधार पर प्रवेश में वरीयता मिलती है।वे छात्र जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं या समाज के कमजोर वर्ग से संबंधित हैं, हालांकि वे शैक्षणिक विशिष्टता में अधिक मेधावी हैं, आम तौर पर साक्षात्कार के तरीके में नुकसान में रहते हैं।लेकिन जिनके पास अधिक है

एच.

कुछ और या एसटी के बजाय आकर्षक शारीरिक रूप और पोशाक।

स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय 139

वे हवादार और चमकदार प्रकार के उम्मीदवार साक्षात्कार ए में उच्च अंक प्राप्त करते हैं जबकि खुरदरे बिना कटे हीरे की सराहना नहीं की जा सकती है।[198 एफ-जी] 3.04।आईडी1 कॉलेज, दिल्ली सोसायटी के ज्ञापन में उल्लिखित आईडी1 कॉलेज का प्राथमिक उद्देश्य कॉलेज के छात्रों को विश्वविद्यालय की डिग्री और परीक्षाओं के लिए तैयार करना और ईसाई धर्म के सिद्धांतों में निर्देश देना है, जो निर्देश उत्तर भारत के चर्च के शिक्षण के अनुसार बी में होना चाहिए।यह उद्देश्य पूरी तरह से साक्षात्कार के बजाय योग्यता परीक्षा में अंकों के आधार पर छात्रों को प्रवेश देकर प्राप्त किया जाता है।[198 एच-199 ए]

3.05 .साक्षात्कार के लिए बुलाए गए योग्य उम्मीदवारों में से छात्रों का चयन सौ प्रतिशत, यानी पूरी तरह से साक्षात्कार के आधार पर किया जाता है और यह स्पष्ट रूप से अजय हासिया के मामले में इस अदालत की संविधान पीठ द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लंघन है, जो लगातार किया जाता रहा है।

बाद के मामलों में इस न्यायालय के बाद, अशोक कुमार यादव और अन्य।वी.हरियाणा राज्य और अन्य।, [1985] खण्ड.4 एस. सी. सी. 417, मोहिंदर सैन गर्ग बनाम।पंजाब राज्य और अन्य।, [1991)] 1 एस. सी. सी. 662 और मुनिंद्र कुमार और अन्य।वी.राजीव डी.

गोविल और ओआरएस।, [1991] 3 एससीसी 368।साक्षात्कार के लिए अधिकतम अंक 15 प्रतिशत हो सकते हैं और उससे अधिक नहीं।[199 बी-सी]

3.06 .सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का एक घटक है और विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए क़ानून अध्यादेशों और अन्य नियमों और विनियमों से बंधा हुआ है जो इसके संबद्ध और संबद्ध कॉलेजों पर समान रूप से लागू होते हैं।शिक्षा के मानकों को बनाए रखना विश्वविद्यालय की प्राथमिक चिंता है और इस संबंध में यदि विश्वविद्यालय की सलाहकार समिति ने केंद्रीय प्रवेश समिति और कुलपति द्वारा इस नियम को स्वीकार कर लिया है कि सभी संबद्ध और घटक कॉलेजों में प्रवेश योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किए जाएंगे, तो यह सेंट स्टीफन कॉलेज पर भी बाध्यकारी है।[196 सी-डी]

ई.

च

3.07 .समग्र रूप से छात्र समुदाय के हित में विश्वविद्यालय की प्राथमिक चिंता स्नातक स्तर पर अध्ययन के लिए समान अवसर प्रदान करना है।वर्तमान मामले में साक्षात्कार का तरीका भेदभाव का कारण बनता है और कला का उल्लंघन करता है।14 क्योंकि इसका स्नातक स्तर पर शिक्षा के अवसर की समानता प्रदान करने के उद्देश्य के साथ कोई उचित संबंध नहीं है।[196 ई]

3.08 .सेंट स्टीफंस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का एक घटक कॉलेज है और विश्वविद्यालय ने 9 जून, 1980 को एक विवादित अधिसूचना जारी की है, जिसके द्वारा एक समान नियम बनाया गया है कि सभी एच. 140 में प्रवेश

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

*

विश्वविद्यालय के एक संबद्ध और घटक महाविद्यालय योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाए जाने चाहिए।[195 जी] 3.09।कॉलेज द्वारा अपनाई गई साक्षात्कार की विधि यह नहीं बताती है कि योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुपात में साक्षात्कार के लिए कितने प्रतिशत अंक रखे जाते हैं।बी प्रत्येक छात्र का यह अधिकार है कि वह कॉलेज द्वारा निर्धारित प्रवेश के आधार को पहले से जान ले।[196 एफ]

3.10 .यह नहीं दिखाया गया है कि कॉलेज के अल्पसंख्यक चरित्र को कैसे प्रभावित किया जाएगा या पूर्वाग्रहित किया जाएगा यदि छात्र गैर से संबंधित हैं

ईसाई समुदाय को प्रवेश केवल योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों सी के आधार पर दिया जाता है न कि साक्षात्कार द्वारा।[196 जी] 3.11।कॉलेज द्वारा अपनाई गई साक्षात्कार की विधि से पता चलता है कि साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों में से अंतिम चयन सौ प्रतिशत यानी केवल साक्षात्कार के आधार पर होता है और इस स्तर पर यह नहीं दिखाया गया है कि योग्यता परीक्षा में प्राप्त डी अंकों और साक्षात्कार के लिए कितना वजन/प्रतिशत दिया जाता है।

आनुपातिक रूप से।चयन की इस विधि के परिणामस्वरूप मनमाना चयन होना तय है।[190 ई-एफ]

3.12 .साक्षात्कार का तरीका परीक्षा राष्ट्र में कदाचार या नकली और जाली प्रमाण पत्र और अंक-पत्र प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है।द.

ई.

इस संबंध में कॉलेज किसी भी छात्र को प्रवेश देने से इनकार करने का हकदार है, जिसके मामले में इस तरह के कदाचार का पता चलता है।[197 जी]

3.13 .हालांकि साक्षात्कार आयोजित करने में कॉलेज के खिलाफ किसी भी दुर्भावना का कोई आरोप नहीं है, लेकिन यह नहीं भुलाया जा सकता है कि साक्षात्कार की प्रणाली में ही अंतर्निहित कमजोरी और दुर्बलता है जिसमें

च

वस्तुनिष्ठ संतुष्टि के बजाय व्यक्तिपरक एक प्रमुख भूमिका निभाता है।इस पृष्ठभूमि में सेंट स्टीफंस कॉलेज में लंबे समय से प्रचलित साक्षात्कार द्वारा चयन की विधि को इतना पवित्र नहीं माना जा सकता है कि इसे रद्द या बदला नहीं जा सकता है, भले ही इस तरह की विधि को दिल्ली विश्वविद्यालय से मंजूरी न मिले।मान लीजिए कि ग्विवा वॉस की विधि के पीछे कोई वैधानिक या विधायी मंजूरी नहीं है और न ही उच्च माध्यमिक या 10 + 2 परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कॉलेज में छात्रों को प्रवेश देने के चरण में किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कोई विधि है।यदि सेंट स्टीफन कॉलेज को छोड़कर दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्य सभी संबद्ध और घटक कॉलेज, योग्यता परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर छात्रों को प्रवेश दे रहे हैं और विश्वविद्यालय अपने विवेक एच में साक्षात्कार की विधि को समाप्त करने और एक समान नियम अपनाने का प्रयास कर रहा है, तो सेंट स्टीफन कॉलेज,

आई.

एसटी.स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय 141

स्टीफंस कॉलेज भी इस तरह के नियम का पालन करने के लिए बाध्य है और लंबे अभ्यास के आधार पर ए पर आपत्ति नहीं कर सकता है।[199 ई-जी]

3.14 .डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले छात्र आम तौर पर 15 से 17 वर्ष की कम उम्र के होते हैं और ऐसे छात्रों के व्यक्तित्व का अभी भी विकास होना बाकी है और इस तरह डिग्री पाठ्यक्रमों में उनके प्रवेश के लिए एकमात्र विचार उनका शैक्षणिक होना चाहिए।

योग्यता परीक्षा में प्रदर्शन।[199 एच] 3.15।विवरण पत्रिका में कहा गया है कि अंतिम चयन साक्षात्कार के बाद किया जाएगा। इससे पता चलता है कि चयन निकाय के प्रबंधन का प्रवेश स्वीकार करने या अस्वीकार करने पर पूरा नियंत्रण होता है

एस.

उनकी अपनी पसंद के अनुसार और योग्य उम्मीदवारों में से किसी भी उम्मीदवार को साक्षात्कार के आधार पर प्रवेश से इनकार किया जा सकता है।[191 बी] 3.16।विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए निर्देश के विपरीत साक्षात्कार के तरीके को लागू करने में कॉलेज की कार्रवाई पूरी तरह से मनमाना, गलत और अवैध है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।[196 बी]।डी. 4.01।यह निर्माण का एक सर्वविदित नियम है कि सामान्य कानून पर विशेष कानून लागू होता है जैसा कि मैक्सिम जनरलिया स्पेशलाइबस नॉन एलिमेंटेंट में निहित है।[202 एच]

4.02 .सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत के लिए किसी न्यायालय को पहले निर्माण द्वारा वैमनस्य पैदा करने की आवश्यकता नहीं है ताकि उसके बाद सामंजस्यपूर्ण निर्माण द्वारा इसका समाधान किया जा सके।व्याख्या का सुनहरा नियम यह है कि शब्दों को सामान्य, प्राकृतिक और व्याकरणिक अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए और सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत केवल इस नियम को लागू करता है कि जहां किसी विषय से संबंधित कानून का सामान्य प्रावधान है, और एक ही विषय से संबंधित विशेष प्रावधान है, तो सामान्य पर विशेष हावी होता है।यदि इसका निर्माण इस तरह से नहीं किया जाता है तो इसका परिणाम यह होगा कि विशेष प्रावधान पूरी तरह से विफल हो जाएगा।[212 डी-ई]

ई.

च

4.03 .संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करते समय कोई भी शब्द आयात या जोड़ा नहीं जा सकता है।यदि कॉलेज की ओर से उठाए गए विवाद को स्वीकार कर लिया जाता है तो इसमें अनिवार्य रूप से शब्दों का आयात शामिल होगा।

जी.

" कला में अपने स्वयं के समुदाय के लिए।30 (1) .कला का खंड (2)।29 द्वारा स्थापित किसी भी शैक्षणिक संस्थान के लिए कोई अपवाद नहीं है

अल्पसंख्यकों और यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि यह राज्य द्वारा बनाए गए या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान पर लागू होता है, चाहे वह अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक द्वारा संचालित हो।[202 एच-203 बी]

{

एच.

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

आई. 142

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

R.Chitralekha & Anr.वी.मैसूर राज्य और अन्य।, [1964] 6 एससीआर 638; अजय

क.

हसिया वी।खालिद मुजीब सहरावर्दी और अन्य।आदि, [1981] 2 एस. सी. आर. 79;

A.Peeriakaruppam v.तमिलनाडु राज्य और अन्य।, [1971] 2 एससीआर 430; अशोक कुमार यादव और अन्य। वी.हरियाणा राज्य और अन्य।, [1985] 4 एससीसी 417;

मोहिंदर सैन गर्ग बनाम।पंजाब राज्य और अन्य।, [1991] 1 एस. सी. सी. 662; मुनिंद्र कुमार और अन्य।वी.राजीव गोविल और अन्य।, [1991] 3 एस. सी. सी. 368; बॉम्बे राज्य बनाम।बी एजुकेशन सोसाइटी, [1955] 1 एस. सी. आर. 568; मद्रास राज्य बनाम।श्रीमती चंपकम दोरैर्जन, [1951] एस. सी. आर. 525; री केरल शिक्षा विधेयक, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 956; सिद्धराजभाई बनाम।गुजरात राज्य, [1963] 3 एस. सी. आर. 837; कटरा एजुकेशन सोसाइटी बनाम।उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य, [1966] 3 एस. सी. आर. 328; गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद बनाम।रंगनाथ मधोलकर, [1961] पूरक।एस. सी. आर. 112; द अहमदाबाद St.Xaviers कॉलेज सोसाइटी और ए. एन. आर.आदि वी।गुजरात सी और ए. एन. आर., [1975] 1 पी पर एस. सी. आर. 173।298 ; डी. ए. वी. महाविद्यालय आदि।पंजाब राज्य और अन्य।, [1971] पूरक।एस. सी. आर. 688 पी.695 ; रे में।केरल शिक्षा विधेयक, 1957 (संदर्भ मामला), [1959] पृष्ठ 1047 पर एससीआर 995; वारब्रुटन बनाम।लव लैंड, [1832] 2 डी एंड सीएल।400 , संदर्भित किया गया।

लोक कार्मिक प्रशासनःग्लेन स्टाल द्वारा संदर्भित।

डी.

मौलिक न्यायनिर्णयः1980 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 1868 (संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

सहित

ई.

डब्ल्यू. पी. नहीं।13213-14 / 84 , टी. सी. नं.3/80

सहित

1

C.A.Nos।1831-41 / 89 , 1786/89 और

च

C.A.No। 1989 का 2829।

V.R.Reddy, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, अनिल बी. दीवान,

M.K.Ramamurthi, R.K.Garg और A.K.Sen, S.S.Shroff, श्रीमती P.S.Shroff, R.Sasiprabhu, सैयद नकवी, श्रीमती सी. राममूर्ति, M.A.Krishnamoorthy, अनिल कुमार गुप्ता, मनोज गोयल, अशोक ग्रोवर, H.L.Tiku, P.K.Chakravarti, ए।

जी.

उपस्थित दलों के लिए मरियारपुथम, श्रीमती अरुणा माथुर, नरसिम्हा (P.S.V.L), हरीश एन. साल्वे (N. P.) और श्रीमती शोभा दीक्षित।

न्यायालय के निर्णय दिए गए थे

के. जगन्नाथ शेट्टी, जे. परिचयःसेंट स्टीफंस *

एच.

5

एसटी.स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय (शेट्टी, जे.) 143

नई दिल्ली में महाविद्यालय और नैनी में इलाहाबाद कृषि संस्थान हमारे दो प्रमुख और प्रसिद्ध संस्थान हैं।पहला दिल्ली विश्वविद्यालय से और दूसरा यू. पी. विश्वविद्यालय से संबद्ध है।दोनों सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान हैं और राज्य निधि से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।उनका अपना प्रवेश कार्यक्रम है जिसका वे हर शैक्षणिक वर्ष में पालन करते हैं।प्रवेश कार्यक्रम ईसाई छात्रों के पक्ष में वरीयता देने का प्रावधान करता है।यह दावा किया जाता है कि वे अपने स्वयं के प्रवेश कार्यक्रम के हकदार हैं क्योंकि बी वे धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थान हैं।प्रवेश प्रो ग्राम की वैधता और ईसाई छात्रों को दी जाने वाली वरीयता ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें इन मामलों में हल करने की आवश्यकता है।ये प्रश्न बहुत संवैधानिक महत्व के हैं और देश के सभी अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए परिणाम हैं।

एस.

सामान्य तथ्य

एसटी.स्टीफन कॉलेज सेंट स्टीफन कॉलेज की स्थापना 1 फरवरी, 1881 को हुई थी।यह दिल्ली का सबसे पुराना कॉलेज है।यह पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय और फिर पंजाब विश्वविद्यालय और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध था।डी दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्धता के बाद यह इसके तीन मूल घटक कॉलेजों में से एक बन गया।महाविद्यालय बी. ए./बी. एस. सी. में तीन साल का डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान करता है।(ऑनर्स), बी. ए. (उत्तीर्ण) और B.Sc.General के साथ-साथ एम. ए. में दो साल का स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम और

एम. एससी. शैक्षणिक वर्ष 1980-81 के लिए, कॉलेज ने 25 मई, 1980 को "प्रवेश टीएम प्रॉस्पेक्टस" प्रकाशित किया, जिसमें ई के लिए आवेदन प्रदान किए गए थे।

प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश 20 जून, 1980 को या उससे पहले कॉलेज कार्यालय में प्राप्त किया जाना चाहिए।उसी विवरण पत्रिका में यह भी प्रावधान किया गया था कि महाविद्यालय में प्रवेश के लिए छात्रों के अंतिम चयन से पहले साक्षात्कार होगा।ऐसा प्रतीत होता है कि 22 मई, 1980 को दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने विश्वविद्यालय के कानूनों के संविधि 11-जी (4) के तहत अपनी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए विचार करने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया और एफ.

शैक्षणिक सत्र 1980-81 और अन्य संबंधित मामलों के लिए कला और सामाजिक विज्ञान/गणित और विज्ञान संकायों में विभिन्न स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश/पंजीकरण के लिए तिथियों की सिफारिश करें।

प्रवेश के बारे में।सलाहकार समिति का गठन था

29 मई, 1980 को आयोजित अपनी बैठक में अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित और शैक्षणिक परिषद ने कुलपति को कार्यान्वयन के लिए सलाहकार समिति की जी सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए भी अधिकृत किया।अदवी सोरी समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित रूप में निर्धारित कियाः

" (1) बी. ए. में प्रवेश (उत्तीर्ण)/बी. ए. व्यावसायिक अध्ययन पाठ्यक्रम योग्यता परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत की योग्यता पर आधारित होंगे।

एच}

144

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

(ii) B.Com (पास) बी. ए. में प्रवेश। (ऑनर्स) और B.Com

क.

(ऑनर्स।) पाठ्यक्रम भी अंकों के आधार पर होते हैं।हालांकि, कॉलेज कुल अंकों के अलावा एक या अधिक व्यक्तिगत विषयों में प्राप्त अंकों को महत्व दे सकता है।

योग्यता परीक्षा।लेकिन जब भी कॉलेज द्वारा अलग-अलग विषयों को महत्व देने का प्रस्ताव किया जाता है, तो इसे कॉलेज प्रॉस्पेक्टस/नोटिस के माध्यम से छात्रों को पहले से सूचित किया जाना चाहिए।

1

बोर्ड ताकि प्रवेश चाहने वाले आवेदकों को पहले से पता हो

प्रवेश का आधार।

(iii) सभी स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 जून, 1980 होगी और सभी महाविद्यालयों द्वारा इसका औपचारिक रूप से पालन किया जाएगा।

ग

इन सिफारिशों को केंद्रीय प्रवेश समिति और कुलपति ने भी स्वीकार कर लिया था।

विश्वविद्यालय के निदेशक

डी.

कि 5 जून, 1980 को विश्वविद्यालय ने सभी संबद्धों को परिपत्र जारी किया

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 जून, 1980 निर्धारित करने वाले कॉलेज।परिपत्र में प्रवेश का चरणबद्ध कार्यक्रम भी निम्नलिखित रूप में प्रदान किया गया है:A. उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए प्रवेश का पहला चरण

ई.

45 % निशान या उससे ऊपर

(i) प्रथम प्रवेश की अधिसूचना

बुधवार 2 जुलाई,

महाविद्यालयों की सूची

1980

शुल्क का भुगतान (तक)

शुक्रवार 4 जुलाई 1980

च

शाम 4 बजे तक

सामान्य नोट:सभी प्रवेश सूचियों में नामों की संख्या के अनुरूप होगी

जी संबंधित पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों की संख्या।कोई भी छात्र जिसका नाम प्रवेश सूची में दिखाई देता है (या जो सूची में बताए गए प्रतिशत के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है) को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा बशर्ते वह निर्धारित तिथि और समय तक शुल्क का भुगतान करे।

शुक्रवार 4 जुलाई 1980

((ii) द्वितीय की अधिसूचना

महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश सूची

6 पीएम एसटी।

एच.

स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय (शेट्टी, जे.) 145 शुल्क का भुगतान

शनिवार 5-सोमवार

क.

7 जुलाई 1980 से शाम 4 बजे तक

B. प्रवेश का दूसरा चरण हासिल करने वाले छात्रों के लिए

45 प्रतिशत से कम लेकिन उससे अधिक

40 % निशानियाँ

आई।

तीसरी अधिसूचना

मंगलवार 8 जुलाई 1980,

महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश सूची

12.00 सायंकाल

गुरुवार 10 जुलाई 1980,

शुल्क का भुगतान (अधिकतम)

4.00 पीएम

ग

9 जून, 1980 को विश्वविद्यालय ने सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को एक और परिपत्र जारी किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बी. ए. में प्रवेश की सूचना दी गई। (उत्तीर्ण)/बी. ए. व्यावसायिक अध्ययन पाठ्यक्रम योग्यता परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत की योग्यता पर आधारित होते हैं।B.Com (पास), बी. ए. में प्रवेश। (ऑनर्स) और B.Com (ऑनर्स) पाठ्यक्रम अंकों के आधार पर होंगे।चाहे जो भी हो, कॉलेज एक या अधिक डी में प्राप्त अंकों को महत्व दे सकता है।

योग्यता के कुल अंकों के अलावा व्यक्तिगत विषय

जाँच।लेकिन जब भी कॉलेज द्वारा व्यक्तिगत विषय (विषयों) को महत्व देने का प्रस्ताव किया जाता है, तो इसे कॉलेज प्रॉस्पेक्टस/नोटिस बोर्ड के माध्यम से छात्रों को पहले से सूचित किया जाना चाहिए ताकि प्रशासक बनने के इच्छुक आवेदकों को प्रवेश का आधार पहले से पता हो।यह परिपत्र कुछ ई भी प्रदान करता है।

खिलाड़ियों और अन्य विशिष्टताओं वाले व्यक्तियों के प्रवेश के लिए दिशानिर्देश।दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों से शिकायत की थी कि कॉलेज आवेदनों की प्राप्ति के लिए अपना समय निर्धारित करने के साथ-साथ प्रवेश से पहले साक्षात्कार निर्धारित करके विश्वविद्यालय के कानूनों और मानदंडों का उल्लंघन कर रहा है।इस शिकायत के आधार पर

विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने 9 जून, 1980 को एक पत्र लिखकर कॉलेज के प्राचार्य से अनुरोध किया कि वे 5 जून, 1980 के परिपत्र द्वारा कॉलेज को भेजी गई विश्वविद्यालय की अनुसूची का पालन करें।इसके बाद कॉलेज प्रबंधन और कुलपतियों के बीच कुछ और पत्राचार हुआ।कॉलेज प्रबंधन ने बताया कि उस अंतिम चरण में उनके प्रवेश कार्यक्रम में कोई बदलाव करना संभव नहीं होगा।वहाँ कुलपति ने 7-9 जून, 1980 को महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष को एक पत्र संबोधित किया जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय प्रवेश समिति के निर्णय के अनुसार, स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 जून, 1980 होनी चाहिए और उस उद्देश्य के लिए महाविद्यालय को 20 जून, 1980 के रूप में निर्धारित करना विश्वविद्यालय के अधिकारियों के लिए बहुत शर्मनाक होगा।कुलपति ने कॉलेज के प्रबंधक को फिर से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथियों का पालन करने के लिए कहा।

च

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

जी146

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कॉलेज के प्राचार्य उस समय उपलब्ध नहीं थे और उनके

क.

उनकी अनुपस्थिति में, कॉलेज के उपाध्यक्ष ने 12 जून, 1980 को कुलपति को पत्र लिखकर जवाब दिया कि "एक सक्षम निकाय द्वारा संभावित छात्रों का साक्षात्कार सेंट स्टीफन कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया का अभिन्न अंग है और इस नीति का पूरे कॉलेज के इतिहास में पालन किया गया है और इसे अत्यधिक महत्व दिया गया है।"इस प्रकार उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से बताया कि कॉलेज के लिए विश्वविद्यालय के परिपत्रों का पालन करना संभव नहीं था।हालाँकि, उन्होंने कुलपति को आश्वासन दिया कि पहली प्रवेश सूची प्रकाशित करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि 2 जुलाई, 1980 से पहले कोई प्रवेश सूची नहीं रखी जाएगी।

एक छात्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को स्थानांतरित किया

एस.

जब मामला इस तरह खड़ा हो गया, तो राहुल कपूर नाम का एक छात्र मांग रहा था

स्नातक पाठ्यक्रम के लिए कॉलेज में प्रवेश ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका संख्या 790/80 दायर की, जिसमें सेंट स्टीफन कॉलेज के प्रवेश कार्यक्रम और उम्मीदवारों के लिए निर्धारित साक्षात्कार परीक्षा को चुनौती दी गई।रिट याचिका 16 जून, 1980 को दायर की गई थी।30 जून, 1980 को उच्च न्यायालय ने कॉलेज को 30 जून, 1980 तक प्रवेश के लिए आवेदन प्राप्त करने का निर्देश देते हुए आदेश पारित किया।

एस.

महाविद्यालय द्वारा प्रवेश सूची की घोषणा करने से लेकर, जिसके लिए निर्धारित तिथि 2 जुलाई 1980 थी, रिट याचिका के निपटारे तक।संयोग से, उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि उसके पास इस तरह का आदेश जारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि सेंट स्टीफंस कॉलेज ने 5 और 9 जून, 1980 के विश्वविद्यालय के परिपत्रों की वैधता को चुनौती नहीं दी थी।यह रिट याचिका 1980 के हस्तांतरित मामले संख्या 3 में विषय वस्तु थी।

ई.

"

एसटी.स्टीफन कॉलेज ने सर्वोच्च न्यायालय को स्थानांतरित किया

कि इन घटनाओं के अनुसरण में, सेंट स्टीफन कॉलेज ने इसे आगे बढ़ाया

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका के माध्यम से न्यायालय।हम हैं।

}

च

मुख्य रूप से 1980 की इस रिट याचिका (सिविल) संख्या 1868 से संबंधित है।रिट याचिका में दिए गए कथन इस प्रकार हैं:कि सेंट स्टीफन कॉलेज एक धार्मिक अल्पसंख्यक-संचालित संस्थान है।यह एक घटक कॉलेज है, एक संबद्ध कॉलेज की तरह जिसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में प्रवेश दिया जाता है, लेकिन एक बनाए रखा कॉलेज नहीं है।बहुत शुरुआत से, कॉलेज कुछ स्पष्ट अभ्यास कर रहा है और

जी अंतर्निहित प्रबंधकीय शक्तियाँ:उनमें से एक प्रवेश के लिए उचित तारीखें तय करना था और दूसरा उम्मीदवारों के साक्षात्कार के लिए था।विश्वविद्यालय द्वारा इन प्रबंधकीय कार्यों पर कभी भी सवाल नहीं उठाए गए हैं या उनमें हस्तक्षेप नहीं किया गया है।यह स्वीकार किए बिना कि विनियमों की सामान्य शक्ति के भीतर, विश्वविद्यालय के पास प्रवेश की तारीख निर्धारित करने की शक्ति है, यह एच कॉलेज के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा क्योंकि इस अनुसूची का निर्धारण प्रत्यक्ष रूप से प्रबंधकीय है।प्रबंधन को करना चाहिए

1 एफआर * एसटी।

स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय (SHETTY, J.) 147 नियंत्रण से मुक्त हो ताकि संस्थापक या उनके नामांकित व्यक्ति ए संस्थान को अपने विचार के अनुसार ढाल सकें।

1

सामान्य रूप से समुदाय और विशेष रूप से संस्थान के हितों की सर्वोत्तम सेवा की जाएगी।इस प्रबंधन के किसी भी हिस्से को गारंटीकृत अधिकार पर अतिक्रमण किए बिना दूसरे निकाय में नहीं लिया जा सकता है और निहित नहीं किया जा सकता है।

वी.

यह भी आरोप लगाया जाता है कि बी कॉलेज को अपनी 300 उपलब्ध सीटों के मुकाबले लगभग 6000 आवेदन प्राप्त होते हैं। इसके पूर्व-प्रतिष्ठित पद के कारण, देश के हर हिस्से से आवेदन आते हैं।बाद के वर्षों में, 12000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। इसलिए, एक दिन के भीतर उन आवेदनों को संसाधित करना और निष्पक्षता की किसी भी झलक के साथ सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों में से 300 का चयन करना मानवीय रूप से असंभव होगा।आम तौर पर

एस.

लगभग 40 प्रतिशत आवेदक बाहर से हैं; भर्ती किए जाने वाले 300 में से 100 छात्रावास में प्रवेश के लिए हैं।साक्षात्कार के लिए प्रावधान, जो अपनी स्थापना के बाद से कॉलेज द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया रही है, कॉलेज के प्रशासन का एक अभिन्न अंग है।यह इसके प्रबंधकीय कार्य का एक हिस्सा है और इसे विश्वविद्यालय द्वारा नहीं लिया जा सकता है।उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त केवल अंकों के आधार पर चयन अनुचित होगा और संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत गारंटीकृत कॉलेज के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।इन और अन्य दलीलों के साथ, कॉलेज ने एक घोषणा के लिए प्रार्थना की कि 5 और 9 जून, 1980 को जारी किए गए परिपत्र

डी.

विश्वविद्यालय अपने अल्पसंख्यक दर्जे को देखते हुए कॉलेज से अलग है।

यह न्यायालय उक्त रिट याचिका में नियम निसी जारी करते हुए रोक लगा चुका है।

ई.

परिपत्रों का संचालन।इस न्यायालय द्वारा दी गई रोक को ध्यान में रखते हुए,

कॉलेज ने बाद के वर्षों में अपनी प्रवेश नीति, तौर-तरीके और कार्यक्रम का पालन करना जारी रखा।

दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ ने सर्वोच्च न्यायालय का प्रस्ताव रखा

च

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ इस लेख में एक मध्यस्थ है

सेंट स्टीफन कॉलेज द्वारा दायर 1980 की याचिका संख्या 1868।कि बाद में प्रवेश वर्ष 1984-85 के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ और डॉ. महेश सी. जैन ने डब्ल्यू. पी. संख्या दायर की।13213-14 / 84 संस्थान के अनुच्छेद 32 के तहत सेंट स्टीफन कॉलेज को विश्वविद्यालय की सभी नीतियों, नियमों, विनियमों, प्रवेश आदि के संबंध में अध्यादेशों का पालन करने का निर्देश देने की मांग की गई है और कॉलेज में प्रवेश के मामले में कॉलेज को क्रिस टियान छात्रों के पक्ष में वरीयता देने से रोकने का निर्देश दिया गया है।रिट याचिका में आरोप लगाया गया था कि कॉलेज को किसी भी अदालत द्वारा अल्पसंख्यक कॉलेज घोषित नहीं किया गया है और न ही इसे विश्वविद्यालय द्वारा अल्पसंख्यक कॉलेज के रूप में मान्यता दी गई है।वैकल्पिक रूप से यह तर्क दिया गया कि यह मानते हुए भी कि यह एक अल्पसंख्यक कॉलेज है, यह एच नहीं है

$

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

जी 148

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कॉलेज के रूप में धर्म के आधार पर छात्रों के साथ भेदभाव करने का अधिकार है

क.

सरकार से रखरखाव अनुदान प्राप्त करना।का भेदभाव

क.

केवल धर्म के आधार पर कॉलेज में प्रवेश के लिए छात्र संविधान के अनुच्छेद 29 (2) के प्रावधानों के विपरीत हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय का मामला

दिल्ली विश्वविद्यालय ने विपक्ष में अपने हलफनामे में कहा है कि

दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, अध्यादेश II और विश्वविद्यालय के प्रासंगिक कानूनों के प्रावधानों के संदर्भ में उपरोक्त परिपत्र जारी करना।संविधि 30 और महाविद्यालयों को सरकारी अनुदान के नियमों और शर्तों का संदर्भ दिया गया है।यह कहा जाता है कि प्रत्येक कॉलेज विश्वविद्यालय के कानूनों, सी अध्यादेशों और विनियमों का पालन करेगा।महाविद्यालय की आवश्यकता है कि

छात्रों के प्रवेश के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना।रिलायंस को अध्यादेश XVIII पर भी रखा गया है जो प्रत्येक कॉलेज में एक कर्मचारी परिषद के गठन का प्रावधान करता है।शिक्षण कर्मचारियों के सभी सदस्य, लाइब्रेरियन और शारीरिक शिक्षा निदेशक कर्मचारी परिषद का गठन करते हैं।प्राचार्य कर्मचारी परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं।डी कर्मचारी परिषद के कार्यों का प्रावधान अध्यादेश XVIII के खंड 6-ए के उपखंड (5) में किया गया है।कर्मचारी परिषद को सौंपे गए कार्यों में से एक है प्रवेश नीति के निर्माण के संबंध में सिफारिशें करना।

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नीति की रूपरेखा।हालांकि, कॉलेज अपनी प्रवेश नीति निर्धारित नहीं कर सकता है ताकि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नीति के साथ टकराव हो।विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार ई में भर्ती अन्य सभी कॉलेजों की तरह, सेंट स्टीफन कॉलेज को भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से रखरखाव अनुदान प्राप्त है।चूँकि कॉलेज राज्य निधि से सहायता प्राप्त कर रहा है, इसलिए यह धर्म और/या भाषा के आधार पर प्रवेश के मामले में भेदभाव करने का हकदार नहीं है।यह स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 29 (2) के जनादेश के विपरीत है।विश्वविद्यालय के परिपत्रों में संबद्ध विश्वविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश के बारे में निर्देश हैं

च

कानून किसी भी तरह से कॉलेज का प्रशासन करने वाले निकाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है, यह स्वीकार किए बिना कि ऐसा निकाय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत मौलिक अधिकार का दावा करने का हकदार है।इसलिए कॉलेज उन दो निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है जो विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के प्रासंगिक अध्यादेशों के तहत अपनी वैधानिक जी शक्ति का प्रयोग करते हुए सभी कॉलेजों को समान रूप से दिए गए हैं।

इलाहाबाद कृषि संस्थान यह एक पेशेवर महाविद्यालय है जो कृषि विज्ञान में अध्ययन के कई पाठ्यक्रम प्रदान करता है।यह निर्विवाद रूप से ईसाई धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित एक संस्था है।1911 में, इसकी स्थापना क्रिस एसटी द्वारा की गई थी।

स्टीफंस कॉलेज वी।डॉ. सैम हिगिनबॉथम के नेतृत्व में दिल्ली विश्वविद्यालय (शेट्टी, जे.) के 149 शिक्षक।यह अब इलाहाबाद के प्रसिद्ध तीर्थ और शिक्षा केंद्र में नैनी नामक एक छोटे से स्थान पर जमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है।इसमें 600 एकड़ का परिसर है जिसमें कर्मचारी आवास, पुरुष और महिला छात्रावास, पुस्तकालय और दस विभागों और संस्थान की सहायक इकाइयों के साथ प्रशासनिक भवन शामिल हैं।यह संस्थान अध्ययन के कई पाठ्यक्रमों जैसे अंतर कृषि, अंतर गृह विज्ञान, भारतीय डेयरी डिप्लोमा (आई. डी. डी.), कृषि में बी. एससी., बी. एससी. में शिक्षा प्रदान करता है। गृह अर्थशास्त्र, बी B.Tech।कृषि इंजीनियरिंग में एम. एससी. कृषि में और एम. एससी. कृषि में

कृषि अभियांत्रिकी।यह एक राष्ट्रीय संस्थान होने का दावा करता है और हर साल विभिन्न केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है। इसने प्रत्येक डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम निम्नानुसार निर्धारित किए हैंः

1 पूरे देश के चर्च प्रायोजित छात्र जिनमें से कम से कम 1/5 सी उत्तर प्रदेश से होंगे। न्यूनतम 50 प्रतिशत

2. चर्च प्रायोजित सहित यू. पी. अधिवास के छात्र 40 प्रतिशत योग्यता रैंकिंग पर आते हैं

3. विदेशी छात्रों सहित अन्य राज्यों के छात्र, लेकिन यू. पी. और डी. चर्च-प्रायोजित छात्रों को छोड़कर 5 प्रतिशत

4. जनजातीय 5 प्रतिशत राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने और ई.

संस्थान की अखिल भारतीय प्रकृति के अनुसार, सीटों का वितरण इस प्रकार होगाः

क्षेत्रः

उत्तर हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एफ बिहार, बंगाल और दिल्ली

40 %

दक्षिणःउड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पांडिचेरी, गोवा, 30 प्रतिशत

अंडमान और निकोबार

10 % जी.

पश्चिमःगुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश

उत्तर-पश्चिमःअसम, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम

-20 %

न.

(2) प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों और पुराने छात्रों को पहले प्रत्येक संबंधित कोटे और क्षेत्रों में समायोजित किया जाएगा।

(3) प्रत्येक श्रेणी में केवल वे लोग हैं जिन्होंने योग्यता प्राप्त की है

क.

प्रवेश परीक्षा पर विचार किया जाएगा और प्रत्येक सूची के भीतर योग्यता के क्रम में सख्ती से प्रवेश दिया जाएगा।

(4) अनुशासनात्मक कार्रवाई-कोई भी छात्र जिसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, उसे इस संस्थान में किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(5) नामांकन का कम से कम 25 प्रतिशत महिला छात्र होंगी।जिन छात्रों को इस संस्थान द्वारा प्रवेश से वंचित कर दिया गया है, उन्होंने चर्च प्रायोजित ईसाई सी छात्रों के आरक्षण और प्रवेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाएं दायर कीं।उच्च न्यायालय ने यह घोषणा करने वाली रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है कि ईसाई छात्रों के लिए आरक्षण की नीति संविधान के अनुच्छेद 29 (2) के तहत नागरिकों के लिए समान गारंटी के विपरीत है।

उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित होने के कारण, संस्थान ने संविधान के अनुच्छेद 133 (1) (ए) के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त करके प्राथमिकता दी है।

डी सिविल अपील सं।1831-41 1989 से।सिविल अपील सं।1786/89 और 2829/89 कुछ छात्रों द्वारा बनाए गए हैं।वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उसी फैसले के खिलाफ जुड़ी हुई अपीलें हैं।

1 .

कानून का प्रश्न

ई.

सुनवाई के दौरान हमारे सामने कई प्रश्नों पर बहस हुई।

महत्वपूर्ण मुद्दों को तीन मुख्य शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता हैः

पहला, क्या सेंट स्टीफंस कॉलेज अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित संस्थान है?दूसराःक्या St.Stephen का कॉलेज अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में बाध्य है

च

5 जून, 1980 और 9 जून, 1980 के विश्वविद्यालय के परिपत्रों में निर्देश दिया गया है कि कॉलेज योग्यता परीक्षाओं में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत की योग्यता के आधार पर छात्रों को प्रवेश देगा।

तीसराःक्या St.Stephen का कॉलेज और इलाहाबाद कृषि

संस्थान अपने छात्रों को वरीयता देने या उनके लिए सीटें आरक्षित करने के हकदार हैं।

जी.

अपना समुदाय और क्या ऐसी वरीयता या आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 29 (2) के तहत अमान्य होगा?

पहले दो प्रश्न केवल सेंट स्टीफन कॉलेज के लिए प्रासंगिक हैं और वे इलाहाबाद कृषि संस्थान के मामले में उत्पन्न नहीं होते हैं क्योंकि उस संस्थान के अल्पसंख्यक चरित्र के बारे में कोई विवाद नहीं है।वहाँ भी नहीं है

“ एसटी.स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय (शेट्टी, जे.) 151

यू. पी. विश्वविद्यालय द्वारा उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया के साथ शिकायत ए के बाद संस्थान द्वारा।तीसरा प्रश्न, निश्चित रूप से, आम लोगों के लिए प्रासंगिक है।

दोनों संस्थानों की समस्याएं।

हम इन प्रश्नों को बारी-बारी से उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले, हम कुछ मामलों का संक्षेप में उल्लेख कर सकते हैं जहां इसी तरह की समस्या सामने आई थी।

बम्बई राज्य बनाम।बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी [1955] 1 एससीआर 568 बॉम्बे राज्य के नासिक जिले के देवलाली में बर्न्स हाई स्कूल के रूप में जाने जाने वाले संबंधित स्कूल को एंग्लो-इंडियन समुदाय से संबंधित होने के रूप में मान्यता दी गई थी, जिसकी मां अंग्रेजी है।इस प्रकार न्यायालय के लिए एंग्लो-इंडियन स्कूल के इस दावे को स्वीकार करने में बहुत कम कठिनाई हुई कि यह संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत संरक्षण का हकदार एक भाषाई अल्पसंख्यक सी संस्थान था।सिद्धजभाई भाई बनाम।बॉम्बे और अन्र राज्य।[1963] 3 एस. सी. आर. 837 यह न्यायालय शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण महाविद्यालय से संबंधित था, जिसे बोरसद, जिला कैरा में "मैरी ब्राउन मेमोरियल ट्रेनिंग कॉलेज" के रूप में जाना जाता था।प्रशिक्षण महाविद्यालय के रखरखाव की लागत आयरिश प्रेस्बिटेरियन मिशन से प्राप्त दान, विद्वानों से शुल्क और राज्य सरकार की शिक्षा संहिता के तहत अनुदान सहायता के रूप में वहन की जाती थी।महाविद्यालय और अन्य बयालीस, प्राथमिक विद्यालय उत्तरी भारत के संयुक्त चर्च के धार्मिक संप्रदाय और आम तौर पर भारतीय ईसाइयों के लाभ के लिए चलाए जाते हैं, हालांकि अन्य समुदायों से संबंधित छात्रों को विज्ञापन मिशन से वंचित नहीं किया जाता है।इसलिए यह माना जाता था कि प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना और प्रशासन ईसाई अल्पसंख्यकों द्वारा किया गया था।रेव. फादर डब्ल्यू. प्रोस्ट और ओआरएस में।वी.बिहार राज्य और अन्य, [1969] 2 एस. सी. आर. 73 में फिर से कोई गंभीर विवाद नहीं था कि संबंधित संस्थान यानी St.Xavier के कॉलेज की स्थापना रांची के जेसुइट्स द्वारा की गई थी, जो एक ईसाई अल्पसंख्यक थे।गांधी फैज़-आम-कॉलेज शाहजहांपुर बनाम।आगरा विश्वविद्यालय और अन्र।, [1975] 2 एस. सी. सी. 283 अपीलार्थी शाहजहांपुर में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा गठित एक पंजीकृत सोसायटी थी।

च

यह G.F.College चला रहा था।प्रबंधन ने संरक्षण का दावा किया

आगरा विश्वविद्यालय द्वारा हस्तक्षेप के खिलाफ अनुच्छेद 30 (1)।न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की कि समुदाय देश में अल्पसंख्यक है और

एक्स

इसके द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान को अनुच्छेद 30 के संवैधानिक दायरे के भीतर एक 'अल्पसंख्यक' संस्थान पाया गया है। G यह निष्कर्ष संस्थान के विकास पर एक त्वरित नज़र से निकाला गया था।डी. ए. वी. कॉलेज में जालंदूर बनाम.पंजाब राज्य, [1971] 2 एस. सी. सी. 269 पंजाब राज्य में आर्य समाज द्वारा स्थापित कॉलेज ने संविधान के अनुच्छेद 29 (1) और 30 (1) के तहत संरक्षण का दावा किया।पंजाब राज्य द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि पंजाब के हिंदू राज्य में एक धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, हालांकि वे पूरे देश के संबंध में ऐसा नहीं हो सकते हैं।आर्य समाज एच का दावा?

हालाँकि, ए को भाषाई अल्पसंख्यक होने के लिए चुनाव लड़ा गया था।इस न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 30 (1) के उद्देश्य के लिए भाषाई अल्पसंख्यक वह है जिसकी कम से कम एक अलग बोली जाने वाली भाषा होनी चाहिए, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उस भाषा की भी अपनी एक अलग लिपि होनी चाहिए।ऐसे लोगों का वर्ग जो ऐसी भाषा बोलते हैं जिसकी कोई लिपि नहीं है, वे भी अनुच्छेद 30 (1) के संरक्षण के हकदार भाषाई अल्पसंख्यक होंगे।चूँकि आर्य समाज की अपनी बी की एक अलग लिपि है, अर्थात् देवनागरी, इस न्यायालय ने माना कि वे अनुच्छेद 29 (1) के तहत गारंटीकृत अधिकार का उपयोग करने के हकदार हैं क्योंकि वे नागरिकों का एक वर्ग हैं जिनकी एक अलग लिपि है।पंजाब राज्य में धार्मिक अल्पसंख्यक होने के कारण उन्हें अनुच्छेद 30 (1) के तहत भी अधिकार प्राप्त है।यह भी देखा गया कि देश की पूरी आबादी के संबंध में धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है और यदि वे विशेष कानून या संबंधित राज्य के संबंध में ऐसा करते हैं तो यह पर्याप्त है।आर्य

समाज के इतिहास का उल्लेख करने के बाद, यह कहा गया कि हालांकि हिंदू समुदाय पूरे भारत में एक बहुसंख्यक समुदाय है, आर्य समाज जिसमें हिंदू समुदाय के सदस्य शामिल हैं, पंजाब में एक धार्मिक अल्पसंख्यक है और वे अनुच्छेद 29 (1) और 30 (1) के तहत अधिकार का दावा करने के हकदार हैं क्योंकि कॉलेज की स्थापना उस धार्मिक अल्पसंख्यक द्वारा अपनी एक लिपि के साथ की गई थी।

डी.

हाल के एक मामले में ए. पी. क्रिश्चियन मेडिकल एजुकेशनल सोसाइटी बनाम।

आंध्र प्रदेश सरकार, [1986] 2 एस. सी. आर. 749 अपीलार्थी एक रेगिस टेरड सोसायटी थी।इसने ईसाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना और प्रशासन करने का दावा किया।इसने मेडिकल कॉलेज में छात्रों को प्रवेश दिया और अनुच्छेद 30 (1) के तहत सुरक्षा का दावा किया।राज्य

}

ई.

सरकार ने महाविद्यालय की स्थापना की अनुमति देने से इनकार कर दिया।विश्वविद्यालय ने भी संबद्धता से इनकार कर दिया।जब मामला इस न्यायालय के समक्ष आया, तो यह देखा गया कि सरकार, विश्वविद्यालय और अंततः न्यायालय के पास यह अधिकार है कि

'अल्पसंख्यक पर्दा' को भेदने और यह पता लगाने के अधिकार पर संदेह किया कि क्या इसके पीछे कोई अल्पसंख्यक नहीं है और किसी भी मामले में कोई अल्पसंख्यक संस्था नहीं है।अल्पसंख्यक संस्थानों को वास्तव में अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान होने चाहिए।

च

वास्तविकता और केवल नकाबपोश काल्पनिक नहीं।इस बात पर जोर दिया गया कि जो महत्वपूर्ण और अनिवार्य है वह यह है कि कुछ वास्तविक सकारात्मक सूचकांक मौजूद होना चाहिए ताकि संस्थान को अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान के रूप में पहचाना जा सके।

चिक्कला में सैमुअल बनाम।जिला शिक्षा अधिकारी हैदराबाद और अन्न।,

जी.

ए. आई. आर. 1982 ए. पी. 64 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 30 (1) के लाभ का दावा करने के लिए सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने वाले संविधान में अल्पसंख्यकों को यह दिखाना चाहिए कि यह किसी तरह से अल्पसंख्यक समुदाय या उसके एक बड़े वर्ग के हित में काम करता है या बढ़ावा देता है।इसके बिना

सबूत के रूप में, यह कहा गया था कि संस्थान और एच अल्पसंख्यक के बीच कोई सांठगांठ नहीं होगी।

$

1 .

एसटी.स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय [शेट्टी, जे.] 153 राजेरशी मेमोरियल बेसिक ट्रेनिंग स्कूल बनाम।केरल राज्य और ए. एन. आर., ए. आई. आर. 1973 केरल 89 केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि केवल यह तथ्य कि इस विद्यालय की स्थापना एक विशेष धार्मिक व्यक्ति द्वारा की गई थी

क.

दृढ़ता इस प्रश्न पर बिल्कुल भी निर्णायक नहीं है।याचिकाकर्ता को संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करके यह साबित करना होगा कि विचाराधीन विद्यालय अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित और प्रशासित था, चाहे वह धर्म या शिक्षा के आधार पर हो।

भाषा।

अज़ीज़ बाशा बनाम।भारत संघ [1968] 1 एस. सी. आर. 833 चुनौती मुख्य रूप से 1951 के संशोधन अधिनियम और 1965 के संशोधन अधिनियम द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 में किए गए कुछ संशोधनों के लिए निर्देशित की गई थी।याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की कि 1965 में किए गए संशोधनों से प्रबंधन को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासन के अधिकार से वंचित कर दिया गया था और यह सी का अभाव संविधान के अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन था।उठाए गए विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इस अदालत के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 के प्रावधानों के आलोक में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहास का विस्तृत अध्ययन करना आवश्यक पाया गया।अदालत ने कहा कि हालांकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का केंद्र मोहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज था जो 1920 तक एक शिक्षण संस्थान था, लेकिन उस कॉलेज का विश्वविद्यालय में रूपांतरण मुस्लिम अल्पसंख्यकों द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि यह 1920 के अधिनियम के आधार पर हुआ था जिसे तत्कालीन केंद्रीय विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था।चूंकि 1920 के अधिनियम तक कोई अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मौजूद नहीं था और चूंकि इसे केंद्रीय विधानमंडल के अधिनियम द्वारा अस्तित्व में लाया गया था, इसलिए न्यायालय ने यह मानने से इनकार कर दिया कि यह मुस्लिम अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित किया गया था।ई ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि इस दावे को सही ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय मुस्लिम अल्पसंख्यकों को जाता है और इसलिए, उन्हें अनुच्छेद 30 (1) के तहत गारंटीकृत निधि अधिकार के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रशासन करने का कोई अधिकार नहीं है।

अज़ीज़ बाशा के फैसले के कुछ साल बाद, इस अदालत के पास अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा करने वाली एक प्राचीन संस्था की प्रकृति को निर्धारित करने के लिए एक और एफ. एल. एल. अवसर था।एस. के. पात्रो बनाम में निर्णय की सूचना दी गई है।बिहार राज्य।[1970] 1 एस. सी. आर. 172 चूंकि यह मामले के निकट समानांतर प्रतीत होता है, इसलिए इसमें उठाए गए प्रतिद्वंद्वी विवादों पर विचार करना उपयोगी होगा।वहाँ शिक्षा विभाग ने सी. एम. एस. स्कूल को निर्देश दिया कि

प्रबंध समिति का पुनर्गठन किया गया और उस निर्देश को जी पटना उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी गई कि स्कूल एक ईसाई अल्पसंख्यक संस्थान था और राज्य के हस्तक्षेप के बिना अपना प्रबंधन निकाय रखने का हकदार था।उच्च न्यायालय ने संस्थान के उस दावे को स्वीकार नहीं किया और अपने निष्कर्ष को पूरा किया:

" याचिका या जवाब में दिए गए हलफनामे में कहीं भी एच. 154 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [1991] का समर्थन नहीं किया गया है।

3 एस सी आर।

याचिकाकर्ताओं द्वारा कि स्कूल खोला गया था, शुरू किया गया था, स्थापित किया गया था या

क.

अस्तित्व में लाया गया, और इस प्रकार भारतीय चर्च द्वारा स्थापित किया गया।आश्चर्य की बात यह है कि वर्तमान स्वामित्व और प्रशासन के संबंध में भी, याचिकाकर्ताओं द्वारा कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि यह भारतीय नागरिकों का ईसाई अल्पसंख्यक है जो संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अपने स्कूल की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।याचिकाकर्ताओं का यह मामला कहीं भी नहीं है कि भारतीय ईसाई चर्च मिशनरी सोसाइटी, लंदन के सदस्य थे, या भारत में रहने वाले या अधिवासित क्रिस टियन का शैक्षणिक संस्थान की स्थापना में कोई हाथ था। ऐसी स्थिति में यह अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहे हैं कि सी. एम. एस. स्कूल की स्थापना अल्पसंख्यकों द्वारा की गई थी, जो इसके हकदार हैं -

ग

संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षण।

उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि अनुच्छेद 30 में 'अल्पसंख्यक' शब्द का अर्थ विश्व की आबादी के संदर्भ में अल्पसंख्यक नहीं है, बल्कि भारतीय नागरिकों की आबादी के संदर्भ में है।यदि धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक होने का दावा करने वाले भारत में रहने वाले विदेशी किसी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन करना चाहते हैं, तो वे अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि अनुच्छेद 30 का लाभ भारतीय मूल के व्यक्तियों तक ही सीमित था।यह ध्यान दिया गया कि यह विद्यालय 1854 में चर्च मिशनरी सोसाइटी, लंदन द्वारा शुरू किया गया था और ऐसी सोसायटी को भारत का नागरिक नहीं कहा जा सकता था और किसी भी स्थिति में समाज का गठन करने वाले व्यक्ति विदेशी होने के कारण, उनके द्वारा स्थापित सी. एम. एस. स्कूल को अनुच्छेद 30 (1) के ई का लाभ नहीं मिल सका।

अपील पर, उच्च न्यायालय के फैसले को इस न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से दो आधारों पर उलट दिया गया थाः(i) उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य के उस हिस्से पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जो उनके इस दावे को सही ठहराने के लिए पर्याप्त था कि स्थानीय नागरिकों ने प्रतिष्ठान में भाग लिया था।

च

(ii) भारतीय नागरिकता अनुच्छेद 30 के लागू होने की शर्त नहीं होने के कारण, उसके तहत संरक्षण से उस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता था।पहले आधार के संबंध में, न्यायालय ने अभिलेख पर सामग्री की जांच की और यह साबित करने के लिए पर्याप्त पाया कि भागलपुर के स्थानीय ईसाइयों ने स्कूल की स्थापना और रखरखाव में अग्रणी भूमिका निभाई थी।भागलपुर में चर्च मिशनरी एसोसिएशन की रिकॉर्ड बुक जी, भागलपुर में कलकत्ता पत्राचार समिति (चर्च मिशनरी सोसाइटी) द्वारा चर्च मिशनरी सोसाइटी को लिखे गए पत्रों की प्रतियां, आयोजित बैठकों के कार्यवृत्त और भागलपुर की स्थानीय परिषद द्वारा पारित प्रस्तावों पर निष्कर्ष के समर्थन में भरोसा किया गया था।यह भी पाया गया कि संस्था के प्रकाशन के लिए सहायता चर्च एच मिशनरी सोसाइटी, लंदन सहित अन्य निकायों से प्राप्त की गई थी।इस सामग्री पर, यह माना गया था कि स्कूल एसटी था।

स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय (शेट्टी, जे.) 155

एल.

ए के साथ ईसाई मिशनरियों और भागलपुर के स्थानीय निवासियों द्वारा स्थापित

धन की सहायता जिसका एक हिस्सा उनके द्वारा योगदान किया गया था।दूसरे मैदान पर

' इस न्यायालय ने (17 9 पर) टिप्पणी कीः

" यह जांच करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या 1854 में इस विद्यालय की स्थापना में भाग लेने वाले सभी व्यक्ति 'भारतीय नागरिक' थे।संविधान के अधिनियमन से पहले भारतीय नागरिकता की कोई निश्चित अवधारणा नहीं थी, और यह नहीं कहा जा सकता है कि ईसाई मिशनरी जो भारत में बस गए थे और भागलपुर के स्थानीय ईसाई निवासियों ने अल्पसंख्यक समुदाय नहीं बनाया था।यह सच है कि अनुच्छेद 30 (1) के संरक्षण का दावा करने के लिए सक्षम अल्पसंख्यक और इस कारण से अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का विशेषाधिकार भारत में रहने वाले व्यक्तियों के लिए एक समान अधिकार होना चाहिए।यह प्रदान नहीं करता है

भारत में न रहने वाले विदेशियों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है।शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने वाले व्यक्तियों को भारत का निवासी होना चाहिए और उन्हें एक अच्छी तरह से परिभाषित धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक होना चाहिए।हालाँकि, यह भविष्यवाणी नहीं की गई है कि अनुच्छेद 30 के तहत गारंटीकृत अधिकार का संरक्षण केवल संविधान के समक्ष स्थापित संस्था के संबंध में प्राप्त किया जा सकता है।

डी.

ब्रिटिश भारत में पैदा हुए और रहने वाले व्यक्तियों द्वारा।

XXXXX

XXXXX

XXXXX

" अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अधिकार की गारंटी देता हैःअनुच्छेद स्पष्ट रूप से सदस्यों के लिए योग्यता के रूप में नागरिकता का उल्लेख नहीं करता है

अल्पसंख्यक "।

और बाद में (180 पर):

च

" हम उच्च न्यायालय से भी सहमत नहीं हैं कि चर्च मिशनरी सोसाइटी उच्च माध्यमिक विद्यालय के संबंध में अनुच्छेद 30 (1) के तहत किसी भी सुरक्षा का दावा करने से पहले यह साबित करना आवश्यक था कि संस्थान की स्थापना करने वाले सभी व्यक्ति या उनमें से अधिकांश वर्ष 1854 में 'भारतीय नागरिक' थे।वर्ष 1854 में ब्रिटिश साम्राज्य के नागरिक जी जहाज से स्वतंत्र रूप से कोई भारतीय नागरिकता नहीं होने के कारण, एक अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित संस्थान के संबंध में अनुच्छेद 30 की व्याख्या में इस शर्त को शामिल किया जाना चाहिए कि यह उन व्यक्तियों द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्होंने संविधान के बाद इस संस्थान की स्थापना करने का दावा किया है, तो भारतीय नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा।

अनुच्छेद 30 के संरक्षण को इस तरह से कम करना जो संविधान के एच प्रावधानों द्वारा आवश्यक नहीं है।

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

ई 156

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अब तक, प्रश्नों पर काफी प्रचुर मात्रा में मामला कानून है

क.

" अल्पसंख्यक ", अल्पसंख्यक का" स्थापित "करने का अधिकार, और शैक्षणिक संस्थानों को" प्रशासित "करने का उनका अधिकार।ये सवाल पूरे देश में विभिन्न संस्थानों के संबंध में उठे हैं।वे ईसाइयों, मुसलमानों और हिंदुओं के कुछ संप्रदायों और भाषाई समूहों के संबंध में उत्पन्न हुए हैं।कुछ मामलों में न्यायालयों ने बी दावेदार के इस कथन को बिना अधिक जांच के स्वीकार कर लिया है कि विचाराधीन संस्थान की स्थापना एक अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा की गई थी, जबकि कुछ मामलों में न्यायालयों ने संस्थान की स्थापना के प्रमाण की बहुत बारीकी से जांच की है।यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अनुच्छेद 30 (1) में उपयोग किए गए "स्थापित" और "प्रशासित" शब्दों को संयुक्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए।अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा शैक्षणिक संस्थान के प्रशासन का दावा किया गया अधिकार संस्थान की स्थापना के प्रमाण पर निर्भर करता है।संस्थान की स्थापना का प्रमाण सी, इस प्रकार संस्थान को प्रशासित करने के अधिकार का दावा करने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है।भारत के संविधान के प्रारंभ से पहले, भारतीय नागरिकता की कोई निश्चित अवधारणा नहीं थी।हालाँकि, इस न्यायालय ने दोहराया कि संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के संरक्षण का दावा करने के लिए सक्षम अल्पसंख्यक, और उस कारण से अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का विशेषाधिकार, भारत में रहने वाले व्यक्तियों का एक डी अल्पसंख्यक होना चाहिए।उन्होंने एक अच्छी तरह से परिभाषित धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक का गठन किया होगा।यह विदेशी मिशनरी या संस्था के अधिकारों की परिकल्पना नहीं करता है, हालांकि, उनके उद्देश्य प्रशंसनीय हो सकते हैं।संविधान के बाद, अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों का मतलब अनिवार्य रूप से वे लोग होने चाहिए जो भारत के नागरिकों का एक विशिष्ट और पहचान योग्य समूह बनाते हैं।चाहे वह "पुराना सामान" हो या "नया उत्पाद", संस्थान का उद्देश्य वास्तविक होना चाहिए, न कि

ई.

उपकरण या संदिग्ध।नियोजित साधनों और वांछित उद्देश्यों के बीच संबंध होना चाहिए।जैसा कि A.P.Christian एजुकेशनल सोसाइटी केस [1986] 2 SCR 749 में बताया गया है कि शैक्षणिक संस्थान को धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ पहचान करने में सक्षम बनाने के लिए कुछ सकारात्मक सूचकांक मौजूद होना चाहिए।अनुच्छेद 30 (1) केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए एक सुरक्षात्मक उपाय है और यह पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है कि कोई भी बीमार नहीं है।

च

उपयुक्त या छिपी हुई संस्था को संवैधानिक संरक्षण से दूर रहना चाहिए।

इन प्रारंभिक टिप्पणियों के साथ, अब हम पक्षों द्वारा की गई प्रस्तुतियों के आलोक में सेंट स्टीफन कॉलेज के दावे की जांच कर सकते हैं।जी प्रथम प्रश्न

सेंट का मूल और उद्देश्य।स्टीफन कॉलेज आश्चर्य की बात है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने याचिका में कॉलेज के अल्पसंख्यक चरित्र को न तो नकार दिया है और न ही स्वीकार किया है।लेकिन वकील ने

एच विश्वविद्यालय के पास बहस करने के लिए कई चीजें हैं जिन पर वर्तमान में विचार किया जाएगा।

एसटी.स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय (SHETTY, J.) 157 श्री गुप्ता, याचिकाकर्ता के वकील ने टी. सी. संख्या 3/1980 में विशेष रूप से ए से आग्रह किया है कि कॉलेज की स्थापना भारतीय निवासियों द्वारा नहीं, बल्कि कैम्ब्रिज के विदेशी मिशन द्वारा की गई थी और इसलिए, यह इसके लाभ का दावा करने का हकदार नहीं है।

अनुच्छेद 30 (1)।काउंटर से-डॉ. जे. एच. हाला द्वारा दायर हलफनामा-प्राचार्य

7

डब्ल्यू. पी. सं. में महाविद्यालय का।13213-14 1984 के और "द हिस्ट्री ऑफ द कॉलेज" के प्रकाशन से निम्नलिखित तथ्य और परिस्थितियाँ हो सकती हैं -

नोट किया:कॉलेज की स्थापना 1881 में दिल्ली में बी द कैम्ब्रिज मिशन द्वारा सोसाइटी फॉर द प्रोपा गेशन ऑफ द गॉस्पेल (एस. पी. जी.) के सहयोग से एक ईसाई मिशनरी कॉलेज के रूप में की गई थी, जिसके सदस्य भारत में निवासी थे।इस महाविद्यालय की स्थापना ईसाई धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी और

ईसाई छात्रों के साथ-साथ अन्य लोगों के लिए ईसाई मूल्यों पर आधारित शिक्षा जो उक्त शिक्षा का विकल्प चुन सकते हैं।दिल्ली में क्रिश्चियन कॉलेज की स्थापना की योजना के साथ कैम्ब्रिज ब्रदरहुड ने कैम्ब्रिज मिशन भेजा जिसके सदस्य थे:रेव. जे. डी. मुर्रे, रेव. ई. बिकार्स्टेथ, रेव. जी. ए. लाफ्रॉय, रेव. एच. टी. ब्लैकेट, रेव. एच. सी. कार्लियन और रेव. एस. एस. एलनट।कैम्ब्रिज मिशन के उक्त सदस्यों में से रेव. ऑलनट, रेव. ब्लैकेट और रेव. लेफ्रॉय ने कॉलेज की स्थापना के लिए एसपीजी के रेव. आर. आर. विंटर के साथ मिलकर काम किया।यह देखा जाएगा कि अकेले कैम्ब्रिज मिशन ने कॉलेज की स्थापना नहीं की।कैम्ब्रिज मिशन ने भारत में रहने वाले एस. पी. जी. के सदस्यों की सहायता से कॉलेज की स्थापना की।इसलिए, 1980 की टी. सी. संख्या 3 में याचिकाकर्ता के वकील श्री गुप्ता द्वारा इसके विपरीत आग्रह किया गया तर्क गलत है।कॉलेज शुरू करने का उद्देश्य कैम्ब्रिज ब्रदरहुड को 1878 की रिपोर्ट से देखा जा सकता है और इसमें कहा गया है कि "सेंट स्टीफंस मिशन स्कूल छोड़ने के बाद छात्र गैर-ईसाई कॉलेजों में शामिल हो गए और ईसाई ई के साथ संपर्क खो दिया।

शिक्षा. मामला अन्यथा होता अगर हम उन्हें अपने स्कूल से एक कॉलेज में भेजने में सक्षम होते, जहाँ ईसाई प्रोफेसरों द्वारा शिक्षा दी जाती और ईसाई विचारों के साथ व्याप्त होती।(ए हिस्ट्री ऑफ सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली कलकत्ता, 1935 में एफ. एफ. मोंकपी. 3)।अक्टूबर 1879 में कैम्ब्रिज समिति ने निर्देश देने की इच्छा भी व्यक्त की।

धर्मनिरपेक्ष विषयों में "।यह भी महसूस किया गया कि मिशनरियों का प्रभाव एफ

यदि वे कुछ धर्मनिरपेक्ष विषयों में कक्षाएं आयोजित करते थे और उनकी शिक्षाओं को सख्त धार्मिक शिक्षा के अनुरूप नहीं बनाते थे तो इसमें बहुत वृद्धि होगी।(आई. बी. आई. पी. 5)

निर्माण

मूल रूप से, कॉलेज की इमारत किराए के परिसर में रखी गई थी जिसके लिए भुगतान किया गया था।

एसपीजी द्वारा।अंततः सोसाइटी फॉर द जी प्रोपेगेशन ऑफ गॉस्पेल द्वारा एक नई इमारत का निर्माण किया गया, जिसकी आधारशिला निम्नलिखित थी:

शिलालेख:

ईश्वर की महिमा के लिए

और ध्वनि की उन्नति

एच.

सीखना

और धार्मिक शिक्षा 158

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कॉलेज का नया भवन अंततः 8 दिसंबर को खोला गया था।

क.

बेर, 1881, रेव. एलनट द्वारा।बरामदे के सामने उक्त इमारत पर, पैरापेट के शीर्ष पर, बेस-रिलीफ में एक 'क्रॉस' रखा गया था और तुरंत ब्रैकेट के नीचे 'अद देई ग्लोरियम' शब्द उत्कीर्ण किए गए थे जोः

तब से इसे कॉलेज मोटो के रूप में अपनाया गया है।

आज विश्वविद्यालय परिसर में कॉलेज की नई इमारत भी बहुत बड़ी है।

' मुख्य मीनार के शीर्ष पर और सामने के बरामदे में 'क्रॉस' पर सेंट स्टीफंस मोटो 'एड देई ग्लोरियम' अंकित है जो छात्रों को कॉलेज के उद्देश्य और उद्देश्य, अर्थात् 'द ग्लोरी ऑफ गॉड' को कायम रखने और याद दिलाने के लिए है।कॉलेज परिसर में एक चैपल भी है जहाँ सुबह धार्मिक सभा के लिए ईसाई सुसमाचार में धार्मिक निर्देश सी दिया जाता है।इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि 1881 में अपनी स्थापना के बाद से, सेंट स्टीफन कॉलेज ने स्पष्ट रूप से अपने ईसाई चरित्र को बनाए रखा है और यह होगा

इसके नाम, प्रतीक, मोटो, एक चैपल की स्थापना और धार्मिक सभा के लिए ईसाई सुसमाचार में इसके धार्मिक निर्देश से स्पष्ट है। ये

डी.

वे विवाद के दायरे से परे हैं।

महाविद्यालय का गठन

ऐसा कहा जाता है कि कॉलेज के इतिहास के शुरुआती दौर में इसका प्रबंधन किया गया था।

0

मिशन परिषद द्वारा-एक पूरी तरह से ईसाई निकाय।1913 के अंत में यह था

ई एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत था और 6 नवंबर, 1913 को एक संविधान तैयार किया गया था जिसे एस. पी. जी. स्थायी समिति और कैम्ब्रिज समिति द्वारा अपनाया गया था।संविधान आज भी अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान के रूप में इसे प्रशासित करने के अधिकार से समझौता किए बिना एक ईसाई कॉलेज के रूप में कॉलेज के आवश्यक चरित्र को बनाए रखता है। महाविद्यालय के संविधान में सोसायटी का ज्ञापन और नियम शामिल हैं।का खंड 2

च

ज्ञापन में कहा गया है कि "इसका उद्देश्य कॉलेज के छात्रों को विश्वविद्यालय की डिग्री और परीक्षाओं के लिए तैयार करना और ईसाई धर्म के सिद्धांतों में निर्देश देना है जो निर्देश चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की शिक्षाओं के अनुसार होना चाहिए।"खंड 4 सोसायटी के मूल सदस्यों को निर्धारित करता है जो ज्यादातर ईसाई थे।सोसायटी की संरचना इसके जी ईसाई चरित्र को भी दर्शाती है जितना कि दिल्ली के बिशप के बिशप सोसाइटी के अध्यक्ष हैं [नियम 1 (ए)]:इसके अलावा, दिल्ली डायोसिस के बिशप द्वारा नियुक्त दो व्यक्ति, जिनमें से एक डायोसिस का वरिष्ठ प्रेस्बिटेरियन होगा, सोसाइटी [नियम 1 (बी)] के सदस्य होंगे।चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सिनोडिकल बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति भी सोसायटी (नियम 1 (जी)) का सदस्य होगा।डायोसेसन बोर्ड ऑफ एजुकेशन [नियम 1 (एच)] द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एच व्यक्ति की स्थिति भी ऐसी ही है।

दो एसटी।स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय (शेट्टी, जे.) 159 व्यक्तियों की नियुक्ति डायोसिस की कार्यकारी समिति द्वारा की जाएगी, जो ए.

आर एक्स

जो प्रेस्बिटेरियन होगा, वह भी सोसायटी [नियम 1 (i)] का सदस्य होगा।समाज की संरचना, इसलिए, एक बड़ी उपस्थिति का संकेत देती है

इस पर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के ईसाई सदस्यों की संख्या है।

प्रबंधन

महाविद्यालय के प्रबंधन की देखरेख सर्वोच्च परिषद और शासी निकाय द्वारा की जा रही है।सर्वोच्च परिषद में कुछ शामिल हैं -

समाज के सदस्य, जिनमें से सभी उत्तर भारत के चर्च या उसके साथ किसी अन्य चर्च के सदस्य होने चाहिए, या किसी अन्य विधिवत सदस्य होने चाहिए।

ईसाई चर्च का गठन किया।वे इस प्रकार हैंः

एस.

(क) दिल्ली डायोसिस के बिशप, जो अध्यक्ष होंगे।(ख) डायोसिस के बिशप द्वारा नियुक्त दो व्यक्ति (के तहत)

नियम 1-बी)।

(ग) चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सिनोडिकल डी द्वारा नियुक्त व्यक्ति

उच्च शिक्षा बोर्ड (नियम 1-जी के तहत)।

(घ) डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन द्वारा नियुक्त व्यक्ति (नियम 1-एच के तहत)।

(ङ) महाविद्यालय के प्राचार्य (सदस्य-सचिव)।सोसायटी के नियम 3 में प्रावधान है कि सर्वोच्च परिषद ज्यादातर छात्रों को धार्मिक और नैतिक शिक्षा और कॉलेज के धार्मिक चरित्र को प्रभावित करने वाले मामलों की देखभाल करती है।महाविद्यालय के प्राचार्य सर्वोच्च परिषद के सदस्य सचिव हैं।नियम 4 में प्रावधान है कि प्राचार्य एफ होगा

उत्तर भारत के चर्च या भारत के चर्च के साथ सहभागिता रखने वाले चर्च का सदस्य।उप-प्राचार्य की नियुक्ति प्रतिवर्ष प्राचार्य द्वारा की जाती है।वह चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया या किसी अन्य चर्च का भी सदस्य होगा।

उसके साथ सहभागिता में अन्य चर्च।

यह सच है कि नियम 5 में यह प्रावधान है कि कॉलेज के प्रशासन पर कॉलेज की सर्वोच्च परिषद का कोई जी अधिकार क्षेत्र नहीं है और इसकी देखभाल शासी निकाय द्वारा की जाएगी।लेकिन शासी निकाय एक धर्मनिरपेक्ष निकाय नहीं है जैसा कि विश्वविद्यालय के विद्वान वकील ने तर्क दिया है।नियम 6 में कहा गया है कि

सोसायटी के अध्यक्ष (बिशप ऑफ डायोसिस ऑफ दिल्ली) शासी निकाय के अध्यक्ष होंगे।खण्ड (1) की श्रेणियों ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, 1 और एम में निर्धारित समाज के सदस्य एच के सदस्य होंगे।

एक शासी निकाय।शासी निकाय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के सदस्य होंगे।खंड (1) में श्रेणियों (ए) से (एम) में से केवल श्रेणी (के) शिक्षण कर्मचारियों का सदस्य हो सकता है जो ईसाई नहीं हो सकता है।दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा श्रेणी (1) के तहत नियुक्त किए जाने वाले दो सदस्य ईसाई नहीं हो सकते हैं और इसी तरह, श्रेणी (एन) के तहत ईसाई नहीं हो सकते हैं।लेकिन शेष सदस्य बी ईसाई होंगे।तेरह श्रेणियों में से केवल तीन श्रेणियां गैर-ईसाई हो सकती हैं और इसलिए, इससे

कॉलेज के शासी निकाय के ईसाई चरित्र में बहुत कम अंतर पड़ता है।कैलेंडर खंड I के पृष्ठ 127-128 पर दिल्ली विश्वविद्यालय के क़ानून 30 (c) की तुलना से अंतर पता चलेगा।

सेंट स्टीफन कॉलेज के विपरीत क़ानून के तहत अन्य कॉलेजों के शासी निकाय के बीच।

एस.

मौलिक विधि के बीच के अंतर को ध्यान में रखना फिर से महत्वपूर्ण है

सेंट स्टीफन कॉलेज और अन्य सभी कॉलेजों के प्राचार्य की नियुक्ति।सेंट स्टीफन कॉलेज के प्राचार्य की नियुक्ति सुप्रीम काउंसिल द्वारा की जाती है।

डी और वह चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया (नियम 4) से संबंधित एक ईसाई होना चाहिए।वह नियंत्रण का प्रयोग करेगा, और कॉलेज के अनुशासन और विनियमन को बनाए रखेगा।वह प्रवेश समिति की सहायता से महाविद्यालय में प्रवेश के पूर्ण प्रभारी होंगे।लेकिन अध्यादेश XVIII खंड 7 (2) [पृष्ठ 335 कैलेंडर खंड I] के तहत अन्य संबद्ध कॉलेजों के प्राचार्यों की नियुक्ति कॉलेज के शासी निकाय द्वारा की जानी है।

ई.

महाविद्यालय की अचल संपत्ति भारतीय में निहित होगी।

चर्च न्यासी, जो केवल न्यासी के रूप में कार्य करेंगे, और उनके पास प्रबंधन की कोई शक्ति नहीं होगी।महाविद्यालय से जुड़ी अन्य सभी संपत्ति सोसायटी (नियम 21) में निहित होगी।

च

दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम और संगठन यह तर्क दिया गया कि सेंट स्टीफन कॉलेज ने दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध होने के बाद अपना अल्पसंख्यक चरित्र खो दिया है।यह तर्क दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम और बनाए गए अध्यादेशों के कुछ प्रावधानों पर आधारित था

जी इसके तहत।यह कहा जाता था कि छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाता है न कि कॉलेज में।लेकिन हमें विवाद में कोई सार नहीं मिलता है।सबसे पहले, यह कहा जा सकता है कि राज्य या राज्य का कोई भी साधन अनिवार्य संबद्धता द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित संस्थान के चरित्र को वंचित नहीं कर सकता है क्योंकि अनुच्छेद 30 (1) अल्पसंख्यकों के लिए अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने का एक विशेष अधिकार है।अल्पसंख्यक संस्थान के पास एच की एक विशिष्ट पहचान है और इस तरह की पहचान को जारी रखते हुए प्रशासन करने का अधिकार है।

LI ST.स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय [शेट्टी, जे.] 161 को दंडात्मक कार्रवाई द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस तरह की कोई भी दंडात्मक कार्रवाई संवैधानिक गारंटी के विपरीत होने के कारण अमान्य होगी।प्रशासन का अधिकार संस्था के कार्यों के संचालन और प्रबंधन का अधिकार है।इस अधिकार का प्रयोग व्यक्तियों के एक समूह द्वारा किया जाता है जिसमें संस्थापकों को विश्वास और विश्वास होता है।यदि अधिकार को मान्यता और बनाए रखना है तो संस्थान के ऐसे प्रबंधन निकाय को विस्थापित या पुनर्गठित नहीं किया जा सकता है।हालाँकि, उचित विनियम अनुमत हैं, लेकिन विनियम नियामक प्रकृति के होने चाहिए और अनुच्छेद 30 (1) के तहत गारंटीकृत अधिकार के संक्षिप्त-बी के नहीं होने चाहिए।

दूसरा, हम दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं पाते हैं।

महाविद्यालय के प्रबंधन को प्रयोग करने से रोकने वाली प्रबल शक्तियाँ

एक अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में महाविद्यालय का प्रशासन करने का अधिकार।दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 2 (ए) 'कॉलेज' को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है 'विश्वविद्यालय द्वारा अपने विशेषाधिकार के लिए बनाए रखा गया संस्थान या सी और इसमें एक संबद्ध कॉलेज और एक संविधान महाविद्यालय शामिल है'।धारा 4 के तहत, विश्वविद्यालय के पास परीक्षा आयोजित करने और विश्वविद्यालय या किसी भी कॉलेज में अध्ययन के पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को डिग्री और अन्य शैक्षणिक सम्मान प्रदान करने की शक्तियां हैं।धारा 6 में प्रावधान है कि विश्वविद्यालय किसी भी लिंग और किसी भी जाति,

पंथ, जाति या वर्ग के सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा।धारा 7 डी के तहत यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालय के संबंध में सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण

{ 1

पाठ्यक्रमों का संचालन शैक्षणिक परिषद के नियंत्रण में किया जाएगा।धारा 23 द्वारा, शैक्षणिक परिषद का गठन विश्वविद्यालय के शैक्षणिक निकाय के रूप में किया गया है, और यह अधिनियम, क़ानून और अध्यादेश के प्रावधानों के अधीन, नियंत्रण और सामान्य विनियमन के लिए जिम्मेदार होगा, और ई. आई. के लिए जिम्मेदार होगा।

शिक्षा आदि के मानकों का रखरखाव।

धारा 30 अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है जो प्रदान कर सकती है

$

विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश और उनके नामांकन के लिए प्रक्रिया।अध्यादेश 1. प्रवेश के लिए योग्यता निर्धारित करता है। अध्यादेश 1 के खंड 4 में कहा गया है कि अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार एफ

उस संबंध में बनाए गए नियमों और शर्तों को पूरा करना होगा।

अध्यादेश II में प्रवेश समितियों के गठन का प्रावधान है और

विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रक्रिया।इस अध्यादेश का खंड 2 (ii) है -

महत्वपूर्ण और अब तक प्रासंगिक इस प्रकार हैः

जी.

" प्रवेश/पंजीकरण के लिए आवेदन पूर्व में किया जाएगा।

लिखित रूप।प्रवेश के इच्छुक छात्रों द्वारा आवेदन

कला, गणितीय विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संगीत और विज्ञान संकायों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संबंधित संकायों के डीन को सीधे भेजे जाएंगे।एच पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन

}

एल #}

ऊपर उल्लिखित लोगों के अलावा, के प्रधानाचार्या को भेजा जाएगा

क.

संबंधित महाविद्यालय "।

XXXXX

XXXXX

XXXXX

अध्यादेश II का खंड (3) समान रूप से प्रासंगिक है और इसमें निम्नलिखित प्रावधान हैं:

" संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों और संकायों के डीन द्वारा प्रवेश को अंतिम रूप दिया जाएगा, जैसा भी मामला हो, ऐसी अंतिम तिथि से बाद में नहीं जो शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित की जाए।

समय-समय पर।

48 7

बशर्ते कि कुलाधिपति, अपने विवेकाधिकार पर, प्रत्येक अपवादात्मक कारणों से, जैसे कि परिणामों की देर से घोषणा या ऐसे अन्य कारणों से जो कुलाधिपति द्वारा संतोषजनक माने जाते हैं, प्रत्येक मामले में उनके द्वारा उचित समझी जाने वाली तारीखों तक, उपरोक्त निर्धारित तिथि के बाद किसी भी पाठ्यक्रम में विज्ञापन भेजने की अनुमति दे सकता है:

डी.

बशर्ते कि प्रत्येक वर्ष शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित की जाने वाली तारीख से पहले किसी कॉलेज द्वारा कोई प्रवेश नहीं किया जाएगा:XXXXX

XXXXX

XXXXX

ई.

अध्यादेश XVIII खंड 6-ए (1) में प्रावधान है कि प्रत्येक महाविद्यालय में एक कर्मचारी परिषद होगी।अधिनियम, कानून और विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के प्रावधानों के अधीन, कर्मचारी परिषद अन्य मामलों के साथ-साथ संगठित करने के संबंध में निर्णय लेगी।

छात्रों का प्रवेश "।

च

अधिनियम और अध्यादेशों के इन और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों से, हमें सामान्य योजना या अन्य विशिष्ट प्रावधानों में ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है जो हमें यह कहने में सक्षम बनाए कि कॉलेज कानूनी रूप से अपने अल्पसंख्यक चरित्र को बनाए रखने से वंचित है।कि ऑनर्स पाठ्यक्रमों सहित डिग्री पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश के मामलों में,

जी उम्मीदवारों को अपनी पसंद के कॉलेज में आवेदन करना होता है न कि विश्वविद्यालय में और यह निर्णय लेने और अंतिम प्रवेश करने के लिए संबंधित कॉलेज के प्राचार्य या संकायों के डीन के लिए होता है।इसलिए, यह कहना गलत है कि कॉलेज में कोई प्रवेश नहीं है, बल्कि केवल विश्वविद्यालय के लिए है।स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया निश्चित रूप से अलग है, लेकिन हम इन मामलों में उस मामले से चिंतित नहीं हैं।

एच एस टी।स्टीफंस कॉलेज वी।यह ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि ए कॉलेज सोसाइटी के नियमों के नियम (8) के तहत प्रबंधन ने विश्वविद्यालय के संबंधित कानूनों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा निर्धारित शासी निकायों की संरचना, कॉलेजों के प्रबंधन, प्राचार्यों की नियुक्ति आदि से संबंधित सभी नियमों और विनियमों को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन केवल ऐसे निर्देशों को स्वीकार करने के अपने अधिकार सुरक्षित रखे हैं जो इसके संविधान के विपरीत नहीं हैं, और जिन्हें उसने कॉलेज के बेहतर प्रबंधन और कॉलेज के सुधार के लिए उपयुक्त पाया है।

शैक्षणिक मानक।महाविद्यालय का गठन एक स्वायत्त और स्वायत्त संस्थान के रूप में किया गया है।इसने अपने स्वयं के शासी निकाय को चुनने और अपने स्वयं के प्राचार्य का चयन करने और नियुक्त करने के अधिकार को संरक्षित किया है, दोनों का संस्थान के अल्पसंख्यक चरित्र को बनाए रखने के लिए एक बड़ा योगदान कारक है।यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि कॉलेज के संविधान को दिल्ली प्रांत के संयुक्त स्टॉक कंपनियों के पंजीयक के साथ-साथ दिल्ली विश्वविद्यालय सी में भी विधिवत पंजीकृत किया गया है।यह विवादित नहीं है कि विश्वविद्यालय ने किसी भी स्तर पर कॉलेज के संविधान के किसी भी प्रावधान के बारे में

कोई आपत्ति नहीं जताई है।इन तथ्यों और परिस्थितियों से यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि सेंट स्टीफन कॉलेज की स्थापना और प्रशासन एक अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा किया गया था।, ईसाई समुदाय जो निर्विवाद रूप से भारत के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में एक धार्मिक अल्पसंख्यक है जहाँ कॉलेज स्थित है।दूसरा प्रश्न

क्या सेंट स्टीफंस कॉलेज अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में 5 जून, 1980 और 9 जून, 1980 के विश्वविद्यालय के परिपत्रों से बंधा था?

ई [1]

विश्वविद्यालय के 5 जून, 1980 के पहले परिपत्र में प्रवेश के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।9 जून, 1980 के दूसरे परिपत्र द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों को निर्देश दिया गया था कि वे केवल योग्यता परीक्षाओं में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर निर्धारित योग्यता के आधार पर छात्र को प्रवेश दें।पहला बामा वृत्ताकार F

स्वयं शिकायत नहीं की जा सकती थी, लेकिन यह दूसरे परिपत्र के निर्देश से बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है।यदि आवेदनों की प्राप्ति के लिए पहले परिपत्र में निर्धारित अंतिम तिथि का पालन किया गया था, तो कॉलेज अपने स्वयं के प्रवेश कार्यक्रम का पालन करके आवेदकों का चयन नहीं कर सकता था।यह कॉलेज का मामला है कि यह 100 से अधिक वर्षों से अपने स्वयं के प्रवेश कार्यक्रम का पालन कर रहा है और वर्षों से इसने कई जी विशिष्ट गतिविधियों में एक कॉर्पोरेट छवि का निर्माण किया है। महाविद्यालय का प्रवेश कार्यक्रम एक बन गया है

संस्थान की उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण साधन और यह प्रशासन का हिस्सा है जिसे कॉलेज अल्पसंख्यक के रूप में रखने का हकदार है।

संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत संस्था।विश्वविद्यालय महाविद्यालय के कुप्रशासन के प्रमाण के अभाव में महाविद्यालय को अपने प्रवेश कार्यक्रम को समाप्त करने का निर्देश नहीं दे सकता है।परिपत्रों को एच. 164 में भी चुनौती दी गई है।

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए इस आधार पर कि वे प्रकृति में नियामक नहीं हैं।ऐसा कहा जाता है कि यदि छात्रों को विशुद्ध रूप से योग्यता परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जाता है तो किसी भी ईसाई छात्र के लिए प्रवेश प्राप्त करना संभव नहीं होगा।यह पाया गया है कि जब तक रियायत नहीं दी जाती, तब तक ईसाई छात्रों को विचार के दायरे में नहीं लाया जा सकता है।अन्य आवेदकों की तुलना में उनमें आम तौर पर एम. सी. आर. टी. की कमी होती है।

क.

एसटी का प्रवेश कार्यक्रम।स्टीफन कॉलेज

अध्ययन के प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए आवेदनों को प्रवेश के शिक्षक की प्रत्यक्ष देखरेख में क्रमबद्ध किया जाता है, और फिर संबंधित विभाग के दो शिक्षकों को जांच के लिए भेजा जाता है।इन आवेदनों की आगे उनकी अंतिम परीक्षा में छात्रों द्वारा लिए गए विषयों के संयोजन और उस पाठ्यक्रम के संबंध में उनके द्वारा इंगित वरीयता क्रम के संबंध में जांच की जाती है जिसमें उनके द्वारा प्रवेश मांगा जाता है।इस स्तर पर विभिन्न विषयों के संयोजन के लिए विभागों द्वारा दिए गए कट ऑफ प्रतिशत के अनुसार, संबंधित विभाग के दो शिक्षक, जिनमें से एक विभाग का प्रमुख होता है और दूसरा विभाग का नामित होता है, एक सूची तैयार करते हैं -

डी.

"

संभावित उपयुक्त उम्मीदवार जो आम तौर पर 1 के आधार पर होते हैं:4 या 1:5 क्रमशः कला और विज्ञान के छात्रों के लिए। प्रत्येक विषय के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाए गए आवेदकों के नामों की सूची नोटिस बोर्ड पर अलग से उस तारीख और समय

के साथ रखी जाती है जिस पर उनका साक्षात्कार किया जाएगा।केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के बाहर रहने वालों को डाक द्वारा सूचित किया जाता है।आवेदक

साक्षात्कार के लिए चयनित व्यक्ति को एक चयन समिति के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है जिसमें आमतौर पर प्राचार्य, प्रवेश के लिए शिक्षक, संबंधित विभाग के दो सदस्य और खेल अध्यक्ष (संकाय का एक वरिष्ठ सदस्य) शामिल होते हैं।समिति के प्रत्येक सदस्य के पास साक्षात्कार के लिए आमंत्रित उम्मीदवारों की पूरी सूची होती है, जिसमें उनके कुल अंकों का प्रतिशत, व्यक्तिगत विषयों में प्राप्त अंक, खेल और पाठ्येतर गतिविधियों आदि में रुचि और प्रवीणता होती है। उम्मीदवार के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं

च

वर्तमान समस्याओं के बारे में उनकी सामान्य जागरूकता के साथ विषय।साक्षात्कार मौखिक रूप से आयोजित किया जाता है लेकिन यदि और जब आवश्यक हो, तो समस्याओं को लिखित रूप में हल करने के लिए दिया जाता है।प्रत्येक आवेदन पत्र में स्थान भी प्रदान किया गया है जहाँ आवेदक को अपनी रुचि, शौक, मूल्यों, कैरियर योजना आदि के बारे में लिखना आवश्यक है। जी विशेष पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता निर्धारित करते समय इसका सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाता है।समिति का प्रत्येक सदस्य उम्मीदवारों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है और अध्ययन के प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए साक्षात्कार के अंत में, सभी सदस्यों की राय को ध्यान में रखा जाता है और सर्वसम्मति से प्रवेश के लिए चुने गए उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार की जाती है।

ईसाई छात्रों और अन्य लोगों के लिए विचार

एच.

1

ईसाई छात्रों को 10 प्रतिशत तक की छूट दी जाती है।द शेड एसटी।

स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय (शेट्टी, जे.) 165 शासित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार जिनके पास न्यूनतम 50 प्रति ए है

मैट।

ऑनर्स पाठ्यक्रमों में चयन के लिए साक्षात्कार के लिए प्रतिशत अंकों को बुलाया जाता है।बी. ए. पास पाठ्यक्रम के लिए, उन्हें एक और रियायत दी जाती है और योग्यता अंकों को 50 प्रतिशत से भी कम कर दिया जाता है।जहां तक खिलाड़ियों और खेल महिलाओं का संबंध है, राष्ट्रीय या राज्य स्तर के खिलाड़ियों को आम तौर पर 10 प्रतिशत तक और असाधारण मामलों में 15 प्रतिशत या उससे भी अधिक रियायत दी जाती है।हालांकि, एक ईसाई छात्र, जो कट-ऑफ प्रतिशत से 10 प्रति बी से अधिक नीचे है

प्रतिशत को कभी भी साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाता है।

महाविद्यालय द्वारा दी गई रियायत का वास्तविक कार्यकरण और कई वर्षों में उस पर प्राप्त परिणाम 1980 के अनुलग्नक-I से लेखन याचिका संख्या 1868 में दिए गए हैं।जिन ईसाई छात्रों को 10 प्रतिशत तक की रियायत मिलती है और इस तरह उन्हें वरीयता प्राप्त प्रवेश मिलता है, वे केवल 6 प्रतिशत से 10 प्रतिशत हैं।उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार सी में भी प्रवेश दिया जाता है और जो भी मानक से नीचे आता है उसे कभी भी कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया गया है।दिल्ली विश्वविद्यालय और छात्र संघ की सामग्री

दिल्ली विश्वविद्यालय और छात्र संघ की ओर से विवादित डी परिपत्रों को कई आधारों पर उचित ठहराने की मांग की गई थी।प्रवेश के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि निर्धारित करने वाले पहले परिपत्र की मांग की गई थी।इस आधार पर उचित ठहराया गया कि इसका उद्देश्य एकरूपता सुनिश्चित करना था

सभी कॉलेजों में प्रवेश की तारीखें और यह उन छात्रों के लिए फायदेमंद होगा जो विभिन्न कॉलेजों में प्रवेश चाहते हैं।विश्वविद्यालय के दूसरे परिपत्र के संबंध में यह तर्क दिया गया था कि योग्यता परीक्षाओं में आवेदकों द्वारा प्राप्त अंकों द्वारा निर्धारित योग्यता के आधार पर प्रवेश चयन में मनमानेपन को बाहर कर देगा और सभी आवेदकों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करेगा।यह भी प्रस्तुत

किया गया था कि परिपत्र चरित्र में विनियामक हैं और एक अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में सेंट स्टीफन कॉलेज को अनुच्छेद 30 (1) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं।

च

अनुच्छेद 30 (1) प्रदान करता हैः

"30. शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार

जी.

(1) सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। प्रशासन-एच 166

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुच्छेद के तहत अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों का विवरण।30 (1) इसका अर्थ है 'संस्था के मामलों का प्रबंधन'।यह प्रबंधन नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए ताकि संस्थापक या उनके नामांकित व्यक्ति संस्थान को अपने विचार के अनुसार ढाल सकें और उनके विचारों के अनुसार कि सामान्य रूप से समुदाय और विशेष रूप से संस्थान के हितों की सर्वोत्तम सेवा कैसे की जाएगी।लेकिन शिक्षा के मानक प्रबंधन का हिस्सा नहीं हैं।3 मानक राजनीतिक निकाय से संबंधित हैं और देश और उसके लोगों के विचारों या प्रगति द्वारा शासित होते हैं।इस तरह के नियम सीधे प्रबंधन पर लागू नहीं होते हैं, हालांकि वे अप्रत्यक्ष रूप से इसे प्रभावित कर सकते हैं।इसलिए राज्य को शिक्षा के स्तर और संबंधित मामलों को विनियमित करने का अधिकार है।अल्पसंख्यक संस्थानों को मानकों से नीचे आने की अनुमति नहीं दी जा सकती

शैक्षणिक संस्थानों से अपेक्षित उत्कृष्टता।वे प्रबंधन के अनन्य अधिकार की आड़ में शिक्षा के सामान्य स्वरूप सी का पालन करने से इनकार नहीं कर सकते।जबकि प्रबंधन उन पर छोड़ दिया जाना चाहिए, वे दूसरों के साथ कदम रखने के लिए मजबूर हो सकते हैं।इन सिद्धांतों पर अधिकार का खजाना है।परिदृश्यःबॉम्बे राज्य बनाम।बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी, [1955] 1 एस. सी. आर. 568 रीःकेरल शिक्षा विधेयक 1957, [1959] एस. सी. आर. 995; सिद्धजभाई भाई बनाम।बॉम्बे राज्य [1963] 3 एस. सी. आर. 837; रेव. फादर प्रोस्ट और ओआरएस।वी.बिहार राज्य, [1969] 2 एससीआर डी 73 और केरल राज्य बनाम।मदर प्रोविंशियल, [1971] 1 एससीआर 734।

(

1 यद्यपि अनुच्छेद 30 (1) संविधान के भाग 3 में अन्य मौलिक अधिकारों के स्पष्ट रूप से विपरीत है, लेकिन इसे शिक्षा, शैक्षिक मानकों और संबद्ध मामलों को विनियमित करने की राज्य की शक्ति के अधीन पढ़ा जाना चाहिए।अहमदाबाद में सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज सोसाइटी बनाम।ई गुजरात और ए. एन. आर., [1975] 1 एस. सी. आर. 173, जो कि नौ न्यायाधीशों की पीठ, रे, सी. जे. का निर्णय था, जिसके साथ पालेकर, जे. ने सहमति व्यक्त की, ने कहा (पृष्ठ संख्या में)। 197, 200) कि किसी विश्वविद्यालय से संबद्धता होने पर, अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों को शिक्षा के स्वरूप और मानकों में सहमत होना चाहिए।जो विनियम छात्रों के हितों की पूर्ति करेंगे, जो विनियम शिक्षकों के हितों की पूर्ति करेंगे, वे अच्छे प्रशासन में सर्वोपरि हैं। नियम-कानून

च

शिक्षकों की दक्षता के हित में, संबद्ध संस्थानों के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रशासन में अनुशासन और निष्पक्षता आवश्यक है।यह आगे देखा गयाः

" यह कि सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने वाले अल्पसंख्यक संस्थानों का भी अंतिम लक्ष्य सीखने की प्रगति है।यह न्यायालय

जी.

लगातार यह माना गया है कि शिक्षा के मानकों में उत्कृष्टता और एकरूपता प्राप्त करने के लिए शैक्षिक और शैक्षणिक विषयों में हर चीज को विनियमित करना न केवल अनुमेय है, बल्कि वांछनीय भी है

कैशन "।

इसी मामले में खन्ना, जे. ने सिद्धांतों पर एक अलग जोर दिया।

एच.

(पर 234-35); ST।

स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय (SHETTY, J.) 167 "हालांकि, शैक्षणिक संस्थानों को प्रशासित करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार उन संस्थानों के संबंध में उचित विनियम बनाने से नहीं रोकता है।नियम अनिवार्य रूप से एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में संस्थान के हित में बनाए जाने चाहिए।उन्हें इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए ताकि इसे शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रभावी साधन बनाया जा सके।राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों को प्रशासित करने के अधिकार में स्पष्ट रूप से शिक्षा का अधिकार शामिल नहीं हो सकता है।अस्वास्थ्यकर परिवेश में किसी शैक्षणिक संस्थान के आवास को रोकने के साथ-साथ योग्य शिक्षकों के बिना किसी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना या निरंतरता को रोकने के लिए भी नियम बनाए जा सकते हैं।संस्थान की उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए राज्य नियम निर्धारित कर सकता है।राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों के लिए मानकों का निर्धारण सी अल्पसंख्यक के संस्थानों को प्रशासित करने के अधिकार के खिलाफ नहीं है।शिक्षा, अनुशासन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और इसी तरह की दक्षता के सच्चे हित में बनाए गए विनियम निस्संदेह लगाए जा सकते हैं।इस तरह के नियम उस अधिकार के सार पर प्रतिबंध नहीं हैं जिसकी गारंटी दी गई है:वे उचित कार्यकरण डी को सुरक्षित करते हैं

शैक्षणिक मामलों में संस्थान का "।मैथ्यू, जे. को यह कहना था (267 पर):

" इस मामले का सार यह है कि किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित कोई भी शैक्षणिक संस्थान कुल ऋण माफी का दावा नहीं कर सकता है।

विधायिका या विश्वविद्यालय द्वारा विनियमों से छूट यदि वह संबद्धता या मान्यता चाहता है; लेकिन अनुमेय विनियमों का स्वरूप उनके उद्देश्य पर निर्भर करना चाहिए।जैसा कि हमने कहा, ऐसे विनियम अनुमत होंगे यदि वे मान्यता या संबद्धता के उद्देश्य को सुरक्षित करने या बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रासंगिक हैं।ऐसे सीमा रेखा मामले होंगे जहां यह तय करना मुश्किल है कि क्या कोई विनियमन वास्तव में मान्यता या संबद्धता के उद्देश्य को पूरा करता है।लेकिन यह सिद्धांत के सवाल को प्रभावित नहीं करता है। प्रत्येक मामले में जब किसी विनियमन की तर्कसंगतता अदालत के समक्ष विचार के लिए आती है, तो यह सवाल पूछा और जवाब दिया जाना चाहिए कि क्या विनियमन की गणना मान्यता या संबद्धता के उद्देश्य को कम करने के लिए की गई है या प्रभावी रूप से कम करेगा, अर्थात् अल्पसंख्यक समुदाय और अन्य व्यक्तियों के लिए सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के लिए एक वाहन के रूप में संस्थान की उत्कृष्टता जो इसका सहारा लेते हैं।यह प्रश्न कि क्या कोई विनियमन आम जनता के हित में है, इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, यदि यह सामान्य धर्मनिरपेक्षता के लिए एक वाहन के रूप में संस्थान की उत्कृष्टता को आगे नहीं बढ़ाता है।

शिक्षा, पूर्व परिकल्पना के रूप में, केवल अनुमेय नियम एच 168 हैं।

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जो सुविधा के उद्देश्य की प्रभावशीलता को सुरक्षित करते हैं,

क.

अर्थात्, अपने शैक्षिक मानकों के संबंध में शैक्षणिक संस्थानों की उत्कृष्टता।यही कारण है कि इस न्यायालय ने बार-बार कहा है कि यह सवाल कि क्या किसी विशेष विनियमन की गणना आम जनहित को आगे बढ़ाने के लिए की जाती है, अगर यह अल्पसंख्यक समुदाय और इसका सहारा लेने वाले व्यक्तियों के हित के लिए अनुकूल नहीं है तो इसका कोई परिणाम नहीं है।

लिली कुरियन बनाम।लेविना और ओआरएस।, [1979] 2 एस. सी. सी. 124 को इंगित किया गया था (137 पर):

" अल्पसंख्यकों का संरक्षण संविधान में आस्था का एक अनुच्छेद है

एस.

भारत का।अनुच्छेद 30 (1) में निहित अल्पसंख्यक की पसंद के संस्थानों के प्रशासन के अधिकार का अर्थ है संस्थान के 'मामलों का प्रबंधन'।हालाँकि, यह अधिकार राज्य की नियामक शक्ति के अधीन है।अनुच्छेद 30 (1) कुप्रशासन के लिए एक चार्टर नहीं है; विनियमन, ताकि संस्थान के लाभ के लिए प्रशासन के अधिकार का बेहतर उपयोग किया जा सके, अनुमत है; लेकिन जिस क्षण कोई उससे आगे निकल जाता है और लागू करता है, जो वास्तव में है, केवल विनियमन नहीं है, बल्कि प्रशासन के अधिकार की हानि है, अनुच्छेद लागू होता है और हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

डी.

1 .

आम जनता के हितों की पैरवी करके; हस्तक्षेप को न्यायोचित ठहराने वाले हित केवल अल्पसंख्यकों के हित हो सकते हैं।

ई.

इस पहलू पर विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता वास्तव में आवश्यक नहीं है।अल्पसंख्यकों, चाहे वे धार्मिक हों या भाषाई, को शिक्षा का प्रशासन करने का अधिकार

संस्थान और शैक्षणिक मामलों और प्रबंधन को विनियमित करने की राज्य की शक्ति अब काफी अच्छी तरह से तय हो गई है। प्रशासन के अधिकार में कुशासन का अधिकार शामिल नहीं है।प्राधिकरण को नियंत्रित करने वाले राज्य को अधिकार है

च

और सभी शैक्षणिक मामलों को विनियमित करने का कर्तव्य।ऐसे विनियम बनाए जा सकते हैं जो छात्रों और शिक्षकों के हितों की पूर्ति करेंगे और संबद्ध संस्थानों के बीच शिक्षा के मानकों में एकरूपता बनाए रखेंगे।अल्पसंख्यक संस्थान ऐसे सामान्य पैटर्न और मानक के खिलाफ या कानून और व्यवस्था, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जी श्रम संबंधों, सामाजिक कल्याण कानूनों, अनुबंधों, अपकृत्यों आदि से संबंधित सामान्य कानूनों के खिलाफ प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकते हैं जो सभी समुदायों पर लागू होते हैं।जब तक शैक्षणिक संस्थान के प्रबंधन के लिए अल्पसंख्यकों के मूल अधिकार को छीन नहीं लिया जाता है, तब तक राज्य नियामक कानून बनाने के लिए बाध्य है।हालाँकि, विनियमों का प्रभाव अल्पसंख्यकों के अपने बच्चों को शिक्षित करने के अधिकार से वंचित करने का नहीं होगा।

संस्था।यह एक विशेषाधिकार है जो अनुच्छेद एच 30 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार में निहित है।

एसटी.स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय (शेट्टी, जे.) 169 प्रवेश के लिए छात्रों का चयन करने का अधिकार प्रशासन का एक हिस्सा है।यह ए

1

वास्तव में यह प्रशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है।यह शक्ति भी हो सकती है

विनियमित लेकिन विनियमन किसी भी अन्य विनियमन की तरह उचित होना चाहिए।यह अल्पसंख्यक संस्थान के कल्याण के लिए या इसका सहारा लेने वालों की बेहतरी के लिए अनुकूल होना चाहिए।बॉम्बे सरकार के उस आदेश को, जिसमें अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग करने वाले स्कूलों को अंग्रेजी के अलावा अन्य मातृभाषा रखने वाले छात्रों को प्रवेश देने से रोक दिया गया था, माना गया था

अमान्य क्योंकि इसने स्कूलों के प्रवेश पैटर्न को प्रतिबंधित कर दिया था।(बॉम्बे राज्य बी बनाम।बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी, [1955] 1 एससीआर 568)।गुजरात सरकार ने अल्पसंख्यक संचालित कॉलेज को 80 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का निर्देश दिया

सहायता अनुदान और मान्यता वापस लेने की धमकी देने वाले सरकार द्वारा चुने गए उम्मीदवारों को संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत अल्पसंख्यकों को दिए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के रूप में खारिज कर दिया गया था।(सिद्धजभाई भाई बनाम।बॉम्बे और अन्र राज्य, [1963] 3 एस. सी. आर. 837)।आर टी में।रेव. मैगर।मार्क नेटो वी।केरल सरकार, [1979] 1 एस. सी. आर. 609 एक अल्पसंख्यक विद्यालय के प्रबंधन को बालिकाओं को प्रवेश देने की अनुमति से इनकार करना गलत माना गया था।उस मामले में क्षेत्रीय उप निदेशक ने दो आधारों पर लड़कियों के प्रवेश के लिए मंजूरी देने से इनकार कर दिया; (i) कि स्कूल एक मिश्रित स्कूल के रूप में नहीं खुला था और यह कि स्कूल 25 वर्षों से विशुद्ध रूप से लड़कों के स्कूल के रूप में चलाया जा रहा है; और (ii) कि पास के डी बालिका विद्यालय में इलाके की लड़कियों की शिक्षा की सुविधा थी जो मुसलमानों द्वारा स्थापित किया गया था और एक अल्पसंख्यक संस्थान भी था।इस अदालत ने नोट किया कि इलाके में ईसाई समुदाय चाहता था कि उनकी लड़कियां भी अपने समुदाय द्वारा विशेष रूप से बनाए गए स्कूल में शिक्षा प्राप्त करें।उन्होंने अपने बच्चों को अन्य अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित मुस्लिम बालिका विद्यालय में भेजना अपने हित में नहीं सोचा।लड़कों के अल्पसंख्यक विद्यालय में लड़कियों के प्रवेश की अनुमति को रोकना अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन था।यह भी देखा गया कि अनुमति से इस तरह के इनकार को मंजूरी देने वाला नियम ई नियामक माप के अवरोध को पार करता है और प्रशासन के साथ हस्तक्षेप के क्षेत्र में आता है।

संस्थान, एक ऐसा अधिकार जिसकी अनुच्छेद 30 (1) के तहत अल्पसंख्यकों को गारंटी दी गई है।न्यायालय ने नियम के संचालन को प्रतिबंधित कर दिया और इसे लागू नहीं किया

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान।तमिलनाडु सरकार के स्कूल शिक्षा निदेशक बनाम।रेव. ब्रदर जी. आरोग्यसामी, ए. आई. आर. 1971 मद्रास 440 एफ. मद्रास उच्च न्यायालय के पास सहायता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालयों में उम्मीदवारों के प्रवेश के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एक समान प्रक्रिया की वैधता पर विचार करने का अवसर था।सरकार ने निर्देश दिया कि उम्मीदवारों का चयन स्कूल अधिकारियों द्वारा प्रवेश के लिए पात्र प्रत्येक उम्मीदवार का साक्षात्कार करके और साक्षात्कार में मूल्यांकन और अंक प्रदान करके किया जाना चाहिए।साक्षात्कार में प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए अंकों को S.S.L.C सार्वजनिक परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ा जाएगा।आई. डी. 1. परीक्षा में कुल अंकों और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन बिना किसी विवेकाधिकार के किया जाना था।द.

पी.

उच्च न्यायालय ने कहा कि चयन की विधि ने अल्पसंख्यक संस्थानों की अपने छात्रों को प्रवेश देने की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगाए हैं।यह एच 170 पाया गया था

ए कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र अन्य समुदायों के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे।अन्य समुदायों के छात्रों के आवेदनों को कानून के तहत प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।परिणाम यह हुआ कि अल्पसंख्यक समुदाय के जिन छात्रों के लाभ के लिए संस्थान की स्थापना की गई थी, उन्हें प्रवेश मिलने की बहुत कम संभावना थी।उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चयन की समान विधि निर्धारित करने वाले सरकारी आदेश बी को अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं किया जा सकता है।

तत्काल मामले में भी योग्यता परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के समान आधार पर छात्रों का चयन करने के लिए विश्वविद्यालय के विवादित निर्देश सेंट स्टीफन कॉलेज के ईसाई समुदाय से संबंधित छात्रों को प्रवेश देने के अधिकार से वंचित कर देंगे।यह कॉलेज का अनुभव रहा है जैसा कि सी से चयन के चार्ट में देखा गया है कि जब तक ईसाई छात्रों को कुछ रियायत नहीं दी जाती है, तब तक उनके पास कॉलेज में प्रवेश करने का कोई मौका नहीं होगा।यदि उन्हें अन्य समुदायों से संबंधित छात्रों की व्यापकता के साथ प्रतिस्पर्धा में डाला जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के लिए विचार के क्षेत्र में भी नहीं लाया जा सकता है।कुछ हद तक रियायत देने के बाद भी, अल्पसंख्यक आवेदकों की एक छोटी संख्या को ही प्रवेश मिलेगा।यह विवाद के दायरे से परे है।

विश्वविद्यालय और छात्र संघ की शिकायत है कि कॉलेज प्रवेश कार्यक्रम योग्यता में हेरफेर करने का एक उपकरण है न कि उम्मीदवारों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक वैज्ञानिक परीक्षा।चयन साक्षात्कार में उम्मीदवारों और योग्यता में प्राप्त अंकों का मूल्यांकन करके किया जाता है।

ई.

चयन के लिए परीक्षाओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है।अंक केवल उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाने के लिए प्रासंगिक हैं। हमने कॉलेज प्रवेश कार्यक्रम की सावधानीपूर्वक जांच की है और हमारी राय में, विश्वविद्यालय और छात्र संघ के लिए आग्रह किया गया तर्क गलत है।साक्षात्कार का उद्देश्य योग्यता परीक्षाओं में आवेदकों की योग्यता का पुनर्मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन करना नहीं है।योग्यता परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंक हैं -

च

वास्तव में चयन के लिए प्रासंगिक है और साक्षात्कार केवल पूरक परीक्षा है।महाविद्यालय विभिन्न विषयों में अंकों का अलग-अलग कट-ऑफ प्रतिशत तय करता है।उम्मीदवारों को 1 के अनुपात में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है:4 या 1:5 यह अध्ययन के पाठ्यक्रमों के चयन के लिए उम्मीदवारों की पसंद पर निर्भर करता है।साक्षात्कार यह है

उच्च सत्यनिष्ठा, क्षमता और योग्यता वाले पुरुषों द्वारा आयोजित।वे पुरुष जी हैं जो शिक्षा और छात्रों से संबंधित हैं।साक्षात्कार के दौरान, उम्मीदवार के विषय के ज्ञान और उसके सामान्य ज्ञान का परीक्षण करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं।

वर्तमान समस्याओं के प्रति जागरूकता।छात्र को आवेदन पत्र में अपनी रुचि, शौक, मूल्य, कैरियर योजना आदि भी प्रस्तुत करनी होती है। साक्षात्कार समिति के प्रत्येक सदस्य उम्मीदवारों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं और साक्षात्कार समिति के सभी सदस्यों द्वारा व्यक्त एच राय को ध्यान में रखते हुए अध्ययन के प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए चयन किया जाता है।

एसटी द्वारा।स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय (शेट्टी, जे.) 171

सर्वसम्मति से उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार की जाती है।इस प्रकार चयन किया जाता है

क.

उम्मीदवार के शैक्षणिक रिकॉर्ड और साक्षात्कार में प्रदर्शन का आधार

एस.

उसकी सर्वांगीण क्षमता, महाविद्यालय में रहने से लाभान्वित होने की क्षमता के साथ-साथ महाविद्यालय के जीवन में योगदान करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए।ग्रेडिंग द्वारा प्रदर्शन का आकलन करना शैक्षणिक क्षेत्र में अपनाई जाने वाली एक प्रसिद्ध विधि है।

मौखिक साक्षात्कार को एक पूरक परीक्षा के रूप में और कॉलेज में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए एक विशेष परीक्षा के रूप में इस न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है।लेकिन साथ ही, चयन में मनमानेपन से बचने के लिए बार-बार यह माना गया है कि मौखिक साक्षात्कार परीक्षा के लिए उच्च प्रतिशत अंकों का आवंटन नहीं किया जाएगा।जहाँ उम्मीदवार का व्यक्तित्व अभी तक नहीं है

विकसित करते हुए, इस बात पर जोर दिया गया है कि लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के लिए प्रति बल अधिक वजन सी दिया जाना चाहिए और साक्षात्कार परीक्षा से जुड़ा महत्व न्यूनतम होना चाहिए।न्यायालय ने आम तौर पर संकेत दिया है कि साक्षात्कार के अंक कुल अंकों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।(देखिए:आर. चित्रलेखा और अन्य।वी.मैसूर और अन्य राज्य, [1964] 6 एस. सी. आर. 368; ए. पीरियाकरुप्पन बनाम।तमिलनाडु राज्य, [1971] 2 एससीआर 430; सुश्री निशी माघू डी।

और ओआरएस।वी.जम्मू और कश्मीर राज्य, [1980] 4 एससीसी 95; अजय हसिया आदि।वी. खालिद मुजीब सेहरावर्दी, [1981] 2 एससीआर 79; लीला धर बनाम।राजस्थान राज्य और अन्य।, [1982] 1 एससीआर 320 और कोशल कुमार गुप्ता बनाम।की स्थिति

जम्मू और कश्मीर, [1984] 3 एससीआर 407।

अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि चयन समिति द्वारा किया गया साक्षात्कार उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के विपरीत था।हम साक्षात्कार या चयन में न तो कोई मनमानेपन देखते हैं और न ही कोई दोष या वैज्ञानिक आधार की कमी देखते हैं।साक्षात्कार चयन समिति को अपनी पसंद के किसी भी उम्मीदवार को चुनने और चुनने के लिए कोई व्यापक विवेक प्रदान नहीं करता है।उन्हें उन लोगों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करना होता है जिन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है और विवेक प्रत्येक 4 या 5 में से एक का चयन करने तक सीमित है।इन परिसरों में, हम चयन समिति की पसंद

और विवेकाधिकार को तब तक टाल देंगे जब तक कि वे उचित रूप से कार्य करते हैं और मनमाने ढंग से नहीं और मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के भीतर कार्य करते हैं।

ई.

च

ऐसा लगता है कि कॉलेज के पास अपना अनुसरण करने के लिए मजबूर करने वाले कारण हैं

प्रवेश कार्यक्रम।कॉलेज को देश भर के जी छात्रों से आवेदन प्राप्त होते हैं।प्रवेश के लिए उपलब्ध 400 सीटों की सीमित संख्या के मुकाबले हर साल 12000 से 20000 तक के आवेदन प्राप्त होते हैं।आवेदक विभिन्न मानकों वाले विभिन्न संस्थानों से आते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में आवेदकों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर योग्यता का निर्धारण

एल.

विभिन्न मानकों के साथ योग्यता परीक्षाओं से उचित और

उचित चयन।एच 172 के मानकों को बनाए रखने के लिए भी इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं हो सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

शिक्षा की उत्कृष्टता।जैसा कि इस न्यायालय ने डी. एन. चंचला बनाम में कहा है।मैसूर राज्य, [1971] सप।एस. सी. आर. 608 एक विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षण में एक छात्र द्वारा प्राप्त परिणाम की तुलना परिणाम से नहीं की जा सकती है।

किसी अन्य विश्वविद्यालय की परीक्षा में किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किया गया।इस तरह के मानक कई मानवीय कारकों, शिक्षण की विधि, परीक्षा और उत्तर पत्रों के मूल्यांकन पर निर्भर करते हैं।पढ़ाए जाने वाले और जांचे जाने वाले विषय बी समान हो सकते हैं, लेकिन परीक्षा और मूल्यांकन का मानक भिन्न हो सकता है, और भिन्नताएं अपरिहार्य हैं।परिसर में, केवल छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों द्वारा निर्धारित प्रवेश, भविष्य के शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए सबसे अच्छा उपलब्ध वस्तुनिष्ठ मार्गदर्शक नहीं हो सकता है।दूसरी ओर, उम्मीदवारों के वादे और उपलब्धि की परीक्षा के आधार पर कॉलेज प्रवेश कार्यक्रम, सी योग्यता परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन के अंधे तरीके से बेहतर प्रतीत होता है।इसलिए हम इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि महाविद्यालय प्रवेश कार्यक्रम मनमाना है और चयन के लिए विश्वविद्यालय का मानदंड वस्तुनिष्ठ है।

इसलिए अंत में हम यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित हैं कि सेंट स्टीफन कॉलेज विश्वविद्यालय के विवादित परिपत्रों से बंधा नहीं है।

डी.

तीसरा प्रश्न क्या सेंट स्टीफंस कॉलेज और इलाहाबाद कृषि संस्थान

क्योंकि अल्पसंख्यक संस्थान अपने समुदाय के उम्मीदवारों के पक्ष में वरीयता देने या उनके लिए सीटें आरक्षित करने के हकदार हैं और क्या

ई.

संविधान के अनुच्छेद 29 (2) के तहत वरीयता या आरक्षण अमान्य होगा?

इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि सेंट स्टीफन कॉलेज और इलाहाबाद कृषि

संस्थान सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।सेंट स्टीफन कॉलेज ईसाई छात्रों को प्राथमिकता देता है।इलाहाबाद कृषि संस्थान

च

ईसाई छात्रों के लिए पचास प्रतिशत सीटें आरक्षित करें।वरीयता या आरक्षित कोटे के विरुद्ध प्रवेश पाने वाले ईसाई छात्रों की योग्यता परीक्षा में योग्यता अन्य उम्मीदवारों की तुलना में कम होती है।अधिक योग्यता वाले अन्य उम्मीदवारों को इस आधार पर प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है कि वे ईसाई नहीं हैं।

जी.

विश्वविद्यालय और छात्र संघ के लिए यह तर्क दिया गया कि चूंकि दोनों संस्थानों को राज्य सहायता मिल रही है, इसलिए धर्म के आधार पर प्रशासन के लिए संस्थागत वरीयता संविधान के अनुच्छेद 29 (2) का उल्लंघन है।संस्थान इन आधार पर उम्मीदवारों को पसंद या अस्वीकार नहीं करेंगे -

धर्म।दूसरी ओर, संस्थानों के लिए यह दावा किया गया था कि धार्मिक अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को उनके अपने संस्थानों में कोई भी वरीयता एच नहीं दी जा सकती है।

पे एसटी।स्टीफंस कॉलेज "।दिल्ली विश्वविद्यालय [शेट्टी, जे.] 173 अनुच्छेद 29 (2) के तहत आने वाला भेदभाव।संस्थानों की स्थापना उनके समुदाय के लाभ के लिए की जाती है और यदि उन्हें अपने समुदाय के उम्मीदवारों को प्रवेश देने से रोका जाता है, तो संस्थानों की स्थापना का उद्देश्य विफल हो जाएगा।अल्पसंख्यकों को वरीयता या आरक्षण द्वारा अपने उम्मीदवारों को प्रवेश देने का अधिकार है।वे उन्हें अन्य सभी के बहिष्कार में प्रवेश देने के भी हकदार हैं और यह अधिकार अनुच्छेद 30 (1) के तहत गारंटीकृत शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार से आता है।

हम इस प्रश्न में भेदभाव और मुख्य रूप से सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में धर्म के आधार पर भेदभाव के बारे में चिंतित हैं।इस मुद्दे में नागरिक की अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक हिस्से के रूप में पात्रता शामिल है कि वह अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थान में अल्पसंख्यकों के अधिकार के खिलाफ धर्म के आधार पर भेदभाव न करे।यह सबसे कठिन और जटिल सी मुद्दा है और प्रतीत होता है कि यह इस न्यायालय के किसी भी प्राधिकरण के दायरे में नहीं आता है।इस मुद्दे का निर्धारण मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 29 (2) और 30 (1) के संवैधानिक दायरे पर निर्भर करता है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार

डी.

इस मुद्दे से निपटने से पहले, हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की ओर रुख कर सकते हैं जो हमारे समक्ष अपील के अधीन है।संस्थान द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में उच्च प्रतिशत अंक प्राप्त करने के बावजूद छात्रों को प्रवेश से वंचित कर दिया गया था।यह इनकार इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया था कि चर्च प्रायोजित उम्मीदवारों और आदिवासियों के लिए बड़ी संख्या में सीटें आरक्षित की गई थीं।याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि आरक्षण का उल्लंघन किया गया था

ई.

अनुच्छेद 29 (2) क्योंकि यह धर्म पर आधारित था।उच्च न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार कर लिया और अन्य बातों के साथ-साथ यह भी माना कि धर्म के आधार पर अधिक योग्य उम्मीदवारों को प्रवेश से इनकार करने की अनुमति नहीं है।संस्थान अपने समुदाय के सदस्यों के लिए भी सीटें आरक्षित नहीं कर सका।संवैधानिक

अनुच्छेद 30 (1) में शिक्षा में धार्मिक स्वायत्तता की अवधारणा को अनुच्छेद 29 (2) के तहत संवैधानिक गारंटी के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।दोनों लेख एक ही क्षेत्र में काम करते हैं; शैक्षणिक संस्थान।अनुच्छेद 30 (1) के तहत अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अधिकार की गारंटी को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है, और इसकी व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि यह अनुच्छेद 29 (2) में दिए गए अधिकार को नष्ट न करे।उच्च न्यायालय ने अंततः कहा है कि अनुच्छेद 30 (1) के तहत प्रशासन की शक्ति के आधार पर जी द्वारा किसी संस्थान में निहित प्रवेश का अधिकार अनुच्छेद 29 (2) का उल्लंघन नहीं हो सकता है।

च

हमें ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय ने उदार व्यक्तिवादी सिद्धांत का पालन किया है।उदार व्यक्तिवादी सिद्धांत आम तौर पर अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों की अवधि से पश्चिमी राजनीतिक सिद्धांत है।उच्च न्यायालय ने एच.

1

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

एल 174

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान के तहत गारंटीकृत भाषा, धर्म, शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकारों के संबंध में सकारात्मक अल्पसंख्यक अधिकारों पर थोड़ा या कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।यह अनुच्छेद 30 (1) में व्यक्त प्रमुख जोर पर विचार करने में विफल रहा है।इसने अनुच्छेद 29 (2) में अंतर्निहित परिप्रेक्ष्य में अंतर की अनदेखी की है और

30 (1) .

बी प्री-अल्पसंख्यक अधिकारों का प्राकृतिक इतिहास अल्पसंख्यकों को अधिकारों के सामान्य विधेयक या मौलिक अधिकारों से बहुत अधिक लाभ नहीं होता है जो केवल व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं।अल्पसंख्यकों को अपने अल्पसंख्यक हितों को बनाए रखने के लिए सकारात्मक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है जिन्हें समूह अधिकार भी कहा जाता है।सुरक्षा और समूह अधिकार सी हमारे संविधान निर्माण का हिस्सा रहे हैं।अनुच्छेद 29 और 30 के इतिहास के परिप्रेक्ष्य का अवलोकन करना दिलचस्प है। अल्पसंख्यकों के प्रश्न से निपटने के लिए संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें कीं:

↓

" (i) प्रत्येक इकाई में अल्पसंख्यकों को उनके संबंध में संरक्षित किया जाएगा।

डी.

भाषा, लिपि और संस्कृति, और ऐसा कोई कानून या विनियम नहीं बनाया जा सकता है जो इस संबंध में दमनकारी या पूर्वाग्रहपूर्ण रूप से काम कर सके।

((ii) किसी भी अल्पसंख्यक के साथ, चाहे वह धर्म, समुदाय या समुदाय के आधार पर हो, प्रवेश के संबंध में भेदभाव नहीं किया जाएगा।

ई.

राज्य शैक्षणिक संस्थान, और न ही कोई धर्म, शिक्षा उन पर अनिवार्य रूप से थोपी जाएगी।

(क) सभी अल्पसंख्यक-चाहे वे धर्म, समुदाय या भाषा के आधार पर हों-किसी भी इकाई में अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए स्वतंत्र होंगे; और

च

(ख) राज्य, विद्यालयों को राज्य सहायता प्रदान करते समय अल्पसंख्यकों के प्रबंधन के तहत स्कूलों के साथ भेदभाव नहीं करेगा।

चाहे वह धर्म, समुदाय या भाषा पर आधारित हो।

एल.

मसौदा तैयार करने के चरण में, इन सिफारिशों को अंततः संशोधित किया गया।

जी.

कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ अनुच्छेद 23 का मसौदा।मसौदा समिति ने स्वयं नागरिकों के किसी भी वर्ग के अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के अधिकार और धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों के अपनी पसंद की संस्था की स्थापना

और प्रशासन के अधिकार के बीच अंतर करने का प्रयास किया।इस भेद को ध्यान में रखते हुए, अनुच्छेद 23 कोर एसटी के मसौदे के पहले भाग में 'अल्पसंख्यक' शब्द को 'नागरिकों के किसी भी वर्ग' शब्द से बदल दिया गया था।

स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय (शेट्टी, जे.) 175 वर्तमान अनुच्छेद 29 (1) का समर्थन करता है।हालांकि, मसौदा समिति ने 'ए' शब्द को मसौदा अनुच्छेद के उत्तरार्ध में 'अल्पसंख्यक' शब्द के रूप में बरकरार रखा था, जो बाद में वर्तमान अनुच्छेद 30 (1) बन गया।सी. ए. डी. वॉल्यूम.VII 1949 पी।895

प्रशासनों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव के निषेध के संबंध में

क.

इसलिए, यह हमेशा से महसूस किया जाता रहा है कि अधिकार का विस्तार राज्य सहायता प्राप्त संस्थानों तक भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ मसौदा समिति ने भी बदलाव किए और अनुच्छेद 23 के बी मसौदा खंड (2) को वर्तमान अनुच्छेद 29 (2) के साथ प्रतिस्थापित किया और जिसे सी. ए. डी. खंड स्वीकार कर लिया गया।VII 1949 पी।925 .

डॉ. अम्बेडकर ने कुछ संशोधनों से संबंधित बहस का जवाब देते हुए इस परिवर्तन के कारणों को समझाया।उन्होंने कहा कि पहले के मसौदे में 'अल्पसंख्यक' शब्द का उपयोग न केवल 'सी' शब्द के तकनीकी अर्थ में अल्पसंख्यकों को इंगित करने के लिए किया गया था, बल्कि वे फिर भी अल्पसंख्यक थे।चूंकि 'अल्पसंख्यक' शब्द एक संकीर्ण व्याख्या करने में सक्षम था और इसका उद्देश्य संस्कृति, भाषा और लिपि के मामले में व्यापक अर्थों में सुरक्षा प्रदान करना था, इसलिए मसौदा समिति ने 'अल्पसंख्यक' शब्द को हटा दिया था और इसके बजाय 'नागरिकों का कोई भी वर्ग' शब्द का उपयोग किया था।उन्होंने इशारा किया:भारत की रचना

"

डी.

संविधान-बी. शिव राव का एक अध्ययन 1968 एड पी।280 .

" कि यह अनुच्छेद मसौदा अनुच्छेद में एक सुधार था।मूल प्रावधान में केवल अल्पसंख्यकों की संस्कृति, लिपि और भाषा की रक्षा करने का कर्तव्य राज्य पर डाला गया था।इसने इन समुदायों को कोई मौलिक अधिकार नहीं दिया।इसने केवल कर्तव्य अधिरोपित किया और एक खंड जोड़ा कि जबकि राज्य को भाषा, संस्कृति और लिपि के इन अधिकारों पर सीमाएं लगाने का अधिकार हो सकता है, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिसे दमनकारी कहा जा सके; ऐसा नहीं कि राज्य को इन मामलों को प्रभावित करने वाला कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि यह कि कानून दमनकारी नहीं होगा।

ई.

मूल लेख बहुत असुरक्षित था।यह राज्य की सद्भावना पर निर्भर करता था।वर्तमान स्थिति जैसा कि आप पाते हैं कि हमने इसे एक मौलिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया है, ताकि यदि कोई राज्य कोई ऐसा कानून बनाए जो इस अनुच्छेद के प्रावधानों के साथ असंगत था, तो वह कानून अमान्य हो जाएगा।" ¨

च

अल।

ये वे कारण हैं जिन्होंने जी के उपायों को शामिल करने के लिए प्रेरित किया

*

अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए मौलिक अधिकार।

1

संविधान के अनुच्छेद 29 (1) और 30 (1)

स्थिति निर्धारित करने के बाद, हम अनुच्छेद 29 (1) और 30 (1) के प्रावधानों से अपेक्षाकृत जल्दी निपट सकते हैं।अनुच्छेद 29 (1) के तहत नागरिकों के प्रत्येक वर्ग एच 176

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति रखने वाले को इसे संरक्षित करने का अधिकार है।अनुच्छेद 29 (1) के तहत, अल्पसंख्यकों-धार्मिक या भाषाई-को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है।हालाँकि, न्यायालयों द्वारा लगातार यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्यों तक ही सीमित नहीं है।अनुच्छेद बी 30 (1) में अधिकार व्यापक आयाम के हैं।अनुच्छेद 30 (1) की चौड़ाई को उन विचारों से कम नहीं किया जा सकता है जिन पर अनुच्छेद 29 (1) आधारित है।अनुच्छेद 30 (1) में "उनकी पसंद के" शब्द अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक संस्थानों के प्रकार का चयन करने के लिए विशाल विकल्प छोड़ते हैं जिन्हें वे स्थापित करना चाहते हैं।वे अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के लिए या सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने के लिए या दोनों उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं।(देखिएःफादर डब्ल्यू. प्रोस्ट बनाम।सी बिहार राज्य, [1969] 2 एससीआर 73; अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज बनाम।गुजरात राज्य, [1975] 1 एस. सी. आर. 173 और पुनः:केरल शिक्षा विधेयक मामला, [1959] एससीआर 995।

2

संविधान के अनुच्छेद 29 (2) और 30 (1)

वास्तव में, हमें दो चरम तर्कों से दूर रहना चाहिए जिनके लिए आग्रह किया गया है

डी.

संस्थाएं।संस्थानों के वकील ने तर्क दिया कि अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को उनके अपने शैक्षणिक संस्थान में दी जाने वाली प्राथमिकता अनुच्छेद 29 (2) का उल्लंघन नहीं है।इस तरह की वरीयता केवल धर्म के आधार पर नहीं है, बल्कि इस आधार पर है कि उम्मीदवार अल्पसंख्यक समुदाय से है।यह भी आग्रह किया गया कि अनुच्छेद 30 (1) में अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए अल्पसंख्यक अपने समुदाय के उम्मीदवारों के विशेष लाभ के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के हकदार हैं।जहाँ तक पहले बिंदु का संबंध है, यह ध्यान दिया जा सकता है कि धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के लिए संस्थागत वरीयता स्पष्ट रूप से धर्म के निषिद्ध आधार पर एक संस्थागत भेदभाव है।यह केवल धर्म के आधार पर गैर-अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों को कलंकित करने या अलग करने के लिए काम करता है।यदि कोई शैक्षणिक संस्थान एक उम्मीदवार को एफ "हां" कहता है लेकिन धर्म के आधार पर दूसरे उम्मीदवार को "नहीं" कहता है, तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव के बराबर है।अनुच्छेद 29 (2) का अधिदेश यह है कि ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा।

#

}

समान रूप से, इस दूसरी दलील को स्वीकार करना मुश्किल होगा कि अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है।

जी उनका अनन्य लाभ।अनुच्छेद 30 (1) में दिए गए संस्थान के चयन का मतलब यह नहीं है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए जा सकते हैं।

अपने समुदाय के लोगों का लाभ।वास्तव में वे ऐसा नहीं कर सकते।इसे री में इंगित किया गया थाःकेरल शिक्षा विधेयक [1959] एस. सी. आर. 995 कि अल्पसंख्यक नहीं कर सकते

केवल अपने समुदाय के लाभ के लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित करें।यदि ऐसा उद्देश्य होता, तो अनुच्छेद 30 (1) को अलग तरीके से लिखा जाता और इसमें एच में "अपने समुदाय के लिए" शब्द शामिल होते।इस तरह की अनुपस्थिति में>

| एसटी.स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय [शेट्टी, जे.] 177 शब्दों में, अनुच्छेद का यह अर्थ लगाना कानूनी रूप से अस्वीकार्य है कि ए अल्पसंख्यकों को अपने लाभ के लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है।व्यवहार में भी, ऐसे दावों को काफी हद तक पूरा किए जाने की संभावना है

शत्रुता।अपेक्षाकृत समरूप समाज का होना अनुकूल नहीं हो सकता है।यह धार्मिक कट्टरता की ओर ले जा सकता है जो मानव जाति के लिए अभिशाप है।धर्मनिरपेक्ष चरित्र वाले राष्ट्र निर्माण में सांप्रदायिक स्कूल या कॉलेज; सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने के लिए अलग-अलग बी संकाय या विश्वविद्यालय अवांछनीय हैं और वे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को कमजोर कर सकते हैं।वे संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता और समानता की केंद्रीय अवधारणा के साथ असंगत होंगे।प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान चाहे वह किसी भी समुदाय से संबंधित हो, हमारे राष्ट्रीय जीवन में एक 'मेल्टिंग पॉट' है।छात्र और शिक्षक महत्वपूर्ण घटक हैं।यही वह जगह है जहाँ उन्होंने संस्कृतियों सी और दूसरों की मान्यताओं के प्रति सम्मान और सहिष्णुता विकसित की।इसलिए यह आवश्यक है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न समुदायों के छात्रों का उचित मिश्रण होना चाहिए।

विश्वविद्यालय और छात्रों के लिए वकील के तर्क का मूल

संघ यह है कि सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले अल्पसंख्यक संस्थान डी द्वारा बाध्य हैं

अनुच्छेद 29 (2) का अधिदेश और वे अपने स्वयं के उम्मीदवारों को पसंद नहीं कर सकते।हम अनुच्छेद 29 (2) से शुरुआत कर सकते हैं।

अनुच्छेद 29 (2) प्रदान करता हैः

" 29 (2) किसी भी नागरिक को किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।

राज्य द्वारा अनुरक्षित या राज्य से बाहर सहायता प्राप्त करने वाली संस्था

केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर धन।

राज्य द्वारा बनाए गए या सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच, अनुच्छेद 29 (2) की विशेष चिंता है।यह किसी व्यक्ति के धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी के तत्वावधान में भेदभाव न किए जाने के अधिकार को मान्यता देता है।यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है।

च

;

किसी नागरिक के विशेष धर्म, नस्ल, जाति या किसी विशेष भाषा के आधार पर भेदभाव राज्य द्वारा बनाए गए या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षणिक संस्थानों में पूरी तरह से निषिद्ध है।यह अल्पसंख्यकों के साथ-साथ गैर-अल्पसंख्यकों पर भी लागू होता है।जब अन्य योग्यताएँ समान हों तो किसी नागरिक का धर्म, नस्ल, जाति, भाषा वरीयता या विकलांगता का आधार नहीं होगा।इसी तरह, अनुच्छेद 29 (2) में उपयोग किए गए "उनमें से कोई भी" शब्दों का उद्देश्य इस बात पर और जोर देना है कि अनुच्छेद में उल्लिखित किसी भी आधार को भेदभाव का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता है।(मद्रास राज्य बनाम देखें। चंपकम दोराईराजन [1951] 2 एस. सी. आर. 525 और

जी.

बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी मामला [1955] 1 एससीआर 568।

एच.

4

तथ्य यह है कि अनुच्छेद 29 (2) अल्पसंख्यकों के साथ-साथ गैर-अल्पसंख्यकों पर भी लागू होता है

क.

इसका मतलब यह नहीं है कि इसका उद्देश्य गारंटीकृत विशेष अधिकार को रद्द करना था

अनुच्छेद 30 (1) में अल्पसंख्यक।अनुच्छेद 29 (2) गैर-भेदभाव से संबंधित है और यह केवल व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है।गैर-भेदभाव द्वारा सामान्य समानता अल्पसंख्यकों का एकमात्र लक्ष्य नहीं है।बहुसंख्यक शासन के तहत अल्पसंख्यक अधिकारों का तात्पर्य गैर-भेदभाव से अधिक है और वास्तव में, यह गैर-भेदभावपूर्ण बी राष्ट्र से शुरू होता है।हितों और संस्थानों की सुरक्षा और अवसरों की उन्नति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।विभेदक उपचार जो उन्हें बहुमत से अलग करता है, उनकी बुनियादी विशेषताओं को संरक्षित करने के लिए आवश्यक है।स्पष्ट होने के लिए, काले पुरुष सफेद नहीं होना चाहते हैं।यहूदी प्रोटेस्टेंट नहीं बनना चाहते हैं। सर्ब क्रोएशियाई नहीं बनना चाहते हैं।फ्रांसीसी कनाडाई अपनी फ्रांसीसी विरासत को खोना नहीं चाहते हैं।कई अन्य उदाहरण हैं, जिनमें फ्रांस में कोर्सिकन, अल्स्टर में आयरिश कैथोलिक सी, क्यूबेक में फ्रांसीसी कनाडाई, कोसोवो में अल्बेनियाई, यूगोस्ला के माध्यम से, श्रीलंका में तमिल, फिलीपींस में इस्लामी अलगाववादी और दक्षिणी सूडान में जीववादी और ईसाई अल्पसंख्यक शामिल हैं।भारत में समस्या बहुत अलग नहीं है।भारत एक बहु-सांस्कृतिक और बहु-धार्मिक समाज है।यह विभिन्न धार्मिक लघु संबंधों वाला एक असाधारण बहुलवादी और जटिल समाज है।इसके अलावा भाषाई आकांक्षाएं और जाति संबंधी विचार भी हैं।डी अल्पसंख्यक समूह में ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो बहुमत में आत्मसात करना चाहते हैं, लेकिन समूह का स्वयं गैर-एकीकरण के लिए सामूहिक हित है।यह एक समुदाय के रूप में संरक्षण और संवर्धन में रुचि रखता है।यह मुख्य कारण प्रतीत होता है जिसके लिए अनुच्छेद 30 (1) को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था।नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (1966) का अनुच्छेद 27 भी इस संबंध में एक नींव रखता है।इसमें कहा गया हैः "उन राज्यों में जिनमें ई जातीय, धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक मौजूद हैं, ऐसे अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों को अपने समूह के अन्य सदस्यों के साथ समुदाय में अपनी संस्कृति का आनंद लेने, अपनी संस्कृति का पालन करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।

1

एफ; ए}

धर्म, या अपनी भाषा का उपयोग करना "।फिर भी एक और प्रस्तुति जिसमें वकील ने तर्क दिया कि एक धर्मनिरपेक्ष में

च

लोकतंत्र सरकारी कोष का उपयोग किसी विशेष समुदाय के हितों को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता है और अनुच्छेद 29 (2) केवल तभी प्रतिबंध लगाता है जब अल्पसंख्यक संस्थान राज्य वित्तीय सहायता चाहता है और प्राप्त करता है और अल्पसंख्यक संस्थान अधिकार के रूप में राज्य सहायता का हकदार नहीं है।

यह बिल्कुल सच है कि अल्पसंख्यकों के लिए राज्य अनुदान का कोई हक नहीं है

जी.

शैक्षणिक संस्थान।एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए राज्य अनुदान प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 337 के तहत केवल एक विराम-अंतराल व्यवस्था थी।राज्य से अनुदान प्राप्त करने के लिए अन्य अल्पसंख्यकों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।लेकिन इसके तहत

अनुच्छेद 30 (2), राज्य व्यवहार की समानता बनाए रखने के लिए बाध्य है।

शैक्षणिक संस्थानों को सहायता प्रदान करना।वित्तीय सहायता देते समय अल्पसंख्यक संस्थानों के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।उन्हें पाने का अधिकार है

} एसटी.स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय (शेट्टी, जे.) ने काफी हद तक बहुसंख्यक ए समुदायों के संस्थानों की तरह ही वित्तीय सहायता प्रदान की।

दूसरा, राज्य सहायता की प्राप्ति अनुच्छेद के अधिकारों को बाधित नहीं करती है।

30 (1) .राज्य सहायता अनुदान प्राप्त करने और इसके उचित उपयोग के लिए उचित शर्तें निर्धारित कर सकता है।राज्य के पास अल्पसंख्यकों को मजबूर करने की कोई शक्ति नहीं है

संस्थानों को अनुच्छेद 30 (1) के तहत अपने अधिकारों का त्याग करना।(सेकःरीःकेरल बी शिक्षा विधेयक मामला, [1959] एस. सी. आर. 995 और सिद्धजभाई मामला [1963] 3 एस. सी. आर. 837।बाद के मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि विनियमन जो अनुदान प्राप्त करने की शर्त के रूप में कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है, उसे संस्थान को एक प्रभावी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान बनाने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए।शासन अल्पसंख्यक संस्थान के चरित्र को नहीं बदल सकता है।इस तरह के विनियमों को एक दोहरी परीक्षा को संतुष्ट करना चाहिए; तर्कसंगतता की परीक्षा, और यह परीक्षा कि यह संस्थान के शैक्षिक चरित्र का सी नियामक है।यह संस्थान को अल्पसंख्यक समुदाय या इसका सहारा लेने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए शिक्षा का एक प्रभावी माध्यम बनाने के लिए अनुकूल होना चाहिए।इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बाद भी अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार अप्रभावित रहते हैं।

D शैक्षणिक संस्थान व्यावसायिक घराने नहीं हैं।वे नहीं करते।

धन उत्पन्न करें।वे सार्वजनिक धन या निजी सहायता के बिना जीवित नहीं रह सकते।ऐसा कहा जाता है कि छात्रों की फीस के संग्रह पर भी प्रतिबंध है।शुल्क संग्रह पर प्रतिबंध के साथ, अल्पसंख्यकों को अनुदान-सहायता के बिना शैक्षणिक संस्थानों को बनाए रखने का बोझ नहीं डाला जा सकता है।उनके पास ई नहीं है

दूसरों पर आर्थिक लाभ।राज्य की सहायता के बिना शैक्षणिक संस्थान होना संभव नहीं है।दास, सी. जे. द्वारा भी री में यह विचार व्यक्त किया गया थाःकेरल शिक्षा विधेयक मामला [1959] एससीआर 995।इसलिए अल्पसंख्यकों को अपने दम पर शैक्षणिक संस्थानों को बनाए रखने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

यह तर्क दिया गया कि अनुच्छेद 30 (1) अनुच्छेद 29 (2) के अधीन है और एफ के समर्थन में है।

एकर अवलोकन डी. ए. वी. महाविद्यालय [1971] 2 एस. सी. सी. 269 आ पुनः:केरल शिक्षा विधेयक [1959] एस. सी. आर. 995 मामलों पर भरोसा किया गया।डी. ए. वी. कॉलेज मामले में

इस न्यायालय ने अनुच्छेद 29 (1) और 30 (1) के संबंधित दायरे को समझाया और कहा (273 पर) कि अनुच्छेद 29 (1) अनुच्छेद 30 (1) से व्यापक है।अनुच्छेद 29 (1) के तहत गारंटीकृत अधिकार नाबालिग संबंधों सहित नागरिकों के किसी भी वर्ग के लिए उपलब्ध हैं, जबकि अनुच्छेद 30 (1) के तहत गारंटीकृत अधिकार केवल धर्म या भाषा के आधार पर जी अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध हैं।अनुच्छेद 30 (1) के तहत अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक का अधिकार अपने मानकों की उत्कृष्टता को बनाए रखने और सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य की नियामक शक्ति के अधीन है।यह अधिकार आगे के अधीन है -

अनुच्छेद 29 (2) जो यह प्रावधान करता है कि किसी भी नागरिक को किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा जो राज्य द्वारा बनाए रखा जाता है या एच 180 से सहायता प्राप्त करता है।

[1991] .एसयूपीपी।3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्य केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर धन देता है।इन रेःकेरल शिक्षा विधेयक मामला [1959] एस. सी. आर. 995 में (1047 में) यह बताया गया था कि अनुच्छेद 30 (1) में अधिकार अनुच्छेद 29 (2) के अधीन है जिसमें यह प्रावधान है कि किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा बनाए गए किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा या केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर राज्य के धन से सहायता प्राप्त नहीं की जाएगी।

>

हालाँकि, न्यायालय उस प्रश्न का निर्णय नहीं कर रहा था जो अब हमारे सामने आया है।न्यायालय ने केवल अनुच्छेद 30 (1) में अधिकार का एक पारित संदर्भ दिया।

अब प्रस्तुत किए गए पहलुओं पर न्यायालय द्वारा कभी विचार नहीं किया गया।वास्तव में जिस मुद्दे पर हमें अल्पसंख्यकों के अपने शैक्षणिक संस्थानों में अपने सामुदायिक उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने के अधिकार के बारे में विचार करने के लिए कहा जाता है, वह न्यायालय के समक्ष विचार के लिए नहीं आया था।हम कुंवारी मिट्टी पर हैं, न कि कुचली हुई जमीन पर।

अल्पसंख्यकों के साथ धार्मिक तटस्थ तरीके से व्यवहार नहीं किया जा सकता है

उनके द्वारा स्थापित और प्रशासित शैक्षणिक संस्थान।स्पष्ट रूप से यह उद्देश्य या अनुच्छेद 30 (1) नहीं था।अनुच्छेद 30 (1) को केवल धर्म के नाम पर डी अल्पसंख्यकों के लिए एक उचित सौदा सुनिश्चित करने के लिए शामिल किया गया था।निर्माताओं द्वारा बहुत विचार-विमर्श के बाद उन्हें एक मौलिक अधिकार के रूप में इसकी गारंटी दी गई थी।इसे संकीर्ण न्यायिक व्याख्या या क्राब्ड पेडेंट्री द्वारा रद्द नहीं किया जाना चाहिए।एक व्यापक दृष्टिकोण और राजनेता जैसी दृष्टि होनी चाहिए।कैथोलिक दृष्टिकोण जिसके कारण अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित प्रावधानों का मसौदा तैयार किया गया, जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, को शून्य नहीं माना जाना चाहिए।यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अल्पसंख्यकों को अपनापन और सुरक्षा की भावना से वंचित करने के लिए कुछ भी नहीं किया जाए।[(देखिए:सेंट जेवियर्स मामले में खन्ना, जे. की टिप्पणियाँ [1975] 1 एस. सी. आर. 173 (234 पर)]

भारत बहुत हद तक एक राष्ट्र बन रहा है।संबंध हैं और

बहुस्तरीय मिश्रण में कनेक्शन।चिंता और विचार हैं

च

अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित प्रावधान।संस्थापक पिताओं की स्थिति और अपेक्षाओं के तहत साझा हैं।इस तरह की चिंता और विचार के बिना और इस तरह की साझा स्थिति और अपेक्षाओं के बिना संवैधानिक निर्माण अपर्याप्त होना तय है।यह बहुत हद तक ऐतिहासिक विरोधी होगा और संभावित रूप से विनाशकारी संवैधानिक शून्यवाद पैदा करेगा।

जी परिणाम।“ मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने कहा, "हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह एक ऐसा संविधान है जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं।कुलॉक वी।मैरीलैंड:4 407 पर गेहूं 316 एक उपकरण "आने वाले युगों के लिए तैयार किया गया है, और. अमरता तक पहुंचने के लिए डिज़ाइन किया गया है जितना कि मानव संस्थान पहुंच सकता है"।कोहेन वी.वर्जीनिया 6 गेहूं 264 पी पर।387 .

हमें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट "एसटी" के फैसले के लिए भेजा गया है।

एच.

स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय (शेट्टी, जे.) 181

कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बनाम।ऐलन बक्के 438 यू. एस. 265 जहाँ नियमित प्रवेश के लिए ए बक्के के दावे को कैलिफोमिया मेडिकल स्कूल द्वारा खारिज कर दिया गया था

विशेष प्रवेश कार्यक्रम के तहत भर्ती किए गए कुछ वंचित उम्मीदवारों के पक्ष में बोई गई वरीयता का दृष्टिकोण।द अमेरिकन सु

}

न्यायालय ने विशेष प्रवेश कार्यक्रम को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया क्योंकि यह प्रवेश में एक निर्धारक कारक के रूप में नस्ल पर आधारित था।बक्के के मामले में निर्णय 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम और अमेरिकी संविधान के बी चौदहवें संशोधन पर आधारित था।हालाँकि, यह निर्णय हमारे सामने मामले के लिए बहुत कम सहायक है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में हमारे संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के समान कोई प्रावधान नहीं है।अल्पमत अधिकार और हितों का संतुलन

एस.

हमने कहीं और बताया है कि अल्पसंख्यकों को अपने संस्थानों के अल्पसंख्यक चरित्र को बनाए रखने के लिए अपने उम्मीदवारों को प्रवेश देने का अधिकार है।यह एक आवश्यक सहवर्ती अधिकार है जो अनुच्छेद 30 (1) में शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और

प्रशासन के अधिकार से आता है।अल्पसंख्यक समुदायों में माता-पिता के लिए भी एक संबंधित अधिकार है।माता-पिता डी के हकदार हैं

अपने बच्चों को उन संस्थानों में शिक्षित करें जो उनके अपने धर्म के अनुकूल वातावरण रखते हों [देखें]:सेंट जेवियर के मामले [1975] 1 एस. सी. आर. 173 में 253 पर मैथ्यू, जे. की टिप्पणियाँ।

सामूहिक अल्पसंख्यक अधिकार को कार्यात्मक बनाने की आवश्यकता है और इसे बेकार लकड़ी तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए।अनुच्छेद 30 (1) के तहत एक सार्थक अधिकार को आकार दिया जाना चाहिए, ढाला जाना चाहिए और बनाया जाना चाहिए, साथ ही साथ अनुच्छेद 29 (2) के तहत व्यक्तियों के अधिकार की पुष्टि की जानी चाहिए।दोनों प्रतिस्पर्धी अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है।अनुच्छेद 29 (2) और अनुच्छेद 30 (1) के बीच, इन अनुच्छेदों के अक्षर और भावना के बीच, अतीत की परंपराओं और वर्तमान की सुविधा के बीच, समाज की स्थिरता की आवश्यकता और परिवर्तन की आवश्यकता के बीच मध्यस्थता करना आवश्यक है।

च

संविधान धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की स्थापना करता है।एनिमेटिंग सिद्धांत

किसी भी लोकतंत्र में लोगों की समानता होती है।लेकिन यह विचार कि सभी लोग समान हैं, गहराई से अटकलबाजी है।यह अच्छी तरह से कहा जाता है कि कुछ व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करने के लिए, हमें उनके साथ अलग व्यवहार करना चाहिए।हमें अल्पसंख्यकों के पक्ष में उचित स्तर के भेदभाव को पहचानना होगा।लेकिन धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए धार्मिक तटस्थ तरीके से जी की सकारात्मक कार्रवाई करना असंभव है।धर्म से परे जाने के लिए हम धर्म को नजरअंदाज नहीं कर सकते।हमें पहले धर्म का ध्यान रखना चाहिए।यह ठीक इन विचारों की भावना में है कि इस न्यायालय ने री में अपनी सलाहकार राय में कहा है:केरल शिक्षा विधेयक मामला [1959] एस. सी. आर. 995 ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के पक्ष में उचित स्तर के भेदभाव को मान्यता दी। इस संबंध में ऐसा लगता है कि न्यायालय ने उसी सिद्धांत पर कार्य किया है जो एच 182 है।

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों पर लागू होता है, जो सुरक्षात्मक भेदभाव का सिद्धांत है।बालाजी बनाम।मैसूर राज्य [1963] पूरक।1 एस. सी. आर. 43 ने अनुच्छेद 15 (4) के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वैधता की जांच करते हुए, जैसा कि वे तब थे, गजेंद्रगढ़कर ने बताया कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण समाज में कमजोर तत्वों की प्रगति बी को बढ़ावा देकर बड़े पैमाने पर समाज के हितों की सेवा करेगा।

केरल राज्य में बनाम।एन. एम. थॉमस और अन्य।, [1976] 1 एससीआर 906,933 रे,

सी. जे. ने पिछड़े वर्गों के लिए तरजीही व्यवहार के संदर्भ में अनुच्छेद 14,15 (1) और 16 (1) द्वारा गारंटीकृत समानता की अवधारणा पर विचार करते हुए कहा कि केवल प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए तरजीही व्यवहार का अर्थ सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता हो सकता है।असमान लोगों के लिए अवसर के लिए समानता का अर्थ केवल असमानता को बढ़ाना हो सकता है।अवसर की समानता तर्क के साथ भेदभाव को स्वीकार करती है और बिना कारण के भेदभाव को रोकती है।कारणों के साथ भेदभाव का अर्थ है संवैधानिक रूप से अनुमेय वस्तुओं के साथ संबंध रखने वाले विभेदक उपचार के लिए तर्कसंगत वर्गीकरण।प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए सेवाओं में बैक डी वार्ड वर्गों के लिए तरजीही प्रतिनिधित्व अनुमेय उद्देश्य है और पिछड़े वर्ग हमारे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त एक तर्कसंगत वर्गीकरण है।इसलिए, चयन के मानकों में विभेदक व्यवहार समानता की अवधारणा के भीतर है।

अखिल भारतीय सोशी कर्मचारी संघ (रेलवे) बनाम।भारत संघ

ई.

और ओआरएस।, [1981] 2 एस. सी. आर. 185 चिन्नाप्पा रेड्डी, जे. ने अनुच्छेद 16 (1) और 16 (4) के अंतर-संबंध की व्याख्या करते हुए कहा कि अनुच्छेद 16 (4) अनुच्छेद 16 (1) के अपवाद की प्रकृति में नहीं है।यह अनुच्छेद 16 (1) का एक पहलू है जो विशेष संदर्भ के साथ अवसर की समानता के विचार को बढ़ावा देता है और आगे बढ़ाता है।

नागरिकों के विशेषाधिकार प्राप्त और वंचित वर्ग।यह इस बात का उदाहरण है कि राज्य को समतावादी और समतावादी के बीच के अंतर को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए।

च

यह मानता है कि अवसर की समानता के अधिकार में विशेषाधिकार प्राप्त लोगों द्वारा प्राप्त शर्तों के तुलनीय या क्षतिपूर्ति के लिए वंचित विशेषाधिकार प्राप्त लोगों का अधिकार शामिल है।अवसर की समानता ऐसी होनी चाहिए जिससे परिणामों की समानता प्राप्त हो, न कि वह जो लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से कम भाग्यशाली लोगों के खिलाफ जीतने में सक्षम बनाता है, भले ही प्रतिस्पर्धा स्वयं जी हो अन्यथा असमान हो।

यह अब एक स्वीकृत न्यायशास्त्र और अभ्यास है कि

कानून के समक्ष समानता और कुछ प्रकार के भेदभाव के निषेध के लिए समान व्यवहार की आवश्यकता नहीं है।समानता का अर्थ है सापेक्ष समानता, अर्थात् समान रूप से व्यवहार करने का सिद्धांत जो समान और असमान हैं जो एच असमान हैं।असमान लोगों के साथ उनकी असमानता के अनुसार अलग तरह से व्यवहार करने की न केवल अनुमति है, बल्कि इसकी आवश्यकता भी है।

एसटी.स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय [कासलीवाल, जे.] 183 अनुच्छेद 30 (1) में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को तैयार करने वाले कानून हालांकि, मनमाने, अभेद्य या अन्यायपूर्ण नहीं होने चाहिए; उनका उद्देश्य और नियोजित साधनों के बीच एक उचित संबंध होना चाहिए।व्यक्तिगत अधिकारों को प्रतिस्पर्धी अल्पसंख्यक हितों के साथ संतुलित करना आवश्यक होगा। सिद्धजभाई मामले में सरकार ने अल्पसंख्यक संचालित कॉलेज को सरकारी उम्मीदवारों के लिए 80 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने और अनुदान-सहायता और मान्यता को रोकने के खतरे के साथ प्रबंधन के लिए केवल 20 प्रतिशत सीटों की अनुमति देने का निर्देश देते हुए अदालत द्वारा अनुच्छेद 30 (1) द्वारा गारंटीकृत मौलिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के रूप में खारिज कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 337 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जा सकता है जिसमें संविधान के प्रारंभ से दस वर्षों के लिए एंग्लो-इंडियन समुदाय को विशेष रियायत प्रदान की गई थी।अनुच्छेद 30 (2) के विपरीत इसने एंग्लो-इंडियन समुदाय को अपने शैक्षणिक संस्थानों के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त करने का सकारात्मक अधिकार प्रदान किया, लेकिन इस शर्त के अधीन कि वार्षिक प्रवेश का कम से कम सी चालीस प्रतिशत अन्य समुदायों के सदस्यों को उपलब्ध कराया जाए।

इन सभी सिद्धांतों और कारकों के आलोक में, और अनुच्छेद 30 (1) के तहत अल्पसंख्यक संबंधों के लिए सुरक्षात्मक उपायों को संविधान द्वारा दिए गए महत्व को ध्यान में रखते हुए, अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को विश्वविद्यालय मानक के अनुरूप संस्थानों के विषय के अल्पसंख्यक चरित्र को बनाए रखने के लिए अपने सामुदायिक उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने का अधिकार है।जिस क्षेत्र में संस्थान सेवा करने का इरादा रखता है, उस क्षेत्र में समुदाय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य इस श्रेणी में प्रवेश को विनियमित कर सकता है।लेकिन किसी भी मामले में ऐसा प्रवेश वार्षिक प्रवेश के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।अल्पसंख्यक ई।

संस्थान अल्पसंख्यक समुदाय के अलावा अन्य समुदायों के सदस्यों को वार्षिक प्रवेश का कम से कम पचास प्रतिशत उपलब्ध कराएंगे।अन्य समुदाय के उम्मीदवारों का प्रवेश विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

*

परिणाम में और बताए गए कारणों के लिए, रिट याचिका (सिविल) सं. 1868

सेंट स्टीफन कॉलेज द्वारा दायर 1980 की अनुमति है।डब्ल्यू. पी. सं.13213-14 एफ का

1984 और 1980 की टी. सी. संख्या 3 को खारिज कर दिया गया है।इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपीलों को उच्च न्यायालय के फैसले को ऊपर बताए गए हद तक संशोधित करने की अनुमति है।हालांकि, इलाहाबाद कृषि संस्थान द्वारा अब तक किए गए प्रवेश में कोई बाधा नहीं आएगी।जिन छात्रों को इस न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार प्रवेश दिया गया है

उन्हें अपना पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जाएगी।

G मामले की परिस्थितियों में, हम लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देते हैं।कासलवाल, जे. मुझे निर्णय से गुजरने का लाभ मिला

मेरे विद्वान भाई के. जे. शेट्टी, जे. उचित सम्मान के साथ मैं सहमत नहीं हो पा रहा हूँ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

एच 184

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जे. शेट्टी ने अपने निर्णय में तथ्यों को निर्धारित किया है

क.

विस्तार से, मैं ऐसे तथ्यों का उल्लेख कर रहा हूं जो इन मामलों में उठाए गए प्रश्नों से निपटने के लिए आवश्यक हैं।

1980 का डब्ल्यू. पी. सं. 1868, डब्ल्यू. पी. सं.13213-14 1984 का मामला और 1980 का हस्तांतरित मामला संख्या 3।

ये सभी मामले सेंट स्टीफंस कॉलेज (संक्षेप में 'कॉलेज') से संबंधित हैं और

इन मामलों के तथ्यों को संक्षेप में निम्नानुसार बताया गया है:सेंट स्टीफंस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध है और इसमें से एक है।

तीन मूल घटक महाविद्यालय।शैक्षणिक वर्ष 1980-81 के लिए, कॉलेज सी ने 'प्रवेश विवरण पत्रिका' प्रकाशित की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया था कि प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन 20 जून, 1980 को या उससे पहले कॉलेज कार्यालय में प्राप्त किए जाने चाहिए।विवरण पुस्तिका में यह भी उल्लेख किया गया था कि महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अंतिम चयन से पहले साक्षात्कार होगा।दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने 22 मई, 1980 को शैक्षणिक सत्र 1980-81 और प्रवेश से संबंधित अन्य संबंधित मामलों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश/डी पंजीकरण की तारीखों पर विचार करने और उनकी सिफारिश करने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया।सलाहकार समिति के गठन को भी अकादमिक परिषद द्वारा मंजूरी दी गई थी।दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा गठित सलाहकार समिति निम्नलिखित रूप में निर्धारित है:शैक्षणिक सत्र 1980-81 के लिए प्रवेश से संबंधित मामलों के लिए।

ई.

" (i) बी. ए. में प्रवेश। (पास)/बी. ए.व्यावसायिक अध्ययन पाठ्यक्रम योग्यता परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत की योग्यता पर आधारित होते हैं।

(ii) B.Com (पास) बी. ए. में प्रवेश। (ऑनर्स) और B.Com

च

(ऑनर्स।) पाठ्यक्रम भी अंकों के आधार पर होते हैं।हालांकि, कॉलेज कुल अंकों के अलावा एक या अधिक व्यक्तिगत विषयों में प्राप्त अंकों को महत्व दे सकता है।

योग्यता परीक्षा।लेकिन जब भी कॉलेज द्वारा अलग-अलग विषयों को महत्व देने का प्रस्ताव किया जाता है, तो इसे कॉलेज प्रॉस्पेक्टस/नोटिस के माध्यम से छात्रों को पहले से सूचित किया जाना चाहिए।

जी.

बोर्ड ताकि प्रवेश चाहने वाले आवेदकों को पहले से पता हो

प्रवेश का आधार।

(iii) सभी स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 जून, 1980 होगी और सभी कॉलेजों द्वारा इसका औपचारिक रूप से पालन किया जाएगा।

एच एस टी।स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय (कासलीवाल, जे.) 185 उपरोक्त सिफारिशों को केंद्रीय प्रवेश ए समिति और कुलपति द्वारा भी स्वीकार किया गया था।

5 जून, 1980 को विश्वविद्यालय ने सभी संबद्ध कॉलेजों के लिए परिपत्र जारी किया जिसमें आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 जून, 1980 निर्धारित की गई थी।परिपत्र में प्रवेश का चरणबद्ध कार्यक्रम भी प्रदान किया गया था।9 जून, 1980 को विश्वविद्यालय ने सभी कॉलेजों के प्राचार्यों के लिए एक और परिपत्र जारी किया जिसमें बी. ए. में प्रवेश के बारे में बताया गया था। (पास)/बी. ए.व्यावसायिक अध्ययन पाठ्यक्रम योग्यता परीक्षा देने वाले देश में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत की योग्यता पर आधारित होते हैं।B.Com में प्रवेश।(पास)/बी. ए. (ऑनर्स) और बी. कॉम।(ऑनर्स।) पाठ्यक्रम अंकों के आधार पर होंगे। हालांकि, कॉलेज योग्यता परीक्षा के कुल अंकों के अलावा एक या अधिक व्यक्तिगत विषयों में प्राप्त अंकों को महत्व दे सकता है। लेकिन जब भी कॉलेज द्वारा व्यक्तिगत विषय (विषयों) को सी वेटेज देने का प्रस्ताव किया जाता है, तो इसे कॉलेज प्रॉस्पेक्टस/नोटिस बोर्ड के माध्यम से छात्रों को पहले से सूचित किया जाना चाहिए ताकि प्रवेश पाने के इच्छुक आवेदकों को प्रवेश का आधार पहले से पता हो।इस परिपत्र में खिलाड़ियों के प्रवेश और सह-पाठ्यक्रम संबंधी विशिष्टताओं के लिए कुछ दिशा-निर्देश भी प्रदान किए गए थे।

डी.

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ द्वारा की गई एक शिकायत पर कि कॉलेज आवेदनों की प्राप्ति के लिए अपना समय निर्धारित करने के साथ-साथ प्रवेश से पहले साक्षात्कार को प्रोत्साहित करके विश्वविद्यालय के कानूनों और अध्यादेशों का उल्लंघन कर रहा था, विश्वविद्यालय और कॉलेज के बीच कुछ पत्राचार हुआ, लेकिन कॉलेज के अधिकारी ई का पालन करने के लिए सहमत नहीं हुए।

विश्वविद्यालय के परिपत्र में।इस स्तर पर राहुल कपूर एक छात्र की तलाश में हैं।

महाविद्यालय में प्रवेश ने महाविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश कार्यक्रम के साथ-साथ महाविद्यालय द्वारा निर्धारित साक्षात्कार परीक्षा की नीति को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में 1980 की रिट याचिका संख्या 790 दायर की।यह रिट याचिका 1980 के हस्तांतरित मामला संख्या 3 का विषय है।सेंट स्टीफंस कॉलेज ने कला के तहत इस न्यायालय के समक्ष 1980 की 1868 की रिट याचिका दायर की।32 एफ.

संविधान से।कॉलेज ने वास्तव में यह रुख अपनाया कि यह एक धार्मिक अल्पसंख्यक-संचालित संस्थान था और विश्वविद्यालय द्वारा 5 और 9 जून, 1980 को जारी किए गए परिपत्र कला के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते थे।30 संविधान से। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ कॉलेज द्वारा दायर 1980 की रिट याचिका संख्या 1868 में एक मध्यस्थ बन गया।इसके बाद प्रवेश वर्ष 1984-85 के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र जी संघ और डॉ. महेश सी. जैन ने रिट याचिका संख्या दायर की। 13213-14 कला के तहत 1984 का।32 कॉलेज के खिलाफ संविधान।इन रिट याचिकाओं में यह कहा गया था कि कॉलेज प्रवेश के संबंध में सभी विश्वविद्यालय नीतियों, नियमों, विनियमों, अध्यादेशों का पालन करने के लिए बाध्य है और कॉलेज को ईसाई छात्रों के पक्ष में वरीयता देने से रोका जाना चाहिए।

महाविद्यालय में प्रवेश।यह आरोप लगाया गया था कि कॉलेज अल्पसंख्यक एच 186 नहीं है

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक संस्थान और वैकल्पिक में यह आगे दलील दी गई कि यह मानते हुए भी कि कॉलेज एक अल्पसंख्यक संस्थान है, यह भेदभाव करने का हकदार नहीं है

कॉलेज के रूप में धर्म के आधार पर छात्रों को सरकार से अनुदान-सहायता मिल रही थी।इस तरह का भेदभाव कला का उल्लंघन था।29 (2) संविधान से।

9 दिसंबर, 1987 के आदेश द्वारा इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की एक पीठ

आई।

यह अभिनिर्धारित किया कि स्टीफन कॉलेज, दिल्ली एक धार्मिक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान होने के नाते, कला के तहत गारंटीकृत संस्थान को प्रशासित करने का अधिकार है।30 (1) संविधान अपने साथ अपनी पसंद के छात्रों के प्रवेश को विनियमित करने का अधिकार रखता है, जिसमें संविधान की व्याख्या के बारे में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, और

इसलिए, याचिकाओं को संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए रखे जाने के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाना चाहिए।उपरोक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए इन मामलों को संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए रखा गया था। जहां तक इस सवाल का सवाल है कि क्या सेंट स्टीफन कॉलेज एक अल्पसंख्यक संचालित संस्थान है, माननीय शेट्टी, जे. ने दलीलों के साथ-साथ विभिन्न कारकों पर विचार करने के बाद माना है कि सेंट स्टीफन कॉलेज की स्थापना और प्रशासन एक अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा किया गया था, अर्थात।ईसाई समुदाय डी जो निर्विवाद रूप से भारत के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में एक धार्मिक अल्पसंख्यक है जहां कॉलेज स्थित है।मैं उपरोक्त निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत हूं और मेरे पास जोड़ने के लिए कुछ नहीं है।

अगला सवाल जो विचार करने की मांग करता है वह यह है कि क्या कॉलेज 5 और 9 जून, 1980 के विश्वविद्यालय के परिपत्रों से बाध्य था?ई कॉलेज ने इन अधिसूचनाओं को मानवाधिकारों का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी है।

उनके उल्लंघन के रूप में मामलों के प्रशासन और प्रबंधन का कॉलेज

कला के तहत प्रदत्त अधिकार।30 (1) संविधान से।पहली आपत्ति 5 जून, 1980 के विश्वविद्यालय के परिपत्र से संबंधित है, जिसमें कॉलेज द्वारा निर्धारित 20 जून, 1980 के बजाय 30 जून, 1980 आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी।दूसरा 9 जून, 1980 के परिपत्र से संबंधित है जिसके द्वारा

च

✓

विश्वविद्यालय ने सभी महाविद्यालयों को निर्देश दिया था कि वे योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर निर्धारित की जाने वाली योग्यता के आधार पर ही छात्रों को प्रवेश दें।कॉलेज के अनुसार उन्हें साक्षात्कार आयोजित करने और इस तरह प्रवेश के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए नामित किया गया था

महाविद्यालय।जहाँ तक महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदनों की जी प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि निर्धारित करने से संबंधित पहले विवाद का संबंध है, इसका बहुत अधिक परिणाम प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इसे विश्वविद्यालय के साथ समायोजन द्वारा विनियमित किया जा सकता है।किसी भी मामले में पहले प्रश्न का भाग्य साक्षात्कार के दूसरे प्रश्न पर निर्भर करता है जैसे कि कॉलेज आयोजित करने का हकदार है।

प्रवेश से पहले साक्षात्कार, फिर आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को कॉलेज द्वारा निर्धारित एच प्रवेश को अंतिम रूप देने से पहले साक्षात्कार के लिए पर्याप्त समय देते हुए जल्दी रखा जाना चाहिए।

} एसटी.स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय [कासलीवाल, जे.] 187 इस संबंध में कॉलेज की ओर से तर्क यह है कि यह 100 से अधिक वर्षों से अपने स्वयं के प्रवेश कार्यक्रम का पालन कर रहा है और

बिना किसी आपत्ति के साक्षात्कार के तरीके का पालन किया गया है और इसके परिणामस्वरूप संस्थान की सर्वांगीण छवि और उत्कृष्टता को बढ़ावा मिला है।साक्षात्कार आयोजित करने में किसी भी दुर्भावना का कोई आरोप नहीं है और यह वर्तमान समस्याओं के बारे में अपनी सामान्य जागरूकता के साथ विषय के बारे में उम्मीदवार के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए किया जाता है।कॉलेज के अनुसार इस तरह के बी साक्षात्कार ईसाई छात्रों को 10 प्रतिशत तक की छूट देकर वरीयता देने के अपने दोहरे उद्देश्यों को पूरा करता है जो ईसाई के अल्पसंख्यक समुदाय के हित को कम करता है जिनके लाभ के लिए कॉलेज की स्थापना की गई है और दूसरा, भविष्य के शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा का चयन करना है।इस संबंध में आगे यह तर्क दिया गया है कि छात्रों का चयन करने का अधिकार

प्रवेश प्रशासन का एक हिस्सा है।छात्रों के प्रवेश में कॉलेज के प्रबंधन का पूरा अधिकार है और इसे नियंत्रण से मुक्त छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि अल्पसंख्यक संस्थान छात्रों को उनके विचारों के अनुसार प्रवेश दे सकें कि सामान्य रूप से समुदाय और विशेष रूप से संस्थान के हितों की सर्वोत्तम सेवा कैसे की जाएगी।साक्षात्कार भी आवश्यक है क्योंकि कुछ परीक्षा बोर्डों द्वारा अद्भुत रूप से उच्च अंक दिए जाते हैं और यह कॉलेज के हित में नहीं होगा कि छात्रों को केवल योग्यता परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों डी के आधार पर प्रवेश दिया जाए।

इसका विरोध विश्वविद्यालय के साथ-साथ छात्रों की ओर से भी किया गया था

संघ ने कहा कि प्रवेश के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि निर्धारित करने वाला 5 जून, 1980 का पहला परिपत्र विश्वविद्यालय के सभी संबद्ध कॉलेजों में प्रवेश तिथियों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए किया गया था और इसे समग्र रूप से छात्र समुदाय के हित में फायदेमंद माना गया था।जहां तक 9 जून, 1980 के दूसरे परिपत्र का संबंध है, विश्वविद्यालय को एक समान मानक लागू करने में न्यायसंगत ठहराया गया था कि प्रवेश योग्यता परीक्षाओं में आवेदकों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाना चाहिए और यह चयन में मनमानेपन को बाहर कर देगा और सभी आवेदकों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करेगा।यह प्रस्तुत किया गया है कि विचाराधीन परिपत्र स्वभाव में नियामक थे और कला के तहत गारंटीकृत किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं करते थे।30 (1) सेंट स्टीफन कॉलेज को एक अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में संविधान का।यह आगे तर्क दिया गया कि एक बार एक शैक्षणिक संस्थान से संबद्ध है

ई.

च

विश्वविद्यालय या ऐसे विश्वविद्यालय का घटक बनने पर उसे ऐसे संस्थानों में प्रवेश के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए विनियमों का पालन करना होगा, चाहे वे अल्पसंख्यक या गैर-अल्पसंख्यक संस्थान हों।विश्वविद्यालय को शिक्षा के स्तर को विनियमित करने का अधिकार है और किसी शैक्षणिक संस्थान में छात्रों का प्रवेश इस अधिकार का एक हिस्सा है।सेंट स्टीफन कॉलेज अल्पसंख्यक संस्थान को दिए गए प्रबंधन के विशेष अधिकार की आड़ में छात्रों को प्रवेश देने के लिए एक अलग मानक नहीं अपना सकता है।यह तर्क दिया गया है कि प्रवेश के मामले में एकरूपता एक है

एच.

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

(188

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक कॉलेज में शामिल होकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार का एक आवश्यक सहवर्ती और एक समान पैटर्न समग्र रूप से छात्र समुदाय के हित की बेहतर सेवा करेगा।कॉलेज ने यह नहीं बताया है कि कौन से परीक्षा बोर्ड शानदार रूप से उच्च अंक दे रहे हैं और कॉलेज द्वारा यह नहीं दिखाया गया है कि वे साक्षात्कार के तरीके का सहारा लेकर इस तरह की समस्या का सामना कैसे और किस तरह से कर सकते हैं।महाविद्यालय द्वारा यह भी नहीं दिखाया गया है कि साक्षात्कार के लिए बी के कितने प्रतिशत अंक रखे गए हैं और क्या यह इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मानदंडों और सिद्धांतों के अनुरूप है जो बड़ी संख्या में साक्षात्कार के लिए अंकों के अधिकतम प्रतिशत को सीमित करते हैं।यह प्रस्तुत किया गया है कि अल्पसंख्यक संस्थानों का उद्देश्य शिक्षा के मानकों में एकरूपता बनाए रखना भी है।स्नातक स्तर पर अध्ययन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए एकमात्र प्रासंगिक विचार उम्मीदवार सी द्वारा अपनी योग्यता परीक्षा में दिखाए गए शैक्षणिक प्रदर्शन पर होना चाहिए।यदि उम्मीदवार ने उच्च माध्यमिक या 10 + 2 परीक्षा के स्तर पर शैक्षणिक मानकों में अपनी क्षमता और विशिष्टता दिखाई है, तो उसे साक्षात्कार के तरीके का सहारा लेकर उच्च अध्ययन जारी रखने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।यह भी तर्क दिया गया है कि एक बार जब सेंट स्टीफन कॉलेज, हालांकि एक अल्पसंख्यक संस्थान है, राज्य से अनुदान प्राप्त करता है, तो इसे छात्रों को प्रवेश देने के मामले में डी में अन्य गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों के अनुरूप होना चाहिए और एक समान नियम का पालन करना होगा।

*

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित।

ईसाई समुदाय से संबंधित उम्मीदवारों को लाभ या वरीयता देने के प्रश्न की कला के प्रावधानों से निपटने के दौरान अलग से जांच की जाएगी।29 (2) और कला।30 (1) संविधान से।मैं करूँगा।

ई.

वर्तमान में संविधान के उपरोक्त अनुच्छेदों से स्वतंत्र रूप से सेंट स्टीफन कॉलेज द्वारा प्रवेश के लिए एक नियम के रूप में रखे गए साक्षात्कार की वैधता से निपटना है।कॉलेज ने रिट याचिकाओं (सिविल) संख्या में अपने जवाबी हलफनामे में कहा।13213 14

1984 ने साक्षात्कार के तरीके को इस आधार पर उचित ठहराया है कि 26 से अधिक उच्च माध्यमिक परीक्षा निकाय हैं जो व्यापक रूप से विघटित हैं।

च

अंकन के मानक और विभिन्न श्रेणीकरण प्रणालियाँ।साक्षात्कार विभिन्न परीक्षा/श्रेणीकरण प्रणाली से आने वाले छात्रों की वास्तविक योग्यता निर्धारित करने में समानता का एक मूल्यवान तरीका प्रदान करता है।यह भी आरोप लगाया गया है कि परीक्षाओं में कदाचार अपनाया जाता है और नकली और जाली प्रमाण पत्र और अंक-पत्र लेना व्यापक रूप से प्रचलित है।साक्षात्कार की विधि जी द्वारा कॉलेज एक उम्मीदवार की पेपर योग्यता के स्थान पर वास्तविक योग्यता का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रदान करता है।आवेदकों के पास विषयों का अलग-अलग संयोजन होता है और कठिन व्यक्ति ने विज्ञान विषय में बहुत अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त किए होंगे, लेकिन हो सकता है कि वे इतिहास या अन्य विषयों में प्रवेश चाहते हों।

अँग्रेजी।एक व्यक्तिगत साक्षात्कार इस तरह के विषय के लिए उनकी रुचि और योग्यता का पता लगाने में मदद करता है।साक्षात्कार द्वारा, यह पता लगाया जा सकता है कि क्या आवेदक एच अंग्रेजी के माध्यम से व्याख्यान का पालन करने में सक्षम होगा। साक्षात्कार से, यह है

} एसटी.स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय [कासलीवाल, जे.] 189 ने निर्णय लिया कि क्या उम्मीदवार में कॉलेज के शैक्षणिक समुदाय की समृद्धि और 'ए' विविधता में योगदान करने की योग्यता है।यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि कॉलेज के संस्थापक इसे कभी भी केवल शिक्षण की दुकान नहीं मानते हैं, बल्कि एक ऐसे वातावरण में आस्था, फेलोशिप और फलदायी अध्ययन पर आधारित एक शैक्षणिक समुदाय के रूप में है जिसमें कॉलेज एक राष्ट्रीय सूक्ष्म जगत के रूप में काम कर सकता है और देश के सभी हिस्सों से संबंधित विभिन्न जाति और पंथ के छात्र सीख सकते हैं और एक साथ रह सकते हैं, एक साथ बातचीत कर सकते हैं और एक साथ रह सकते हैं।

इस प्रकार एक वास्तविक राष्ट्रीय एकीकरण होता है।

कॉलेज की ओर से आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि कॉलेज द्वारा प्रवेश के लिए चयन की प्रक्रिया मनमाना नहीं है।यह एक अत्यंत विस्तृत और सावधानीपूर्वक नियोजित प्रक्रिया है, जिसका विवरण उत्तर में दिया गया है।चयन प्रक्रिया में, चयन समिति सी के प्रत्येक सदस्य उम्मीदवारों के प्रदर्शन को श्रेणीबद्ध करते हैं और अध्ययन के ऐसे पाठ्यक्रम के लिए साक्षात्कार के अंत के बाद, सदस्यों की राय को ध्यान में रखा जाता है और सर्वसम्मति से प्रवेश के लिए चुने गए उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार की जाती है।उपरोक्त प्रक्रिया ईसाई के साथ-साथ गैर-ईसाई उम्मीदवारों या अखिल भारतीय परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले या डी खिलाड़ी के आधार पर प्रवेश लेने वाले व्यक्ति के मामले में बिना किसी भेदभाव के लागू की जाती है।महाविद्यालय में प्रवेश के इन तौर-तरीकों का पालन 100 से अधिक वर्षों से किया जा रहा है और ऐसी नीति को बंद करने का कोई कारण नहीं है जो इतने लंबे समय से इतनी मूल्यवान साबित हुई है और समय की कसौटी पर खरी उतरी है।

यह विवादित नहीं हो सकता है कि विश्वविद्यालय उन कॉलेजों के संबंध में नियामक ई उपायों को निर्धारित कर सकता है जो ऐसे विश्वविद्यालय से संबद्ध या घटक हैं, यदि ऐसे उपाय शैक्षणिक संस्थान को शिक्षा के लिए एक प्रभावी वाहन बनाने के लिए उचित और अनुकूल हैं, तो उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती है।यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम 1922, क़ानून और अध्यादेशों और नियमों और एफ द्वारा शासित है।

इसके तहत बनाए गए नियम।विश्वविद्यालय के अध्यादेश XVIII में प्रत्येक महाविद्यालय में एक कर्मचारी परिषद का प्रावधान है। प्राचार्य कर्मचारी परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं।कर्मचारी परिषद के कार्यों में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नीति के ढांचे के भीतर प्रवेश नीति के निर्माण के संबंध में सिफारिशें करना शामिल है।इससे पता चलता है कि कोई भी कॉलेज अपनी प्रवेश नीति निर्धारित नहीं कर सकता है ताकि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित जी नीति के साथ टकराव हो।विश्वविद्यालय ने सभी कॉलेजों को योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर छात्रों को प्रवेश देने का सामान्य निर्देश जारी किया है।हमारे देश में मौजूद वर्तमान स्थिति में एक

ना.

उच्च माध्यमिक या 10 + 2 की योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद डिग्री कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए छात्रों की भारी भीड़।ऐसे कॉलेजों की कमी है और छात्रों की संख्या बड़ी होने के कारण कठिन एच 190 है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए एक प्रतियोगिता।इन परिस्थितियों में यदि दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक समान नियम निर्धारित किया है कि उसके संबद्ध और घटक कॉलेजों में प्रवेश के उद्देश्य से, योग्यता प्राप्त करने वाले परीक्षा राष्ट्र में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए, तो इसे अनुचित होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है।सेंट स्टीफन कॉलेज इस मायने में एक पेशेवर कॉलेज नहीं है कि यह इंजीनियरिंग या चिकित्सा जैसी कोई तकनीकी शिक्षा प्रदान नहीं करता है। यह अन्य सभी कला, विज्ञान और वाणिज्य महाविद्यालयों की तरह है जो स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर तक इन विषयों में अध्ययन प्रदान करते हैं और इस तरह महाविद्यालय में छात्रों को प्रवेश देने के मामले में अलग व्यवहार का दावा नहीं कर सकते हैं। यदि विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद जैसे निकायों ने योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश के लिए नियम को मंजूरी दे दी है, तो सी द्वारा यह रुख अपनाए जाने पर आपत्ति नहीं की जा सकती है कि यह उस ईसाई समुदाय के हित के खिलाफ है जिसके हित के लिए कॉलेज की स्थापना की गई थी।हालांकि कॉलेज की ओर से साक्षात्कार की विधि को उचित ठहराते हुए एक विस्तृत जवाब दिया गया है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा कि इसमें यह उल्लेख नहीं किया गया है कि साक्षात्कार के लिए कितने प्रतिशत अंक रखे जाते हैं और योग्यता परीक्षा के लिए कितने अंक रखे जाते हैं।इस संबंध में कॉलेज द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अनुसार साक्षात्कार के लिए बुलाए गए संभावित उपयुक्त उम्मीदवारों की एक डी सूची तैयार की जाती है जो आम तौर पर 1 के आधार पर होती है:4 या 1:5 कला के लिए और विज्ञान के छात्रों के लिए उच्चतर।इस प्रकार साक्षात्कार में बुलाने के लिए मानदंड या आधार योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के अलावा और कुछ नहीं है।इसके बाद समिति का प्रत्येक सदस्य अध्ययन के प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए साक्षात्कार की समाप्ति के बाद उम्मीदवारों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, सभी सदस्यों की राय को ध्यान में रखा जाता है और सर्वसम्मति से प्रवेश के लिए चुने गए उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार की जाती है।कॉलेज द्वारा अपनाई गई साक्षात्कार की यह विधि यह दर्शाती है कि साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों में से अंतिम चयन सौ प्रति cent.i.e पर आधारित होता है. केवल साक्षात्कार के आधार पर और इस स्तर पर यह नहीं दिखाया गया है कि योग्यता में प्राप्त अंकों को कितना वजन/प्रतिशत दिया जाता है।

परीक्षा और साक्षात्कार के लिए आनुपातिक रूप से कितना।मेरी विनम्रता में

च

राय यह है कि चयन की यह विधि मनमाना चयन के परिणामस्वरूप पाउंड है।महाविद्यालय के अनुसार साक्षात्कार में बुलाने के लिए कट-ऑफ अंक निर्धारित किए जाते हैं और 1980 के डब्ल्यू. पी. सं. 1868 में दिनांक 27 जून, 1984 के अनुलग्नक I के अनुसार

साइंस स्ट्रीम के लिए यह 83 प्रतिशत, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए 80 प्रतिशत, मानविकी के लिए 77 प्रतिशत है।अब इन धाराओं में से प्रत्येक के लिए उम्मीदवारों को उपलब्ध सीटों की संख्या का चार या पांच गुना जी साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है।इसके बाद, यदि उनका चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाता है तो एक अत्यधिक मेधावी छात्र

90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र को प्रवेश नहीं मिल सकता है जबकि कट-ऑफ स्तर के करीब अंक प्राप्त करने वाले छात्र को कॉलेज में प्रवेश मिल सकता है।यह स्पष्ट करने के लिए कि क्या विज्ञान स्ट्रीम में 50 रिक्तियां हैं और 200 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है जिन्होंने विज्ञान स्ट्रीम में कम से कम 83 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं।

एच योग्यता परीक्षा, छात्र संख्या में भी योग्यता में उच्च स्थान पर हैं।1 50 एसटी तक।

स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय [कासलीवाल, जे.] 191 का चयन नहीं किया जा सकता है और जो संख्या में खड़े हैं। 150 200 तक केवल साक्षात्कार के आधार पर प्रवेश ए प्राप्त कर सकते हैं।मान लीजिए कि इसमें कुछ नहीं कहा गया है।

कॉलेज द्वारा जारी विवरण पत्रिका के अनुसार साक्षात्कार के लिए कितने प्रतिशत अंक रखे जाते हैं।इस संबंध में वह पूरी तरह से चुप है।यह उत्तर में नहीं दिखाया गया है और न ही तर्क के दौरान स्पष्ट किया गया है कि साक्षात्कार के लिए कोई भी अंक योग्यता अंकों में जोड़े जाते हैं।जिन उम्मीदवारों का चयन नहीं किया जाता है, उन्हें ऐसे अंकों के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है।विवरण पत्रिका में केवल यह कहा गया है कि अंतिम बी चयन साक्षात्कार के बाद किया जाएगा।इससे पता चलता है कि प्रबंधन या चयन निकाय का प्रवेश स्वीकार करने या अस्वीकार करने पर पूरा नियंत्रण है

अपनी पसंद के अनुसार और योग्य उम्मीदवारों में से कोई भी उम्मीदवार।साक्षात्कार के आधार पर प्रवेश से इनकार किया जा सकता है।

ग

आर. चित्रलेखा और अन्र में।वी.मैसूर राज्य और अन्य।, [1964] 6 एससीआर 638

संविधान पीठ ने मौखिक रूप से चयन के प्रश्न पर विचार किया।सरकार ने तकनीकी शिक्षा निदेशक मैसूर को एक पत्र भेजा,

बैंगलोर ने उन्हें सूचित किया कि यह निर्णय लिया गया है कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए वैकल्पिक विषयों में परीक्षा के लिए अधिकतम अंकों का 25 प्रतिशत साक्षात्कार के अंकों के रूप में तय किया जाएगा; इसने साक्षात्कार में अंक आवंटित करने के लिए मानदंड भी निर्धारित किए हैं।चयन समिति ने वैकल्पिक विषयों में कुल अंकों को अधिकतम 300 अंकों में बदल दिया और साक्षात्कार के लिए अधिकतम अंक 75 निर्धारित किए।जिन उम्मीदवारों के प्रवेश के लिए आवेदन खारिज कर दिए गए थे, उनमें से कुछ ने अनुच्छेद के तहत रिट याचिकाएं दायर कीं।226 मैसूर उच्च न्यायालय में संविधान।उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई विभिन्न दलीलों पर विचार करने के बाद यह अभिनिर्धारित किया कि पिछड़ेपन को परिभाषित करने वाले आदेश वैध थे और छात्रों के साक्षात्कार के लिए निर्धारित मानदंड अच्छे थे, लेकिन यह अभिनिर्धारित किया कि चयन समिति ने उसे प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग किया था और उस निष्कर्ष पर आयोजित साक्षात्कार को दरकिनार कर दिया और निर्देश दिया कि आवेदकों का सरकार द्वारा निर्धारित योजना के अनुसार नए सिरे से साक्षात्कार किया जाएगा।याचिकाकर्ताओं में से दो अपील दायर करके इस अदालत में आए एफ

इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति द्वारा।अपीलार्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि साक्षात्कार द्वारा चयन स्वाभाविक रूप से कला में सन्निहित समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल है।14 संविधान के अनुसार, जो भी वस्तुनिष्ठ परीक्षा निर्धारित की गई हो, अंतिम विश्लेषण में अंकों का पुरस्कार चयन समिति की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर छोड़ दिया जाता है और इसलिए, यह भेदभाव और हेरफेर के लिए पर्याप्त जगह देता है।न्यायालय ने इस तरह के व्यापक जी तर्क को स्वीकार नहीं किया।यह देखा गया कि अदालत के समक्ष बेहतर और अधिक वैज्ञानिक सामग्री रखे बिना यह नहीं माना जा सकता है कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के अलावा साक्षात्कार द्वारा चयन अपने आप में बुरा उल्लंघन है।14 संविधान से।

इस मामले को इस एच 7 की संविधान पीठ द्वारा फिर से विस्तार से निपटाया गया था।

* 192

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अजय हसिया बनाम में एक अदालत।खालिद मुजीब सहरावर्दी और अन्य।आदि। [1981] 2 एस. सी. आर. 79।इस मामले में सवाल रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, श्रीनगर में प्रवेश के बारे में था।प्रवेश के नियमों के अनुसार तुलनात्मक योग्यता का निर्धारण लिखित प्रवेश परीक्षा और मौखिक परीक्षा आयोजित करके किया जाना था और अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के विषयों में लिखित परीक्षा के लिए आवंटित अंक 100 थे, जबकि मौखिक परीक्षा के लिए आवंटित अंक 50 निम्नानुसार विभाजित थेः(i) सामान्य ज्ञान और जागरूकता-15; (ii) विशिष्ट क्षेत्रों की व्यापक समझ।

+

नाम-15; (iii) अतिरिक्त-पाठ्यचर्या गतिविधियाँ-10 और (iv) सामान्य व्यक्तिगत विशेषता-10, जो कुल मिलाकर-50 है। न्यायालय ने कॉलेज में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए मौखिक परीक्षा की वैधता के बारे में प्रश्न को एक अनुमेय परीक्षा के रूप में माना।याचिकाकर्ता 'सी' की ओर से यह तर्क दिया गया कि मौखिक परीक्षा प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता के मूल्यांकन के उचित मानदंड का वहन नहीं करती है और यह एक अत्यधिक व्यक्तिपरक और प्रभाववादी परीक्षा है जहां परिणाम कई अनिश्चित और अभेद्य कारकों जैसे कि साक्षात्कारकर्ताओं की प्राथमिकताओं और पूर्वाग्रहों, उनके दृष्टिकोण और दृष्टिकोण, उनकी पूर्व कल्पित धारणाओं और विशिष्टताओं से प्रभावित होने की संभावना है और यह दुरुपयोग करने में भी सक्षम है क्योंकि यह भेदभाव, हेरफेर और भाई-भतीजावाद के लिए गुंजाइश छोड़ता है जो एक साक्षात्कार के आवरण के तहत अज्ञात रह सकता है और इसके अलावा केवल कुछ मिनटों के लिए चलने वाले साक्षात्कार के दौरान एक उम्मीदवार की क्षमता और क्षमता का आकलन करना संभव नहीं है और इसलिए, चयन किया जाता है।14. न्यायालय ने टिप्पणी कीःयह कि इस आलोचना को पूरी

तरह से निराधार नहीं कहा जा सकता है और ई यह एक ऐसे दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसकी निश्चित रूप से कुछ वैधता है। न्यायालय ने तब "लोक प्रशासन में लोक प्रशासन" पर पुस्तक से निम्नलिखित अंश का हवाला दिया।

$

> 1

एम. पी. शर्मा द्वारा सिद्धांत और अभ्यासः

" साक्षात्कार के मौखिक परीक्षण की इसकी व्यक्तिपरकता और अनिश्चितता के आधार पर बहुत आलोचना की गई है।अलग-अलग साक्षात्कारकर्ताओं के पास अच्छे व्यक्तित्व के बारे में अपनी धारणाएँ होती हैं।कुछ लोगों के लिए, इसमें किसी भी चीज़ के बजाय आकर्षक शारीरिक रूप और पोशाक अधिक होती है, और उनके साथ हवादार और चमकदार प्रकार के उम्मीदवार उच्च अंक प्राप्त करते हैं जबकि खुरदरे बिना कटे हीरे अनुचित हो सकते हैं।साक्षात्कार का वातावरण कृत्रिम होता है और कुछ उम्मीदवारों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने से रोकता है।इसकी अवधि कम होती है, हिट-या-मिस प्रकार के कुछ प्रश्न, जो रखे जाते हैं, उम्मीदवार के वास्तविक मूल्य को प्रकट करने में विफल हो सकते हैं।यह कहा गया है कि भगवान एक आदमी के मूल्य का न्याय करने के लिए पूरे जीवन का समय लेते हैं जबकि साक्षात्कारकर्ताओं को इसे एक घंटे के एक चौथाई में करना होता है।यहां तक कि सबसे अच्छा होने पर भी, सामान्य प्रकार का साक्षात्कार उम्मीदवार के व्यक्तित्व के सतही पहलुओं जैसे उपस्थिति, बोलने की शक्ति और सामान्य पते को प्रकट करता है।

च

}

जी.

एच एस टी।स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय [कासलीवाल, जे.] 193 नेतृत्व, कौशल, सामर्थ्य आदि के गहरे लक्षण काफी हद तक अज्ञात हैं।साक्षात्कार अक्सर नीरस बातचीत की प्रकृति में होता है।अंकन परीक्षक से परीक्षक में बहुत भिन्न होता है। साक्षात्कार परिणामों के विश्लेषण से पता चलता है कि एक ही सेवा के लिए एक से अधिक बार प्रतिस्पर्धा करने वाले उम्मीदवारों को दिए गए अंक आश्चर्यजनक रूप से भिन्न होते हैं।यह सब दर्शाता है कि साक्षात्कार परीक्षा में अवसर का एक बड़ा तत्व है।यह एक गंभीर मामला बन जाता है जब बी मौखिक परीक्षण के लिए सौंपे गए अंक प्रतियोगिता में कुल अंकों का एक उच्च अनुपात बनाते हैं।

न्यायालय ने आगे कहाःओल ग्लेन स्टाल ने "लोक कार्मिक प्रशासन-सी" पर अपनी पुस्तक में बताया है कि मौखिक परीक्षण विधि के तीन नुकसान हैं, अर्थात् (1) वैध और विश्वसनीय मौखिक परीक्षण विकसित करने में कठिनाई; (2) मौखिक परीक्षण पर समीक्षा योग्य रिकॉर्ड हासिल करने में कठिनाई; और (3) सार्वजनिक।

राजनीतिक प्रभाव के प्रयास के लिए एक माध्यम के रूप में मौखिक परीक्षण का संदेह "और हम अन्य भ्रष्ट, भाई-भतीजावादी या बाहरी विचारों को जोड़ सकते हैं।विद्वान लेखक तब एक अत्यधिक बोधगम्य और महत्वपूर्ण डी अंश को जोड़ने के लिए आगे बढ़ता हैः

" मौखिक परीक्षा अतीत में इसके दुरुपयोग की सीमा तक प्रत्यक्ष अनुपात में विफल रही है।यह एक नाजुक उपकरण है और अक्षम हाथों में एक खतरनाक उपकरण है।इसके सफल उपयोग की पहली शर्त इसकी सीमाओं की पूर्ण मान्यता है।सबसे विपुल में से एक

ई.

मौखिक में त्रुटि के स्रोत परीक्षकों की ओर से साक्ष्य की प्रकृति को समझने और जो प्रासंगिक, भौतिक और विश्वसनीय था और जो नहीं था, उसके बीच भेदभाव करने में विफलता रही है।यह भी याद रखना चाहिए कि सबसे अच्छा मौखिक साक्षात्कार किसी व्यक्ति के कुल व्यवहार के केवल एक बहुत छोटे हिस्से के विश्लेषण का अवसर प्रदान करता है।किसी व्यक्ति के कुल व्यक्तित्व पैटर्न के बारे में एकल साक्षात्कार से सामान्यीकरण बार-बार गलत साबित हुए हैं।

च

" लेकिन, इन सभी आलोचनाओं के बावजूद, मौखिक साक्षात्कार कैंडी जी तिथियों की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए एक पूरक परीक्षण के रूप में प्रचलित है, जहां व्यक्तिगत लक्षणों का परीक्षण आवश्यक माना जाता है।व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए एक परीक्षण के रूप में इसकी प्रासंगिकता रही है

इस न्यायालय के कई निर्णयों में मान्यता प्राप्त है जो हम पर बाध्यकारी हैं।इस न्यायालय के समक्ष आए मुद्दे पर पहले मामले में, आर. चित्रा लेखा और अन्य बनाम।मैसूर राज्य और अन्य इस न्यायालय ने इंगित कियाःएच.

:

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

194

सर्वोच्च न्यायालय-रिपोर्ट

" शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की क्षमता और क्षमता के परीक्षण के तरीके के संबंध में अलग-अलग विचार हैं।

क.

7

* $

महाविद्यालयों में प्रवेश।रूढ़िवादी शिक्षाविद वार्षिक परीक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों के साथ खड़े हैं।द.

राय की आधुनिक प्रवृत्ति अन्य अतिरिक्त परीक्षणों पर जोर देती है, जैसे कि साक्षात्कार, प्रदर्शन से लेकर पाठ्येतर गतिविधियाँ, व्यक्तित्व परीक्षण, मनोरोग परीक्षण आदि। जाहिर है कि हम यह तय करने की स्थिति में नहीं हैं कि कौन सी विधि बेहतर है या कौन सी सही है चयन की योजना, हालांकि, वास्तव में यह कागज पर हो सकती है, व्यवहार में इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।यह कि यह दुरुपयोग करने में सक्षम है, इसे रद्द करने का आधार नहीं है।जब तक आदेश प्रासंगिक वस्तुनिष्ठ मानदंड निर्धारित करता है और योग्य व्यक्तियों को चयन की व्यस्तता सौंपता है, तब तक यह न्यायालय स्पष्ट रूप से इस मामले में कुछ नहीं कह सकता है।

एस.

और इस दृष्टिकोण पर मौखिक साक्षात्कार परीक्षा को अप्रासंगिक या मनमाना बताते हुए आयोजित करने से इनकार कर दिया।इस न्यायालय ने ए. पीरियाकरुप्पन बनाम में भी इसका उल्लेख किया था।तमिलनाडु राज्य और अन्य।:

डी.

" अधिकांश मामलों में, पहली धारणा अंतिम धारणा होना आवश्यक नहीं है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में, हम याचिकाकर्ताओं की इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि इस देश में प्रचलित साक्षात्कार की प्रणाली इतनी दोषपूर्ण है कि इसे बनाने के लिए

>

बेकार "

ई.

1

1

.इसलिए, याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि मौखिक साक्षात्कार परीक्षा इतनी दोषपूर्ण है कि लिखित परीक्षा के अलावा मौखिक साक्षात्कार के आधार पर प्रवेश के लिए उम्मीदवारों का चयन मनमाना माना जाना चाहिए।

मौखिक साक्षात्कार परीक्षा निस्संदेह उम्मीदवारों की क्षमता और क्षमता का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए बहुत संतोषजनक परीक्षा नहीं है, लेकिन

च

व्यक्तिगत विशेषताओं और लक्षणों को मापने के लिए किसी भी बेहतर परीक्षण के अभाव में, मौखिक साक्षात्कार परीक्षण को, वर्तमान स्तर पर, तर्कहीन या अप्रासंगिक नहीं माना जाना चाहिए, हालांकि यह व्यक्तिपरक है और पहली छाप पर आधारित है, इसका परिणाम कई अनिश्चित कारकों से प्रभावित होता है और यह दुरुपयोग करने में सक्षम है।तथापि, हम यह इंगित करना चाहेंगे कि महाविद्यालय में प्रवेश के मामले में या सार्वजनिक रोजगार के मामले में भी, वर्तमान में आयोजित मौखिक साक्षात्कार परीक्षा को एक विशेष परीक्षा के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि इसका सहारा केवल एक अतिरिक्त या पूरक परीक्षा के रूप में लिया जा सकता है और इसके अलावा, यह देखने के लिए बहुत सावधानी बरती जानी चाहिए कि मौखिक साक्षात्कार परीक्षा आयोजित करने के लिए नियुक्त किए गए व्यक्ति उच्च निष्ठा, क्षमता और योग्यता वाले व्यक्ति हैं।

.

जी.

न्यायालय ने तब इस प्रश्न की जांच की कि भले ही मौखिक साक्षात्कार हो सकता है

एच.

7 एसटी.स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय (कासलीवाल, जे.) 195 ने सैद्धांतिक रूप से एक कॉलेज ए में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए एक वैध परीक्षा के रूप में माना, क्या यह मनमाना और अनुचित था क्योंकि अंक

मौखिक साक्षात्कार के लिए आवंटित अंक लिखित परीक्षा के लिए आवंटित अंकों की तुलना में बहुत अधिक थे।मौखिक साक्षात्कार के लिए आवंटित अंक लिखित परीक्षा के लिए आवंटित 100 की तुलना में 50 थे, ताकि मौखिक साक्षात्कार के लिए आवंटित अंक चयन करने के उद्देश्य से ध्यान में रखे गए कुल अंकों की संख्या का 33 1/3% हो।इस बी के संबंध में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि मौखिक साक्षात्कार परीक्षा में कमियों और कमियों और परीक्षा में प्रचलित शर्तों को ध्यान में रखते हुए

देश में, विशेष रूप से जब नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है और भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद बहुत बढ़ रहा है, तो मौखिक साक्षात्कार के लिए लिखित परीक्षा में आवंटित अंकों की तुलना में उच्च प्रतिशत अंकों का आवंटन किया जाता है।

परीक्षण, न्यायालय द्वारा मनमानेपन से मुक्त के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।सी कोर्ट ने तब इस तथ्य पर ध्यान दिया कि आई. ए. एस., आई. एफ. एस. और आई. पी. एस. के लिए उम्मीदवारों के चयन के मामले में भी जहां उम्मीदवार का व्यक्तित्व और उसकी व्यक्तिगत विशेषताएँ और लक्षण चयन के उद्देश्य के लिए बेहद प्रासंगिक हैं, मौखिक साक्षात्कार के लिए आवंटित अंक 250 हैं जबकि लिखित परीक्षा के लिए 1800 अंक होते हैं जो चयन करने के उद्देश्य से विचार में लिए गए कुल अंकों का केवल 12.2% होता है।न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया कि मौखिक साक्षात्कार के लिए कुल अंकों के 33 1/3 के रूप में उच्च प्रतिशत का आवंटन प्रवेश प्रक्रिया को संक्रमित करने के रूप में नुकसान हुआ

मनमानी।इस प्रकार न्यायालय का विचार था कि मौजूदा परिपथ स्थितियों के तहत मौखिक साक्षात्कार के लिए कुल अंकों के 15 प्रतिशत से अधिक का आवंटन मनमाना और अनुचित होगा और इसे ई के रूप में निरस्त किया जा सकता है।

संवैधानिक रूप से अमान्य।यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा कि अजय हासिया के मामले (ऊपर) में भी उनके प्रभुओं ने स्पष्ट रूप से यह विचार रखा कि कमियों को ध्यान में रखते हुए और

मौखिक साक्षात्कार परीक्षा में कमियाँ और परीक्षा में प्रचलित स्थितियाँ

देश, विशेष रूप से जब नैतिक मूल्यों और भ्रष्टाचार में गिरावट आ रही है

और भाई-भतीजावाद बहुत बढ़ रहा है, लिखित परीक्षा में आवंटित अंकों की तुलना में मौखिक साक्षात्कार के लिए उच्च प्रतिशत अंकों का आवंटन, न्यायालय द्वारा मनमानेपन से मुक्त के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।तब यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मौजूदा परिस्थितियों में मौखिक साक्षात्कार के लिए कुल अंकों के 15 प्रतिशत से अधिक का आवंटन संवैधानिक रूप

से अमान्य होने के कारण रद्द किया जा सकता है।यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि सेंट स्टीफंस जी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का एक घटक कॉलेज है और विश्वविद्यालय ने

1 {

9 जून, 1981 को विवादित अधिसूचना जारी की गई जिसके द्वारा एक समान नियम बनाया गया है कि विश्वविद्यालय के सभी संबद्ध और घटक कॉलेजों में प्रवेश योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाना चाहिए।कॉलेज द्वारा लिए गए रुख के अनुसार ईसाई समुदाय से संबंधित केवल 6 से 10 प्रतिशत छात्रों को प्रवेश मिलता है और बाकी गैर-ईसाई समुदायों से संबंधित एच छात्र हैं।

!

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

196

इस प्रकार हमें इस बात की जांच करनी होगी कि कॉलेज द्वारा अपनाई गई वाइवा वॉस की यह विधि उचित हो सकती है या नहीं, जो गैर-ईसाई समुदायों से संबंधित 90 से 94 प्रतिशत में से अपनी पसंद के छात्रों को प्रवेश देने में कॉलेज प्रबंधन को स्पष्ट स्वतंत्रता देता है।जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है कि कॉलेज ने न तो विवरण पत्रिका में उल्लेख किया है और न ही न्यायालय के समक्ष रखे गए किसी काउंटर में या यहां तक कि बहस के दौरान भी कि योग्यता परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना में साक्षात्कार के लिए कितने बी प्रतिशत अंक रखे जाते हैं।मेरा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए निर्देश के विपरीत साक्षात्कार के तरीके को लागू करने में कॉलेज की कार्रवाई पूरी तरह से मनमाना, गलत और अवैध है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।संक्षेप में मैं अपने कारणों को इस प्रकार प्रस्तुत करता हूँ:

3 . 2

एस.

(क) सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का एक घटक है और विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए कानूनों, अध्यादेशों और अन्य नियमों और विनियमों से बाध्य है जो इसके संबद्ध और घटक कॉलेजों पर समान रूप से लागू होते हैं।इस संबंध में शिक्षा के मानकों को बनाए रखना विश्वविद्यालय की प्राथमिक चिंता है, यदि विश्वविद्यालय की सलाहकार समिति ने केंद्रीय प्रवेश समिति और कुलपति द्वारा नियम डी को स्वीकार कर लिया है कि सभी संबद्ध और घटक कॉलेजों में प्रवेश योग्यता परीक्षा में प्राप्त एमए के आधार पर किया जाएगा, जो सेंट.

स्टीफंस कॉलेज भी अपने अल्पसंख्यक चरित्र के बावजूद।

(ख) समग्र रूप से छात्र ई. समुदाय के हित में विश्वविद्यालय की प्राथमिक चिंता स्नातक स्तर पर अध्ययन के लिए समान अवसर प्रदान करना है।वर्तमान मामले में साक्षात्कार का तरीका अपराध में परिणत होता है और कला का उल्लंघन करता है।14 क्योंकि इसका स्नातक स्तर पर शिक्षा के अवसर की समानता प्रदान करने के उद्देश्य के साथ कोई उचित संबंध नहीं है।

च

(ग) महाविद्यालय द्वारा अपनाई गई साक्षात्कार की विधि यह नहीं बताती है कि योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुपात में साक्षात्कार के लिए कितने प्रतिशत अंक रखे जाते हैं।महाविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश के आधार को पहले से जानना प्रत्येक छात्र का अधिकार है।

नौकरी।

(घ) यह नहीं दिखाया गया है कि कॉलेज का अल्पसंख्यक चरित्र कैसा है।

' जी.

यदि गैर-ईसाई समुदाय से संबंधित छात्रों को केवल योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जाता है, न कि साक्षात्कार के आधार पर, तो यह प्रभावित या पूर्वाग्रहपूर्ण होगा।यह समझ में आता है कि ईसाई समुदाय के छात्रों को प्राप्त अंकों के संबंध में कुछ छूट दी जाए।

योग्यता परीक्षा या उनके लिए एक उचित विस्तार के लिए कुछ सीटों का आरक्षण करना।

एसटी.स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय (कासलीवाल, जे.) 197 (ई) सार्वजनिक रोजगार के मामले में भी जहां साक्षात्कार ए की विधि का कुछ महत्व हो सकता है, इस न्यायालय ने मामलों की श्रृंखला में निर्धारित किया है कि साक्षात्कार के लिए अंक कुल अंकों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।वर्तमान मामले में हम स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के बारे में चिंतित हैं जिसमें किशोर स्कूल स्तर पर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रवेश लेते हैं।जहाँ तक उनके शैक्षणिक प्रदर्शन का संबंध है, इसे केवल योग्यता परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर आंका जा सकता है।उन्हें किसी भी सार्वजनिक रोजगार के लिए बी नहीं चुना जा रहा है, बल्कि कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए चुना जाना है।यह हमारे देश के प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान का मौलिक कर्तव्य है कि वह शिक्षा के अवसर और भविष्य के लिए उपयुक्तता प्रदान करे

शैक्षणिक प्रदर्शन को योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आंका जा सकता है न कि साक्षात्कार के आधार पर।कॉलेज द्वारा यह नहीं दिखाया गया है कि स्नातक पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में कॉलेज में प्रवेश देने के चरण में दिल्ली विश्वविद्यालय या देश के किसी भी हिस्से से संबद्ध किसी अन्य शैक्षणिक सी संस्थान द्वारा साक्षात्कार का तरीका अपनाया जाता है।(च) महाविद्यालय ने अपने काउंटर में यह रुख अपनाया है कि यह सर्वविदित है कि नकली और जाली प्रमाण पत्रों और अंकपत्रों सहित परीक्षाओं में कदाचार व्यापक रूप से प्रचलित हैं।प्रतिवादी डी कॉलेज द्वारा आयोजित साक्षात्कार एक उम्मीदवार की वास्तविक योग्यता के मूल्यांकन में एक महत्वपूर्ण सुधार प्रदान करता है, जो केवल एक उम्मीदवार की कागजी योग्यता के स्थान पर हो सकता है। उम्मीदवार मौखिक प्रश्नों के साथ-साथ कुछ विषयों में समस्याओं को मौके पर ही लिखित रूप में हल करके अपनी शैक्षणिक क्षमता और क्षमता के बारे में विशेषज्ञों के एक मंडल को व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट करता है।यदि उत्तर में यह भी प्रस्तुत किया गया है कि व्यापक रूप से ई के साथ 25 से अधिक उच्च माध्यमिक परीक्षा निकाय हैं

अंकन और विभिन्न श्रेणीकरण प्रणालियों के अलग-अलग मानक।महाविद्यालय साक्षात्कार के अनुसार विभिन्न परीक्षा/श्रेणीकरण प्रणाली से आने वाले छात्रों की सापेक्ष योग्यता निर्धारित करने के लिए समकक्षता का एक मूल्यवान तरीका प्रदान करता है।एफ की विधि को उचित ठहराने के लिए महाविद्यालय द्वारा उठाए गए उपरोक्त आधार

साक्षात्कार न तो यहाँ है और न ही वहाँ।इसने हमें यह नहीं दिखाया है कि साक्षात्कार विभिन्न उच्च माध्यमिक परीक्षा निकायों द्वारा दिए गए अंकों के संबंध में समानता का एक मूल्यवान तरीका कैसे प्रदान करता है।औचित्य का यह आधार पूरी तरह से अस्पष्ट है और इसका कोई महत्व नहीं है।साक्षात्कार का तरीका परीक्षा में कदाचार या नकली और जाली प्रमाण पत्र प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है।

मार्कशीट।इस संबंध में कॉलेज किसी भी संस्थान में प्रवेश से इनकार करने का हकदार है।

जी.

जिस छात्र के मामले में इस तरह के कदाचार का पता चलता है।(छ) यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि अपने स्वयं के प्रदर्शन के अनुसार कॉलेज के अधिकारी अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाते हैं।

26 उच्च माध्यमिक परीक्षा निकायों द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षा में सम्मानित किया गया।यदि उम्मीदवारों को उस आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, तो यह एच 198 है।

ए इस बात का कारण नहीं है कि साक्षात्कार के समय ऐसे अंकों को सही कैसे नहीं माना जाता है।यह कॉलेज के अधिकारियों द्वारा कहीं भी नहीं कहा गया है कि किस उच्च माध्यमिक परीक्षा निकाय को उनके द्वारा मानक से नीचे माना जाता है।साक्षात्कार की पूरी विधि से यह प्रतीत होता है कि साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों में से जो उपलब्ध सीटों का चार या पांच गुना है, कॉलेज साक्षात्कार के आधार पर उनमें से किसी का भी चयन कर सकता है, चाहे योग्यता परीक्षा में उनके बी अंक प्राप्त हों।इस विधि से 40 सीटों के लिए बुलाए गए 200 उम्मीदवारों में से कॉलेज अधिकारी नंबर 1 पर रखे गए उम्मीदवार को प्रवेश देने से इनकार

कर सकते हैं और नंबर 200 पर रखे गए छात्र को प्रवेश दे सकते हैं और योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता की अनदेखी कर सकते हैं।

(ज) अजय हासिया के मामले (उपरोक्त) में इस अदालत ने मौखिक सी साक्षात्कार परीक्षण को एक संतोषजनक परीक्षण के रूप में मंजूरी नहीं दी है, विशेष रूप से जब यह भेदभाव, हेरफेर और भाई-भतीजावाद के लिए गुंजाइश छोड़ सकता है जो एक साक्षात्कार के आवरण के तहत अज्ञात रह सकता है।इसने इसे एक पूरक परीक्षण के रूप में अनुमति दी है और यह भी कि जहां भी व्यक्तिगत तनाव का परीक्षण आवश्यक माना जाता है।

इस संबंध में न्यायालय ने आगे कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि,

डी.

मौखिक साक्षात्कार परीक्षा में कमियों और कमियों को ध्यान में रखते हुए और देश में प्रचलित स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से जब नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है और भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद बहुत बढ़ रहे हैं, तो लिखित परीक्षा में आवंटित अंकों की तुलना में मौखिक साक्षात्कार के लिए उच्च प्रतिशत अंकों का आवंटन, अदालत द्वारा मनमानेपन से मुक्त के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।इस प्रकार साक्षात्कार की प्रणाली से पीड़ित है

↑

ई.

अंतर्निहित कमजोरी और यदि दिल्ली विश्वविद्यालय अपने विवेक से इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि प्रवेश योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दिया जाना चाहिए, तो विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए ऐसे निर्णय को अवैध या मनमाने होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है।

(i) महाविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है।

च

इस देश का नागरिक।जो नव-धनी या राजनीतिक संरक्षक हैं, उन्हें साक्षात्कार के आधार पर प्रवेश में वरीयता मिलती है।वे छात्र जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं या समाज के कमजोर वर्ग से संबंधित हैं, हालांकि वे शैक्षणिक विशिष्टता में अधिक मेधावी हैं, आम तौर पर साक्षात्कार के तरीके में नुकसान में रहते हैं।लेकिन जिन लोगों के पास किसी भी चीज़ के बजाय अधिक आकर्षक शारीरिक रूप और जी पोशाक है या जो हवादार और चमकदार प्रकार के उम्मीदवार हैं, वे साक्षात्कार में उच्च अंक प्राप्त करते हैं, जबकि खुरदरे बिना कटे हीरे की सराहना नहीं की जा सकती है जैसा कि एम. पी. शर्मा ने कहा है और अजय हासिया के मामले में उद्धृत किया गया है।(जे) सेंट स्टीफन कॉलेज, दिल्ली सोसायटी के ज्ञापन में उल्लिखित सेंट स्टीफन कॉलेज का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों को तैयार करना है।

एच.

एक एसटी।स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय [कासलीवाल, जे.] 199 विश्वविद्यालय की डिग्री और परीक्षाओं के लिए कॉलेज और ईसाई धर्म के सिद्धांतों में निर्देश प्रदान करने के लिए, जो निर्देश उत्तर भारत के चर्च के शिक्षण के अनुसार होना चाहिए।यह उद्देश्य पूरी तरह से साक्षात्कार के बजाय योग्यता परीक्षा में अंकों के आधार पर छात्रों को प्रवेश देकर प्राप्त किया जाता है।

(के) बुलाए गए योग्य उम्मीदवारों में से छात्रों का चयन

साक्षात्कार, सौ प्रतिशत यानी पूरी तरह से साक्षात्कार के आधार पर आधारित है और यह स्पष्ट रूप से अजय हासिया के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लंघन है जिसका इस न्यायालय द्वारा बाद के मामलों में अशोक कुमार यादव और अन्य द्वारा लगातार पालन किया गया है।वी.हरियाणा राज्य और अन्य।, [1985] वॉल्यूम।4 एस. सी. सी. 417, मोहिंदर सैन गर्ग बनाम।पंजाब राज्य और अन्य।, [1991] 1 एस. सी. सी. 562 और मुनिंद्र कुमार और अन्य।

वी.राजीव गोविल और अन्य।, [1991] 3 एस. सी. सी. सी. 368 भी।साक्षात्कार के लिए अधिकतम अंक 15 प्रतिशत हो सकते हैं और उससे अधिक नहीं।

(1) विभिन्न बोर्डों द्वारा योग्यता परीक्षा में दिए गए अलग-अलग अंकों का उपचार सेंट स्टीफंस कॉलेज द्वारा स्वयं की लिखित परीक्षा आयोजित करने में निहित है, न कि साक्षात्कार की विधि द्वारा।अन्यथा भी डी को यह नहीं दिखाया गया है कि साक्षात्कार का सहारा लेकर इस असमानता को कैसे दूर किया जाता है।

(एम) हालांकि साक्षात्कार आयोजित करने में कॉलेज के खिलाफ किसी भी दुर्भावना का कोई आरोप नहीं है, लेकिन यह नहीं भुलाया जा सकता है कि साक्षात्कार की प्रणाली में ही अंतर्निहित कमजोरी और दुर्बलता है जिसमें साक्षात्कार के बजाय व्यक्तिपरक है।

ई.

वस्तुनिष्ठ संतुष्टि एक प्रमुख भूमिका निभाती है।इस पृष्ठभूमि में सेंट स्टीफंस कॉलेज में लंबे समय से प्रचलित साक्षात्कार द्वारा चयन की विधि को इतना पवित्र नहीं माना जा सकता है कि इसे रद्द या बदला नहीं जा सकता है, भले ही इस तरह की विधि को दिल्ली की मंजूरी न मिले।

विश्वविद्यालय।मान लीजिए कि वाइवा वॉस की विधि के पीछे कोई वैधानिक या विधायी मंजूरी नहीं है और न ही उच्च माध्यमिक या 10 + 2 परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कॉलेज में छात्रों को प्रवेश देने के चरण में किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कोई विधि है।यदि सेंट स्टीफन कॉलेज को छोड़कर दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्य सभी संबद्ध और घटक कॉलेज योग्यता परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर छात्रों को प्रवेश दे रहे हैं और विश्वविद्यालय अपने विवेक से साक्षात्कार के तरीके को समाप्त करने और एक समान नियम अपनाने का प्रयास कर रहा है, तो सेंट स्टीफन कॉलेज भी इस तरह के नियम का पालन करने के लिए बाध्य है और लंबे अभ्यास के आधार पर आपत्ति नहीं कर सकता है।

च

जी.

(एन) डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले छात्र आम तौर पर 15 से 17 वर्ष की कम उम्र के होते हैं और ऐसे छात्रों के व्यक्तित्व का अभी भी विकास होना बाकी है और इसलिए डिग्री पाठ्यक्रमों में उनके प्रवेश के लिए केवल एच योग्यता परीक्षा में उनके शैक्षणिक प्रदर्शन पर विचार किया जाना चाहिए।

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

आई 200

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस मामले में विचार के लिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न वैधता है।

क.

ईसाई छात्रों को वरीयता देने वाले कॉलेज प्रवेश कार्यक्रम या दूसरे शब्दों में, क्या सेंट स्टीफन कॉलेज एक अल्पसंख्यक संस्थान होने के नाते, सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने के बावजूद, कला के तहत प्रदत्त अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करते हुए ईसाई समुदाय के छात्रों का चयन करने का कोई अधिकार है।30 (1) या क्या ऐसी वरीयता या आरक्षण अनुच्छेद बी के तहत अमान्य होगा।29 (2) संविधान का?यह एक स्वीकृत तथ्य है कि सेंट स्टीफंस कॉलेज को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वार्षिक घाटे का 95 प्रतिशत अनुदान मिल रहा है।उपरोक्त विवाद पर विचार करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक होगा।उक्त लेख निम्नानुसार हैं:

एस.

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार

कला.29 :- अल्पांशों के हितों की सुरक्षा:

(1) भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिक का कोई भी वर्ग जिसकी अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है।

डी.

स्वयं को उसी को संरक्षित करने का अधिकार होगा।

(2) किसी भी नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा बनाए गए या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।

ई [1]

कला.30 :अल्पांशों की स्थापना और एडी का अधिकार

मंत्री शैक्षिक संस्थानः

(1) सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

च

उनकी पसंद से।

(1 क) स्थापित शैक्षणिक संस्थान की किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए कोई कानून बनाने में और

खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसङ्ख्यक द्वारा प्रशासित राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी विधि द्वारा निर्धारित या उसके अधीन निर्धारित राशि -

जी.

ऐसी संपत्ति का अधिग्रहण ऐसा है जो प्रतिबंधित नहीं करेगा या

उस खंड के तहत गारंटीकृत अधिकार को निरस्त करें।

(2) राज्य, शैक्षणिक संस्थानों को सहायता देने में, किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह अल्पसंख्यक समुदाय के प्रबंधन के अधीन है, चाहे वह निम्न आधारों पर आधारित हो -

एच.

धर्म या भाषा।

टी एस टी।स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय [कासलीवाल, जे.] 201 अल्पसंख्यकों को कला के तहत शैक्षणिक ए संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार प्रदान किया गया है।30 (1) संविधान निरपेक्ष नहीं है और हमेशा उचित विनियमों के अधीन है।यदि किसी अल्पसंख्यक ने राज्य निधि से कोई सहायता प्राप्त किए बिना शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की थी और प्रशासन कर रहा है

फिर कला का खंड (2)।29 खेल में नहीं आएगा।तथापि, यदि ऐसा शैक्षणिक संस्थान राज्य निधि से सहायता प्राप्त कर रहा है तो यह कला के खंड (2) की कठोरता के अधीन होगा।29 और यह केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर प्रवेश से इनकार नहीं कर सकता है।यदि ऐसी संस्था अपने धर्म से संबंधित उम्मीदवारों को वरीयता देती है या आरक्षण देती है, तो यह असमानता और भेदभाव का कारण बनने के लिए बाध्य है।

दूसरे धर्म से संबंधित उम्मीदवार और यह धर्म के आधार पर प्रवेश से इनकार होगा और कला द्वारा प्रभावित होगा।29 (2) .कला के तहत प्रदत्त अधिकार।30 यह सभी अल्पसंख्यकों को दिया गया एक सामान्य अधिकार है, लेकिन अगर ऐसे अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी भी शैक्षणिक संस्थान को भी लाभ मिलता है

एस.

राज्य निधि से अनुदान सहायता के मामले में उसे इस तरह के संस्थान में छात्रों को प्रवेश देने के मामले में अन्य सभी शैक्षणिक संस्थानों के समान होना चाहिए और अपने धर्म के छात्रों के लिए किसी भी स्थान को प्राथमिकता या आरक्षित नहीं करना चाहिए।

डी.

कला का खंड (2)।29 यह कला के समानता खंड का समकक्ष है।15 .

राज्य द्वारा बनाए गए या सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के मामले में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।जबकि कला का खंड (1)।29 नागरिकों के एक वर्ग के अधिकारों की रक्षा करता है जिसकी अपनी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, खंड (2) द्वारा प्रदत्त अधिकार नागरिक को दिया गया एक व्यक्तिगत अधिकार है न कि किसी समुदाय के सदस्य के रूप में।यह खंड (2) सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है, चाहे वे बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हों।यह ध्यान दिया जा सकता है कि कला की तुलना में।15 (1) , ऐसा प्रतीत होता है कि 'लिंग' और 'जन्म स्थान' को कला से हटा दिया गया है।29 (2) .इसलिए, विशेष रूप से पुरुषों या महिलाओं के लिए शैक्षणिक संस्थान को संविधान के उल्लंघन के बिना राज्य द्वारा बनाए रखा जा सकता है।

च

जहाँ तक कला के खंड (1) का संबंध है।30 संबंधित है, यह अल्पसंख्यक समुदाय को अपने समुदाय के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का अधिकार देता है।

इसके द्वारा और अपनी भाषा में संचालित संस्थान।यह दो अधिकार प्रदान करता है (ए) एक संस्था स्थापित करने का अधिकार, (बी) इसे प्रशासित करने का अधिकार।स्थापना के अधिकार का अर्थ है अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा किसी संस्था को अस्तित्व में लाना।जी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई एक परोपकारी व्यक्ति अपने स्वयं के साधनों से संस्था या समुदाय को धन देता है या समुदाय बड़े पैमाने पर धन का योगदान करता है।अधिकार का अगला भाग ऐसी संस्था के प्रशासन से संबंधित है।प्रशासन का अर्थ है संस्थान के मामलों का प्रबंधन।यह प्रबंधन नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए ताकि संस्थापक या उनके नामांकित व्यक्ति संस्थान को अपने विचार के अनुसार और उनके विचारों के अनुसार बना सकें कि सामान्य रूप से समुदाय कैसे एच.

(.

202

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

ए और विशेष रूप से संस्थान को सबसे अच्छी सेवा दी जाएगी।हालाँकि, इसमें एक अपवाद है और यह है कि शिक्षा के मानक प्रबंधन का हिस्सा नहीं हैं।ये मानक राजनीतिक निकाय से संबंधित हैं और देश और उसके लोगों की प्रगति पर विचार करके अपनाए जाते हैं।इसलिए, यदि विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम स्थापित करता है जिसका पालन किया जाना चाहिए, तो विशेष विषयों के अधीन, जिन्हें संस्थान पढ़ाना चाहता है, और कुछ हद तक राज्य शिक्षकों के रोजगार की शर्तों और छात्रों के स्वास्थ्य और स्वच्छता को भी विनियमित कर सकता है।इस तरह के नियम सीधे प्रबंधन पर लागू नहीं होते हैं, हालांकि वे अप्रत्यक्ष रूप से इसे प्रभावित कर सकते हैं।अल्पसंख्यक संस्थानों को उत्कृष्टता के मानकों से नीचे नहीं जाने दिया जा सकता है

शैक्षणिक संस्थानों से, या प्रबंधन के अनन्य अधिकार की आड़ में, सामान्य पैटर्न का पालन करने से इनकार करने की अपेक्षा की जाती है, जबकि प्रबंधन सी उन पर छोड़ दिया जाना चाहिए, वे दूसरों के साथ कदम रखने के लिए मजबूर हो सकते हैं।उपरोक्त प्रस्ताव निम्नलिखित मामलों में निर्धारित किए गए हैं:- बॉम्बे राज्य बनाम।एजुकेशन सोसाइटी, [1955] 1 एस. सी. आर. 568, द स्टेट ऑफ मद्रास बनाम।श्रीमती चंपकम दोराईराजन, [1951], एस. सी. आर. 525, रे में।केरल शिक्षा विधेयक ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 956, सिद्धराजभाई बनाम।गुजरात राज्य, [1963] 3 एस. सी. आर. 837, कटरा एजुकेटन सोसायटी

बनाम।उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य, [1966] 3 एस. सी. आर. 328 और डी. गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद बनाम।रंगनाथ माधोलकर, [1963] पूरक।एससीआर 112।

अब तक, कला का खंड (1)।29 संबंधित है, यह कला के खंड (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार का पूरक है।30. एक अल्पसंख्यक प्रभावी रूप से कर सकते हैं

अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण केवल तभी करें जब उसे

' ई.

अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करें।हालाँकि, कला के तहत अधिकार।30 (1) कला के तहत विचार से स्वतंत्र एक अलग अधिकार है।29 (1) .हमारे समक्ष हाथ में मामलों में शामिल विवाद खंड के बीच है

(2) कला की।29 और कला का खंड (1)।30. संविधान निर्माता लोगों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में पूरी तरह से जानते थे।

च

अल्पसंख्यक लेकिन साथ ही वे चाहते थे कि यदि कोई शैक्षणिक संस्थान राज्य निधि से सहायता प्राप्त करके चलाया जाता है तो किसी भी नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनके किसी भी आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकार।29 (1) या कला।30 (1) कला के खंड (2) के दौरान सक्षम कर रहे हैं।29 यह एक अधिदेश है कि राज्य द्वारा बनाए गए किसी भी शैक्षणिक संस्थान में जी प्रवेश या सहायता प्राप्त करने के मामले में सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और उन्हें केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है।कला के तहत गारंटीकृत अधिकार।29 (2) यह एक विशेष अधिकार है जो अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों को गारंटीकृत सामान्य अधिकार पर प्रबल होगा।30 (1) .यह निर्माण का एक सर्वविदित नियम है कि सामान्य कानून पर विशेष कानून लागू होता है जैसा कि "सामान्य विशेषज्ञता गैर अपमानजनक" उक्ति में एच निहित है।यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि एसटी।

स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय [कासलीवाल, जे.] 203 संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करते समय किसी भी शब्द को आयात या जोड़ा नहीं जा सकता है।यदि महाविद्यालय की ओर से उठाए गए तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है तो इसमें कला में "अपने समुदाय के लिए" शब्दों का आयात अनिवार्य रूप से शामिल होगा।30 (1) .कला का खंड (2)।29 अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित किसी भी शैक्षणिक संस्थान के लिए कोई अपवाद नहीं है और यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि यह राज्य द्वारा बनाए गए या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान पर लागू होता है, चाहे वह अल्पसंख्यक या बी बहुमत द्वारा संचालित हो।अहमदाबाद सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज सोसाइटी और ए. एन. आर.आदि वी। गुजरात राज्य और अन्र।[1975] 1 एस. सी. आर. 173 पी.298 , द्विवेदी, जे. ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" संविधान के भाग III के संदर्भ और योजना पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि संविधान निर्माताओं का इरादा किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए पूर्ण अधिकार प्रदान करने का नहीं था। सहयोगी कला।29 (2) हम कला में अधिकार पर एक प्रतिबंध लगाते हैं।30 (1) .राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने वाला कोई भी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक किसी भी नागरिक को केवल इस आधार पर संस्थान में प्रवेश से इनकार नहीं करेगा कि -

:

धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से कोई भी।किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश पाने का अधिकार निश्चित रूप से इसे प्रशासित करने के अधिकार में शामिल है।इस अधिकार को कला द्वारा आंशिक रूप से कम किया गया है।29 (2) .

प्रवेश के अधिकार को कला द्वारा और कम कर दिया गया है।15 (4) जो कला को एक अपवाद प्रदान करता है।29 (2) .कला.15 (4) राज्य द्वारा बनाए गए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश या राज्य से सहायता प्राप्त करने के मामले में किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रगति के लिए राज्य को कोई विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है।

कला.28 (3) कला में अधिकार पर तीसरा प्रतिबंध लगाता है।30 (1) .यह.

यह प्रावधान है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में भाग लेने वाले या राज्य द्वारा कोई सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति से किसी भी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी जो ऐसी संस्था में दी जा सकती है या किसी भी धार्मिक पूजा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी जो ऐसी संस्था में या उससे जुड़े किसी परिसर में की जा सकती है जब तक कि ऐसा व्यक्ति या, यदि ऐसा व्यक्ति नाबालिग है, तो उसके अभिभावक ने उसके लिए अपनी सहमति नहीं दी है।जाहिर है, कला।28 (3) एक धार्मिक अल्पसंख्यक को एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने से रोकता है।

जी.

शिक्षा जो सहायता प्राप्त करती है या संस्थान में पढ़ने वाले किसी भी नागरिक को धर्म प्राप्त करने के लिए मजबूर करने से राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है-एच

:

204

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उसकी इच्छाओं के विरुद्ध या यदि उसकी इच्छाओं के विरुद्ध छोटा निर्देश

क.

उसका रक्षक।इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि किसी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने का धार्मिक अल्पसंख्यक का अधिकार संस्थान के प्रशासन के अधिकार का हिस्सा है।और फिर भी

कला.28 (3) यह उस अधिकार को कुछ हद तक कम करता है।

संक्षेप में, अनुच्छेद 29 (2), 15 (4) और 28 (3) कुछ अभिव्यक्तियाँ रखते हैं।

कला में अधिकार पर सीमाएँ।30 (1) .कुछ निहितार्थ भी हैं

इस अधिकार की सीमाएँ।अधिकार को उनके अधीन पढ़ा जाना चाहिए

निहित सीमाएँ "।

कला के दायरे से निपटने के दौरान।29 (2) दास, जे. (जैसा कि वे तब थे)

सी. बॉम्बे राज्य बनाम।बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी और ओआरएस।, [1955] 1 एस. सी. आर. 568 को निम्नानुसार देखा गयाः

विद्वान महान्यायवादी तब कला की प्रयोज्यता से बचने के लिए दो विवादों पर वापस आ जाता है।29 (2) .सबसे पहले वह उस कला का विरोध करते हैं।29 (2) कोई मौलिक अधिकार प्रदान नहीं करता है

डी.

सभी नागरिक आम तौर पर छोटे समूहों के नागरिकों के अधिकार की गारंटी देते हुए यह प्रावधान करते हैं कि उन्हें केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा बनाए गए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाना चाहिए या राज्य निधि से सहायता प्राप्त नहीं की जानी चाहिए और वह हमें अनुच्छेद के सीमांत नोट की ओर संदर्भित करता है। यह निश्चित रूप से पहली बार हमारे सामने रखा गया एक नया विवाद है।ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय में विपक्ष में दायर हलफनामों में इसे विशेष रूप से नहीं लिया गया है और अपील के तहत दिए गए फैसले में इस बात का कोई संकेत नहीं है कि इसे उच्च न्यायालय के समक्ष इस रूप में आगे बढ़ाया गया था।न ही इस न्यायालय में अपील करने की अनुमति के लिए याचिका में इस बिंदु को विशेष रूप से अपील का आधार बनाया गया था।इसके अलावा, हमें लगता है कि विवाद योग्यता से रहित है।

कला.29 (1) एक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति रखने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को उनके संरक्षण के अधिकार की गारंटी देकर सुरक्षा प्रदान करता है।कला.30 (1) सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा के आधार पर हों, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है।अब मान लीजिए कि राज्य नागरिकों के एक वर्ग की विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण में मदद करने के लिए एक शैक्षणिक संस्थान रखता है या अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के लिए धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित एक शैक्षणिक संस्थान को अनुदान देता है जो कला के संरक्षण का दावा कर सकता है।29 (2) ऐसी किसी संस्था में प्रवेश के मामले में?निश्चय ही, उसी वर्ग के नागरिक जिनकी भाषा,

ई.

च

जी.

एच एस टी।स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय (कासलीवाल, जे.) 205 लिपि या संस्कृति को संस्था या ए नागरिकों द्वारा संरक्षित करने की मांग की जाती है, जो बहुत ही अल्पसंख्यक समूह से संबंधित हैं, जिन्होंने संस्थान की स्थापना की है और संस्थान का प्रशासन कर रहे हैं, उन्हें अपने खिलाफ किसी भी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है और इसलिए।कला.29 (2) इस धारा या इस अल्पसंख्यक के संरक्षण के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है।न ही हम कला को सीमित करने का कोई कारण देखते हैं।29 (2) अनुच्छेद में निर्दिष्ट वर्ग या अल्पसंख्यकों के अलावा किसी अन्य अल्पसंख्यक समूह से संबंधित नागरिकों के लिए। 29 (1) या बी कला।30 (1) , नागरिकों के लिए, जो किसी भी अल्पसंख्यक समूह से संबंधित नहीं हैं, उन्हें इस सुरक्षा की उतनी ही आवश्यकता हो सकती है जितनी अन्य अल्पसंख्यक समूहों के नागरिकों को।यदि यह आग्रह किया जाता है कि बहुसंख्यक समूहों के नागरिक कला द्वारा पर्याप्त रूप से संरक्षित हैं।15 और कला के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है।29 (2) , फिर उस तर्क के कई स्पष्ट उत्तर हैं।कला की भाषा।29 (2) यह व्यापक और अयोग्य है और सभी नागरिकों को अच्छी तरह से कवर कर सकता है चाहे वे बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समूह से संबंधित हों।कला.15 कला का संरक्षण करते हुए राज्य के खिलाफ सभी नागरिकों की रक्षा करता है।29 (2) यह राज्य या उसके द्वारा प्रदत्त अधिकार से इनकार करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ लागू होता है।इसके अलावा अनुच्छेद 15 सभी नागरिकों को आम तौर पर भेदभाव से बचाता है लेकिन कला। 29 (2) एक विशेष प्रजाति या गलत अर्थात् निर्दिष्ट प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से इनकार के खिलाफ एक संरक्षण है। अगली जगह कला।15 यह अपनी शर्तों में काफी सामान्य और व्यापक है और सभी नागरिकों पर लागू होता है, चाहे वे बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हों, और सभी नागरिकों को कुछ विशिष्ट आधारों पर राज्य द्वारा भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।कला.29 (2) राज्य द्वारा अनुरक्षित या सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए नागरिकों को विशेष अधिकार प्रदान करता है।इस अधिकार को केवल अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित नागरिकों तक सीमित करना होगा

ऐसे नागरिकों के लिए दोहरी सुरक्षा प्रदान करना और यह अभिनिर्धारित करना कि बहुसंख्यक समूह के नागरिकों को किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश पाने के अधिकार की प्रकृति में कोई विशेष शैक्षिक अधिकार नहीं है, जिसके रखरखाव के लिए वे करों के माध्यम से योगदान करते हैं।हम इस तरह के भेदभाव का कोई ठोस कारण नहीं देखते हैं।जिस शीर्षक के तहत अनुच्छेद 29 और 30 को एक साथ समूहीकृत किया गया है-अर्थात्, "सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार" काफी सामान्य है और इस तरह के भेदभाव पर विचार नहीं करता है।यदि यह तथ्य कि संस्थान को राज्य निधि से बनाए रखा जाता है या सहायता प्रदान की जाती है, इस गारंटीकृत अधिकार का आधार जी है, तो सभी नागरिक, चाहे वे बहुसंख्यक हों या अल्पसंख्यक समूह, इस मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए समान रूप से हकदार हैं।इन सब को देखते हुए

केवल सीमांत नोट पर विचार करें, जिस पर महान्यायवादी निर्भर करता है, उसे उस भाषा के स्पष्ट अर्थ को नियंत्रित करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है जिसमें कला है।29 (2) सोफे हो गए हैं।वास्तव में एच 206 में

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मद्रास राज्य बनाम।श्रीमती चंपकम दोराईराजन, यह

क.

न्यायालय पहले ही निम्नलिखित रूप में निर्णय दे चुका हैः

" यह ध्यान दिया जाएगा कि जहां खंड (1) नागरिकों के एक वर्ग की भाषा, लिपि या संस्कृति की रक्षा करता है, वहीं खंड (2) एक व्यक्तिगत नागरिक के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है।में उल्लिखित किसी भी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने का अधिकार

खंड (2) एक ऐसा अधिकार है जो एक व्यक्तिगत नागरिक को एक नागरिक के रूप में प्राप्त है और

किसी समुदाय या नागरिक वर्ग के सदस्य के रूप में नहीं।

हमारे निर्णय में विद्वान महान्यायवादी के तर्क के इस हिस्से को कायम नहीं रखा जा सकता है।

ग

इसकी एक संविधान पीठ।डी. ए. वी. महाविद्यालय आदि में न्यायालय v.की स्थिति

पंजाब और ओआरएस।, [1971] पूरक।एस. सी. आर. 688 पी.695 न्यायालय के लिए जे. जगमोहन रेड्डी के माध्यम से निम्नलिखित टिप्पणी की गईः

" यह देखा जाएगा कि कला।29 (1) कला से व्यापक है।30 (1) , उस में,

डी.

जबकि अल्पसंख्यकों सहित नागरिकों का कोई भी वर्ग, कर सकता है

कला के तहत गारंटीकृत अधिकारों का आह्वान करें।29 (1) कला के तहत गारंटीकृत अधिकार।30 (1) केवल धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध हैं।यह कला के लिए आवश्यक नहीं है।30 (1) कि अल्पसंख्यक धार्मिक अल्पसंख्यक होने के साथ-साथ भाषाई अल्पसंख्यक भी होना चाहिए।यह पर्याप्त है यदि यह एक या दूसरा या दोनों है।इन दो अनुच्छेदों को पढ़ने के लिए हमें इस बात पर सहमति जतानी होगी कि एक धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है ताकि इसके प्रभावी संरक्षण के लिए

ई.

जे.

विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति, जो अपने मानक की उत्कृष्टता को बनाए रखने और सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य की नियामक शक्ति के अधीन है।यह अधिकार आगे कला के खंड (2) के अधीन है।29 जो यह प्रावधान करता है कि किसी भी नागरिक को किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा जो राज्य द्वारा बनाए रखा जाता है या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करता है, केवल धर्म, नस्ल, जाति भाषा या उनमें से किसी के आधार पर।जबकि ऐसा है कि ये दोनों लेख आपस में जुड़े नहीं हैं और न ही यह उनके होने की अनुमति देता है।

च

एक साथ पढ़ें "।

जी.

रे में।केरल शिक्षा विधेयक, 1957 (संदर्भ मामला) [1959] पृष्ठ 1047 पर एस. सी. आर. 995 एस. आर. दास, सी. जे. ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" अनुच्छेद 29 के खंड (1) के तहत भारत के क्षेत्र में या उसके किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों का कोई भी वर्ग

एच एस टी।स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय [कासलीवाल, जे.] 207 भाषा, लिपि या अपनी संस्कृति को ए के संरक्षण का अधिकार है।यह स्पष्ट है कि एक अल्पसंख्यक समुदाय प्रभावी रूप से कर सकता है

शैक्षणिक संस्थानों द्वारा और उनके माध्यम से अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण करना और इसलिए अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के अधिकार के लिए एक आवश्यक संगत है और यही कला द्वारा सभी अल्पसंख्यकों को प्रदान किया जाता है।30 (1) जिसे यहाँ बी पहले पूरी तरह से उद्धृत किया गया है।हालाँकि, यह अधिकार कला के खंड (2) के अधीन है।29 जिसमें यह प्रावधान है कि किसी भी नागरिक को धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा बनाए गए या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।

एस.

इसी मामले में आगे यह अभिनिर्धारित किया गया (पी. 1050-51): "इस तर्क को कला के संदर्भ से मजबूत करने की कोशिश की गई है।29 (2) .यह कहा जाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित एक शैक्षणिक संस्थान जो राज्य के धन से कोई सहायता नहीं मांगता है, उसे डी समुदाय से संबंधित एक भी विद्वान को प्रवेश देने की आवश्यकता नहीं है, इसके अलावा कि जिसके लाभ के लिए यह एक अन्य समुदाय था, जिसके लाभ के लिए यह स्थापित किया गया था और जिसे राज्य से कला प्रदान करने के लिए सहायता मिलती है।29 (2) इसे केवल आधार पर अन्य समुदायों के सदस्यों को प्रवेश से इनकार करने से रोक देगा।

धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी भी और इसके परिणामस्वरूप यह अल्पसंख्यक समुदाय की पसंद का एक शैक्षणिक संस्थान नहीं रहेगा जिसने इसे स्थापित किया था।यह तर्क हमें अनुच्छेद की भाषा द्वारा ही समर्थनीय नहीं लगता है।अनुच्छेद 30 (1) में ऐसी कोई सीमा नहीं है और इस सीमा को स्वीकार करने के लिए आवश्यक रूप से अनुच्छेद में "अपने समुदाय के लिए" शब्दों को जोड़ना शामिल होगा जो सामान्य रूप से और न ही व्याख्या के अच्छी तरह से स्थापित नियमों के अनुसार अनुमेय है।

न ही यह मान लेना उचित है कि यह कला का उद्देश्य है।29 (2) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को राज्य से प्राप्त सहायता से वंचित करना था।यह कहना कि एक संस्थान जो अपने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान होने के कारण सहायता प्राप्त करता है, उसे किसी अन्य समुदाय के किसी भी सदस्य को केवल इसमें उल्लिखित जी आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं करना चाहिए और फिर यह कहना कि जैसे ही ऐसा संस्थान ऐसे बाहरी व्यक्ति को स्वीकार करता है, वह अल्पसंख्यक संस्थान नहीं रहेगा, यह कहने के समान है कि अल्पसंख्यक संस्थान ऐसा नहीं करेंगे।

✓

अल्पसंख्यक संस्थानों के रूप में, किसी भी सहायता के हकदार नहीं होंगे।कला का वास्तविक महत्व।29 (2) और कला।30 (1) हमें ऐसा लगता है कि वे स्पष्ट रूप से

बाहरी लोगों के छिड़काव के साथ एक अल्पसंख्यक संस्थान पर विचार करें एच 208

इसमें प्रवेश लिया।इसमें किसी गैर-सदस्य को शामिल करके अल्पसंख्यक

क.

संस्थान अपने चरित्र को नहीं छोड़ता है और अल्पसंख्यक संस्थान बनना बंद कर देता है।वास्तव में अल्पसंख्यक समुदाय की विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य को विशेष अल्पसंख्यक समुदाय के गैर-सदस्यों के बीच इसका प्रचार करके बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकता है।हमारी राय में, इस शर्त को कला में पढ़ना संभव नहीं है।30 (1) संविधान "।

संविधान निर्माता इन समस्याओं को पूरी तरह से जानते थे -

विभिन्न धर्मों, अलग-अलग भाषाओं और विविध संस्कृतियों वाले विभिन्न समुदाय।हमारे संविधान की पूरी इमारत धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है और जहां तक अल्पसंख्यकों का संबंध है, यह आवश्यक माना गया कि उन्हें अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के संबंध में कुछ अधिकारों की अनुमति दी जानी चाहिए।भारत के क्षेत्र में या उसके किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति रखने का अधिकार दिया गया था।शिक्षा पूरे देश को एकजुट करने के लिए एक मजबूत कारक है और यह आवश्यक माना जाता था कि यदि कोई शिक्षा संस्थान राज्य द्वारा बनाए रखा जाता है या राज्य निधि डी से सहायता प्राप्त करता है तो ऐसे संस्थान में प्रवेश के मामले में प्रत्येक नागरिक को समानता के अधिकार की गारंटी दी जाती थी।यदि धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक राज्य निधि से किसी भी सहायता के बिना कोई शैक्षणिक संस्थान चलाना चाहते हैं, तो ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामले में अल्पसंख्यकों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था और वे अपने समुदाय के छात्रों को प्रवेश देने के लिए स्वतंत्र थे।लेकिन एक मामले में जहां वे राज्य निधि ई से सहायता प्राप्त कर रहे थे, जो पैसा इस देश के प्रत्येक नागरिक से करों के माध्यम से योगदान से आता है, तो अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित ऐसे शैक्षणिक संस्थानों को अन्य सभी शैक्षणिक संस्थानों के अनुरूप होना पड़ता था और वे इनकार करने के हकदार नहीं थे

धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर किसी भी नागरिक को प्रवेश।

च

हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि धार्मिक कट्टरवाद और भाषाई संकीर्णता विघटनकारी प्रवृत्तियों की ओर ले जाती है और समग्र रूप से राष्ट्रीय एकता में बाधा डालती है।यह आवश्यक है कि अल्पसंख्यक शामिल हों और देश की आम धारा का हिस्सा बनें।संविधान निर्माताओं ने इस जी देश के नागरिकों के किसी भी वर्ग की विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का प्रावधान किया और अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार दिया। साथ ही कला में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है।28 कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में पूरी तरह से कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी।

आई.

राज्य निधि से बाहर रखा गया।जबकि राज्य निधि से संस्था के रखरखाव या सहायता प्राप्त करने के मामले में, किसी भी नागरिक को अनुच्छेद 29 के खंड (2) के तहत केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।अल्पसंख्यकों के अधिकारों में कोई बाधा या बाधा नहीं है

> एसटी.स्टीफंस कॉलेज "।दिल्ली विश्वविद्यालय [कासलीवाल, जे.] 209 अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान करने और अतिरिक्त पाठ्यचर्या गतिविधियों के माध्यम से अपनी संस्कृति ए का प्रसार करने और इस प्रकार अपनी संस्कृति का संरक्षण करने के लिए।

1

कला का खंड (2)।29 इस तरह के किसी भी अधिकार को नहीं छीनता है और न ही अल्पसंख्यकों पर उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों को चलाने में कोई प्रतिबंध लगाता है।यह.

1

इसके बजाय अल्पसंख्यकों के हित में होगा कि वे अन्य के छात्रों को प्रवेश दें

समुदाय और सामुदायिकता की एक विस्तृत श्रृंखला में अपनी संस्कृति का प्रसार करना।उदाहरण के लिए, यदि ईसाई एक शैक्षणिक संस्थान चला रहे हैं, तो वे शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी रखने के लिए स्वतंत्र हैं।वे ईसाई धर्म के उच्च आदर्शों और मूल्यों को भी सिखा सकते हैं।एकमात्र प्रतिबंध वह है जो अनुच्छेद 28 (3) में निहित है जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान पर लागू होता है, चाहे वह अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक संस्थान हो। कला के तहत प्रतिबंध।28 (3) यह है कि ऐसे शैक्षणिक संस्थान में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी जो ऐसी संस्था में दी जा सकती है या किसी भी धार्मिक पूजा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी जो उसके बिना ऐसी संस्था में आयोजित की जा सकती है।

सहमति और यदि ऐसा व्यक्ति अपने अभिभावक की सहमति के बिना नाबालिग है।हमारे संविधान का उद्देश्य विविधता में एकता है। यह विविधताओं को आत्मसात करके एकता को समृद्ध करने के लिए है, यह विभाजक को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं है।

प्रवृत्तियाँ।कला द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार।30 (1) इसलिए, इसे इस तरह से नहीं बढ़ाया जाना चाहिए कि अन्य मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण किया जाए या समाप्त किया जाए।

संस्थापक पिताओं के इरादों के विपरीत।इन अनुच्छेदों पर विचार करते समय संविधान सभा की बहसों पर विचार करना उपयोगी होगा।4 एलई

संविधान के अनुच्छेद 29 और 30:

ये एक ओर अनुच्छेद 23 (1) और दूसरी ओर 23 (3) (ए) और 23 (3) (बी) थे।

दूसरी ओर संविधान के मसौदे में।सबसे पहले, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने संविधान के वर्तमान अनुच्छेद 28 के अनुरूप अनुच्छेद 23 (2) के मसौदे के संबंध में कहा कि अनुच्छेद 30 और 29 के संबंध में भी राज्य धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों को सहायता देने या न देने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है।उन्होंने कहाः

" अब, दूसरे खंड के संबंध में मुझे लगता है कि इसे पर्याप्त रूप से अच्छी तरह से समझा नहीं गया है।हमने एक ऐसे समुदाय के दावे को समेटने की कोशिश की है जिसने शिक्षा या सांस्कृतिक मामलों में अपने बच्चों की उन्नति के लिए शैक्षणिक संस्थान शुरू किए हैं, ताकि ऐसे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने की अनुमति दी जा सके; इस तथ्य के बावजूद कि उसे राज्य से कुछ सहायता मिलती है।राज्य, निश्चित रूप से, सहायता देने के लिए स्वतंत्र है, सहायता नहीं देने के लिए स्वतंत्र है; हमने केवल एक सीमा रखी है, कि राज्य संस्था को अपने अनुदान-सहायता संहिता के तहत सहायता का दावा करने से नहीं रोकेगा।

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

जी 210

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस आधार पर कि यह एक समुदाय द्वारा चलाया और बनाए रखा जाता है और नहीं

क.

एक सार्वजनिक निकाय द्वारा अनुरक्षित।हमने वहाँ एक और योग्यता भी प्रदान की है, कि यद्यपि संस्थान में धार्मिक शिक्षा देना स्वतंत्र है और राज्य द्वारा दिया गया अनुदान ऐसी संस्था को देने में बाधा नहीं होगा, लेकिन यह अन्य समुदायों के बच्चों को तब तक निर्देश नहीं देगा या उन्हें अनिवार्य रूप से नहीं बनाएगा जब तक कि वे माता-पिता की सहमति प्राप्त न कर लें।

इन बच्चों में से।यह, मुझे लगता है, एक हितकारी प्रावधान है।यह प्रदर्शन करता है।

दो कार्यः

श्री एच. वी. कामत-स्पष्टीकरण के एक बिंदु पर क्या?

किसी समुदाय या अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित संस्थान और विद्यालय

एस.

अपने स्वयं के छात्र-एक ऐसा विद्यालय नहीं जहाँ सभी समुदाय मिश्रित हैं, बल्कि एक ऐसा विद्यालय है जो समुदाय द्वारा अपने छात्रों के लिए चलाया जाता है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकरःअगर मेरे दोस्त, श्री कामत दूसरे लेख को पढ़ेंगे तो वे देखेंगे कि एक बार एक संस्थाःचाहे समुदाय द्वारा बनाए रखा जाए या नहीं, अनुदान मिलता है, शर्त है

डी.

कि यह विद्यालय को सभी समुदायों के लिए खुला रखेगा।वह प्रावधान उन्होंने नहीं पढ़ा है "।

(VII सी. ए. डी. 884)

उन्होंने राज्य की सहायता देने या न देने की स्वतंत्रता की पुष्टि की।

ई.

ये स्कूल जब सीधे अनुच्छेद 23 के मसौदे का उल्लेख करते हैं जो वर्तमान अनुच्छेद 29 और 30 का अग्रदूत है:मुझे लगता है कि अनुच्छेद 23 को पढ़ने में एक और बात जो उठानी चाहिए वह यह है कि यह राज्य पर कोई दायित्व या बोझ नहीं डालता है। यह नहीं कहता कि, उदाहरण के लिए जब मद्रास के लोग आते हैं

च

बम्बई, बम्बई सरकार को कानून द्वारा तमिल "भाषा या आंध्र भाषा या किसी अन्य भाषा" में शिक्षा देने की किसी भी परियोजना के लिए वित्तपोषण करने की आवश्यकता होगी।राज्य पर कोई बोझ नहीं है।अनुच्छेद 23 द्वारा लगाई गई एकमात्र सीमा यह है कि यदि कोई सांस्कृतिक अल्पसंख्यक है जो अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को संरक्षित करना चाहता है, तो राज्य कानून द्वारा ऐसा नहीं करेगा।

जी.

उस पर कोई अन्य संस्कृति थोपी जाए जो या तो स्थानीय हो या

अन्यथा "।

(VII सीएडी। 923)

अल।

दूसरा, अनुच्छेद 23 के मसौदे का वास्तविक उद्देश्य अब

एच एस टी।स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय [कासलीवाल, जे.] 211 अनुच्छेद 29 और 30 को श्री के. संथानम द्वारा लाया गया था, जिन्हें संविधान सभा के सर्वश्रेष्ठ जानकार और विद्वान सदस्यों में से एक माना जाता है, उन्होंने कहा:

" महोदय, आपको याद होगा कि पूरे यूरोप में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, अल्पसंख्यक जो कुछ भी चाहते थे, वह था अपने स्वयं के स्कूल रखने और अपनी संस्कृतियों के संरक्षण का अधिकार, जिसे फासीवादी बी और नाजियों ने अस्वीकार कर दिया था।वास्तव में, वे राज्य सहायता या राज्य सहायता नहीं चाहते थे।वे बस चाहते थे कि उन्हें अनुमति दी जाए

!

अपने रीति-रिवाजों का पालन करना और अपनी संस्कृतियों का पालन करना और अपने स्वयं के स्कूलों की स्थापना और संचालन करना।इसलिए, मुझे नहीं लगता कि किसी भी अल्पसंख्यक की ओर से कला में दिए गए अधिकारों का अवमूल्यन करना सही है।23 (1) ..... इस संबंध में हमें दो अलग-अलग रुझानों के बीच भी सी संतुलन बनाए रखना होगा।सबसे पहले हमें एक बड़े भाषाई अल्पसंख्यकों को विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर उनकी अपनी भाषा में शिक्षित होने का अधिकार देना होगा।साथ ही हमें अनुकरण की ऐतिहासिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि आने वाले सैकड़ों और हजारों वर्षों तक ये भाषाई अल्पसंख्यक खुद को वैसे ही कायम रखेंगे जैसे वे हैं।ऐतिहासिक प्रक्रिया को स्वतंत्र रूप से खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए।इन अल्पसंख्यकों को इलाके के लोगों के साथ आत्मसात करने में मदद की जानी चाहिए।उन्हें धीरे-धीरे इलाके की भाषा को आत्मसात करना चाहिए और वहां के लोगों के साथ मिल जाना चाहिए, अन्यथा वे उन प्रांतों में विदेशी हो जाएंगे।इसलिए, हमारे पास ऐसे कठोर प्रावधान नहीं होने चाहिए जिनके द्वारा प्रत्येक बच्चा अपनी मातृभाषा में स्वचालित रूप से संरक्षित हो।दूसरी ओर, यह प्रक्रिया अचानक नहीं होनी चाहिए, इसे मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।जहाँ भी बड़ी संख्या में बच्चे हैं, वहाँ उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए-प्राथमिक शिक्षा।

एफ.

मातृभाषा।साथ ही, उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और एफ

प्रांतों के सामान्य विद्यालयों में जाने और स्थानीय भाषा को आत्मसात करने और लोगों के साथ आत्मसात होने में सहायता की। मुझे लगता है कि यह खंड इन आकस्मिकताओं के लिए सबसे व्यावहारिक तरीके से प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 30 (1) के तहत अल्पसंख्यक जी को गारंटीकृत अधिकार और अनुच्छेद 29 (2) के तहत इस तरह के अधिकार पर लगाए गए प्रतिबंध के सवाल पर विचार करते समय यह नहीं कहा जा सकता है कि हम कुंवारी धरती पर हैं क्योंकि हमारे पास पहले के कई संविधान निर्णयों में पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान किया गया है।वे श्रीमती हैं।चम्पकम

दोराईराजन का मामला, स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम।बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी, केरल शिक्षा विधेयक, 1957 संदर्भ मामला, डी. ए. वी. कॉलेज बनाम।पंजाब और अन्य राज्य और अहमदाबाद सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज सोसाइटी।मैं पहले ही प्रासंगिक एच को उद्धृत कर चुका हूँ।

ए 212

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

कला के दायरे में इन मामलों के अंश।29 (2) और कला।30 (1) .संविधान के भाग (III) की पूरी योजना का एक पहलू स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि संविधान निर्माताओं का इरादा किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए पूर्ण अधिकार प्रदान करने का नहीं था।प्रवेश के अधिकार को कला द्वारा सीमित किया गया है।15 (4) जो राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षिक प्रगति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है।

बी राज्य से सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामले में नागरिकों के पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए।कला.28 (3) अन्य प्रतिबंध लगाता है जिसके अनुसार राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या कोई सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या ऐसे संस्थान में दी जाने वाली या आयोजित किसी भी धार्मिक पूजा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसे व्यक्ति की सी सहमति के बिना या यदि ऐसा व्यक्ति अपने अभिभावक की सहमति के बिना नाबालिग है।इस प्रकार, भले ही एक अल्पसंख्यक ने एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की हो, लेकिन यदि इसे सहायता मिलती है या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो यह कला के जनादेश से बाध्य है।28 (3) .तीसरा प्रतिबंध कला द्वारा लगाया गया है।29 (2) जिसके अनुसार यदि सुश अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को राज्य निधि से सहायता मिलती है तो वह केवल धर्म, नस्ल, डी जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर किसी भी नागरिक को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकता है।इस प्रकार अनुच्छेद 15 (4), 28 (3) और 29 (2) स्थान लेते हैं।

कला में अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकार पर सीमाएँ व्यक्त करें।30 (1) .सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत के लिए दिशर पेश करने के लिए पहले अदालत की आवश्यकता नहीं होती है

एकर बाद सामंजस्यपूर्ण निर्माण द्वारा एकर समाधान करबाक लेल निर्माण द्वारा मुद्रा।व्याख्या का सुनहरा नियम यह है कि शब्दों को सामान्य, प्राकृतिक और व्याकरणिक अर्थ और सामंजस्य के सिद्धांत में पढ़ा जाना चाहिए।

ई.

निर्माण केवल इस नियम को लागू करता है कि जहां किसी विषय से संबंधित कानून का एक सामान्य प्रावधान है, और उसी विषय से संबंधित एक विशेष प्रावधान है, विशेष सामान्य पर हावी है।यदि इसका निर्माण इस तरह से नहीं किया जाता है तो इसका परिणाम यह होगा कि विशेष प्रावधान पूरी तरह से विफल हो जाएगा।हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने वारब्रुटन बनाम में अवलोकन किया। लवलैंड, (1832) [2 डी. और सी. एल.400] निम्नानुसारः

च

✓

" निर्माण के किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं हो सकती है कि जब एक के शब्द

- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

कानून का हिस्सा एक स्पष्ट अर्थ व्यक्त करता है

यह होगा।

कानून के एक अन्य भाग को पेश करना आवश्यक है जो कम स्पष्टता के साथ बोलता है और जिसके शब्द इस तरह के निर्माण में सक्षम हो सकते हैं ताकि कानून की प्रभावशीलता को कम किया जा सके।

जी.

पहला भाग "।

1

इस प्रकार कला की स्पष्ट भाषा के सामने मेरे विनम्र दृष्टिकोण में।29 (2) , वहाँ

महाविद्यालय की ओर से रखे जाने वाले विवाद को स्वीकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

ए. एन. रे, सीजे., अहमदाबाद सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज सोसाइटी मामले में एसटी रखा गया।

एच.

स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय (कासलीवाल, जे.) ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक ए संस्थानों के प्रशासन के अधिकार के संदर्भ में कहा कि सर्वोत्तम प्रशासन का कोई निशान या रंग प्रकट नहीं होगा।

अल्पसंख्यक।एक अल्पसंख्यक संस्थान को संस्थान के प्रशासन में अनुकरणीय उदारता के साथ चमकना चाहिए।अल्पसंख्यक संस्थान को सबसे अच्छी प्रशंसा यह दी जा सकती है कि वह अपने अल्पसंख्यक चरित्र पर निर्भर या घोषित नहीं करता है। एस.के. संथानम उनके उच्च ध्वनि वाले ज्ञान के शब्द हैं जो उन्होंने कहा था

संविधान सभा ने कहा कि सबसे पहले हमें एक बड़े भाषाई बी> अल्पसंख्यकों को शिक्षित होने का अधिकार देना होगा-विशेष रूप से प्राथमिक चरण में उनकी अपनी भाषा में।साथ ही हमें आत्मसात करने की ऐतिहासिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि आने वाले सैकड़ों और हजारों वर्षों तक ये भाषाई अल्पसंख्यक खुद को वैसे ही कायम रखेंगे जैसे वे हैं।ऐतिहासिक प्रक्रिया को स्वतंत्र रूप से खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए।ये अल्पसंख्यक

इलाकाई लोगों के साथ घुलने-मिलने में मदद की जानी चाहिए।उन्हें सी को धीरे-धीरे इलाके की भाषा को आत्मसात करना चाहिए और वहां के लोगों के साथ विलय करना चाहिए, अन्यथा वे उन प्रांतों में विदेशी होंगे, जैसे कि वे थे।यदि हम सेंट स्टीफन कॉलेज के मामले पर विचार करें, जो शुरू में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में ईसाई समुदाय के हितों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था, तो अब पूरी तरह से आत्मसात हो गया है और इसके साथ विलय हो गया है।

इलाके के लोग और ऐसी प्रक्रिया को रोकने के लिए कोई आधार या औचित्य डी दिखाई नहीं देता है।कॉलेज द्वारा लिए गए रुख के अनुसार हर साल गैर-ईसाई समुदाय के 90 प्रतिशत से अधिक छात्रों को कॉलेज में प्रवेश दिया जाता है और यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कॉलेज पहले ही एकीकरण की प्रक्रिया को हासिल कर चुका है।इस मामले के किसी भी दृष्टिकोण से यदि कॉलेज राज्य निधि से सहायता प्राप्त कर रहा है तो उसे कला की कठोरता का पालन करना होगा।29 (2) मामले में ई

महाविद्यालय में छात्रों का प्रवेश।

}

एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो विचार के लिए उत्पन्न होता है वह यह है कि यदि

सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को अपने समुदाय के छात्रों को प्रवेश देने का हकदार माना जाता है तो कितना प्रतिशत उचित माना जा सकता है।एक बार जब हम यह मान लेते हैं कि अल्पसंख्यक एफ के छात्रों को प्रवेश देने का हकदार है

अपनी पसंद के अनुसार, परिणाम यह होगा कि वे अपने समुदाय के छात्रों को शत-प्रतिशत प्रवेश देने और कला के प्रतिबंध के हकदार होंगे।29 (2) पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा।कॉलेज की ओर से उपस्थित विद्वान वकील यह बताने में असमर्थ थे कि कितना प्रतिशत उचित होगा।यहां तक कि मामलों के तथ्यों को हमारे सामने रखते हुए सेंट स्टीफंस कॉलेज ईसाई छात्रों को 10

प्रतिशत वरीयता देने का दावा कर रहा है, जबकि इलाहाबाद कृषि संस्थान अपनी विवरणिका में दिए गए जी के रूप में 50 प्रतिशत के लिए औचित्य चाहता है।जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि सेंट स्टीफन कॉलेज और इलाहाबाद कृषि संस्थान ईसाई समुदाय के छात्रों के पक्ष में किसी भी तरजीही अधिकार या आरक्षण का दावा करने के हकदार नहीं हैं क्योंकि उन्हें सहायता अनुदान मिल रहा है और इसलिए मैं यह तय करने के सवाल पर और अधिक श्रम करना आवश्यक नहीं समझता कि कितना प्रतिशत उचित माना जा सकता है।

1

एच 214

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नागरिक आवेदन संख्या।1786 1989 का & 1830-41 1989 द्वारा दर्ज किया गया

क.

इलाहाबाद कृषि संस्थानःयह संस्थान इंटर जैसे अध्ययन के कई पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करता है।

कृषि, अंतर गृह विज्ञान, भारतीय डेयरी डिप्लोमा (आई. डी. डी.), कृषि संस्कृति में बी. एससी., बी. एससी. गृह अर्थशास्त्र, एम. टेक।कृषि इंजीनियरिंग में।यह बी संस्थान ईसाई समुदाय से संबंधित छात्रों को अपनी मुहरों का 50 प्रतिशत तक आरक्षण प्रदान करता है।मुझे नहीं लगता कि देना जरूरी है।

{ ईसाई समुदाय से संबंधित 50 प्रतिशत छात्रों का विवरण और विभाजन जैसा कि शेट्टी, जे. के निर्णय में पहले ही विवरण आ चुका है।

सिविल अपील सं।2829 1989 का

ग

अपीलार्थी शशिपाल सिंह और तेजपाल सिंह ने सिविल अपील नं.

2829 1989 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों द्वारा वर्ष 1988 में कृषि संस्थान में प्रवेश दिया गया था।मामले के अंतिम निर्णय के बाद संस्थान द्वारा दिनांक 3.4.1989 के आदेश द्वारा उनका प्रवेश रद्द कर दिया गया था।अपीलार्थियों को तब डी B.Tech में अपनी पढ़ाई पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई थी।इस अदालत के दिनांक 11.5.1989 के एक आदेश द्वारा कृषि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम।इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 1980 की उपरोक्त अपील संख्या 2829 की भी अनुमति है।

जिन छात्रों को इस संस्थान द्वारा प्रवेश नहीं दिया गया था, उन्होंने चर्च ई प्रायोजित ईसाई छात्रों के लिए आरक्षण को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर कीं।उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को यह स्पष्ट करते हुए स्वीकार कर लिया कि ईसाइयों के लिए आरक्षण की नीति अनुच्छेद के तहत गारंटीकृत अधिकार के विपरीत थी।29 (2) संविधान से। इलाहाबाद कृषि संस्थान ने संविधान के अनुच्छेद 133 (1) के तहत प्रमाण पत्र प्रदान करके दीवानी अपील संख्या दायर की है। 1830-41 इस न्यायालय के समक्ष 1989 की सिविल अपील सं. 1786।इन मामलों में उत्पन्न होने वाला विवाद भी वैसा ही है जैसा

}

च

सेंट स्टीफन कॉलेज का मामला और वही तर्क इन अपीलों पर लागू होता है।मेरे विचार में उच्च न्यायालय ने मामले का सही फैसला किया और उच्च न्यायालय के फैसले में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।इसके परिणामस्वरूप मुझे सेंट स्टीफंस कॉलेज के साथ-साथ इलाहाबाद कृषि संस्थान द्वारा दायर अपीलों में कोई बल नहीं मिला।सेंट स्टीफंस कॉलेज द्वारा दायर 1980 का डब्ल्यू. पी. सं. 1868,1989 का सिविल जी अपील सं. 1786 और सिविल अपील सं.1830-41 द्वारा दायर 1989 का

इलाहाबाद कृषि संस्थान को बर्खास्त कर दिया गया है और डब्ल्यू. पी. सं.13213-14 दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ द्वारा दायर 1984 का टी. सी. नंबर 3 विश्वविद्यालय के छात्रों में से एक राहुल कपूर द्वारा दायर किया गया और विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों द्वारा दायर 1989 की सिविल अपील नंबर 2829 की अनुमति है।

} एच हालांकि, वे छात्र जिन्हें पहले ही एसटी में प्रवेश दिया जा चुका था।

स्टीफंस कॉलेज वी।दिल्ली विश्वविद्यालय [कासलीवाल, जे.] 215 इस न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश को उनके पाठ्यक्रमों को पूरा करने की अनुमति दी जाएगी और सेंट स्टीफन कॉलेज और इलाहाबाद कृषि संस्थान द्वारा अब तक किए गए किसी भी प्रवेश में बाधा नहीं डाली जाएगी।

आदेश

6 दिसंबर, 1991 के अपने बहुमत निर्णय में हमारे द्वारा बताए गए कारणों के लिए, सेंट स्टीफन कॉलेज द्वारा दायर 1980 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 1868 की अनुमति है।डब्ल्यू. पी. सं.13213-14 1984 का 1980 का टी. सी. सं. 3 खारिज कर दिया गया है।इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपीलों को उच्च न्यायालय के फैसले को बहुमत के फैसले में इंगित सीमा तक संशोधित करने की अनुमति है।हालांकि, इलाहाबाद कृषि संस्थान द्वारा अब तक किए गए प्रवेश में कोई बाधा नहीं आएगी।जिन छात्रों को उच्च न्यायालय के इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सी में प्रवेश दिया गया है, उन्हें अपना पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जाएगी।

मामले की परिस्थितियों में, हम लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देते हैं।डब्ल्यूपी सं. 1868/80 की अनुमति है।डी.

वी. पी. आर

डब्ल्यू. पी. सं. 13213-14/84 और टी. सी. सं. 3/80 खारिज कर दिया गया है।

: